

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 मार्च, 1984

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 28 मार्च, 1984

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)1
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— चौधरी देवी लाल द्वारा	(13)17
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(13)18
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(13)23
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—मुख्य मंत्री द्वारा	(13)23
विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(13)27

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 28 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, सैक्टर-1, चंडीगढ़ में दोपहर बाद 9.30 बजे हुई। (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मँबर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Construction of Drain in Killoi Constituency

***640. Shri. Hari Chand Hooda:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any drains were constructed in Killoi constituency during the year 1979-80; if so, the number thereof; and

(b) whether any drains have also been constructed in the said constituency during the year from 1981 to 1984 (upto-date); if so, the number thereof?

Irrigation & Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala):

(a) Yes 6 NO. Link drains were constructed.

(b) Yes. 5 NO. Link drains were constructed.

श्री हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब: स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जो लिखा हुआ जवाब दिया है क्या वह इस पर पाबन्द रहेगी? पिछली बार भी मैंने यही सवाल किया था और उसका भी जवाब मुझे यही मिला था कि किलोई कांस्टीच्यूसी में 13 स्कीमें बनी थी और उनमें 11 स्कीमें 1981 से पहले बन चुकी हैं है जो दो बाकी है। वह सरकार बना देगी है अब जो मेरे पास जवाब आया है वह यह है। कि बाकी भी बना दी जायेगी। ओर डाईव न कर दिया जायेगा। मैं यह आ वासन चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पर पाबन्द रहेगी?

चौधरी भाम र सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, ये खुद ही सवाल कर रहे है। और खुद ही जवाब दे रहे है। जो हमारा जवाब था वह इन्होने पढ़ ही लिया है।

चौधरी ओम प्रका T: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महादेय ने सवाल के पार्ट (बी) के जवाब मैं बताया है कि 1981 से 1984 के दौरान 5 लिंक डेन्ज बनाई गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये किस साल में बनाई गई थी ओर पिछले साल के फ्लड को मद्देनजर रखते हुए ओर कितनी लिंक डेन्ज सैकसन हो जायेगी?

चौधरी भाम र सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, धामड लिंक डेन 1982 में बनी नांदल पम्प हाउस 1982 में लाढोट 1980 में चिडी 1981 में ओर भालोट 1981 में बनी।

चौधरी ओम प्रकाश : स्पीकर साहब, मैंने यह भी पूछा था कि नई लिंक ड्रेन कितनी सैक्सन हुई हैं और वह कब तक कम्प्लीट हो जायेगी।

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, लिंक ड्रेन्ज तो बहुत सी सैक्सन की गई है। अगर दो चार या दस ड्रेन्ज के बारे में पूछते तो मैं बता देता। इनके एरिया के नजदीक जो ड्रेन्ज है उनके बारे में बता सकता हूँ। के०सी० वी० आर० ड्रेन के हैड रीच में जमीन एक्वायर नहीं हो सकी। क्योंकि लोगों ने कोर्ट से स्टे लिया था। अब वहां जमीन एक्वायर करने के लिए सैक्सन 4 और 6 के तहत नोटिफिकेशन हो चुके हैं। वहां पर जमीन लेकर जल्दी काम शुरू करने की योजना है। दिल्ली पोरान में तो डैड लाईन आलरेडी काम कर रही है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम दिल्ली वालों से बातचीत शुरू कर रहे हैं। डेन नम्बर 8 से रोहतक के लिये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं अब हम इस डेन की कैपेसिटी 900 क्यूसिकंस से बढ़ा कर 1600 क्यूसिकंस कर रहे हैं इसकी डैड लाईन काम कर रही है।

श्रीमती चन्द्रवती: क्या मंत्री महोदय ने कभी यह इस्पैक्सन करवाई है या नाप करवाया है कि जो ये ड्रेने खोदी जा रही है। उनकी चोडाई और गहराई स्पैसिफिकेशन के मुताबिक है यानी ठीक से खोदी जा रही है या नहीं?

चौधरी भाम ेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने फीता रख कर तो कभी मपवाई नहीं हैं ओर न ही कभी ऐसी जरूरत पडी है। लीडर आफ दी अपोजी इन अगर किसी ड्रेन के बारे में बताएगी कि वह 6 फुट की जगह 3 फुट खोदी गई हैं तो मैं उसका पता करवा लूंगा।

श्री हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने कहा हक ड्रेन नं0 8 की कैपेसिटी 900 से 1600 क्यूबिक करने जा रहे है। क्या इस कैपेसिटी को ओर जमीन एक्वायर करके बढ़ाया जा रहा हैं या नहीं उसी ड्रेन को ओर डीप करेगे। दूसरे के.सी.आ. कड्रेन सिर्फ डीघल गांव का मसला हैं इससे आगे ड्रेन खुदी हैं सिर्फ इसको उसके साथ लिंक करना हैं अगर डीघल गांव की जमीन ले ली जाए तो वहां का सारा पानी निकल सकता हैं क्या ऐसी कोई परपोजल है।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ड्रेन नं0 8 के लिए ओर जमीन एक्वायर करने की योजना नहीं है। जो जमीन आल रेडी हैं उसी को डीप करेगे। उसके दोनो तरफ फारैस्ट के दरखत हैं जो कटवाए जा रहे है। ताकि ड्रेन पूरी तरह से फंक्शन कर सकें। जहां तक दूसरी ड्रेन का ताल्लुक है। उसके लिए 10 किलोमीटर का एरिया लोगों ने एक्वायर नहीं करने दिया। उन्होंने कोर्ट से स्टे ले ली है। अब हम जमीन लेकर इस काम को कम्प्लीट कर देंगे। कौथा, माइना ओर िमली इन तीनों गांवों में पानी की पाकेट है। ड्रेन बनने के बाद यह पानी लिया जा

सकता हैं इन्होंने जो अपना सवाल पूछना था वह छोड़ गया। इनके गांव की जो ड्रेन खडवाली है इसके लिए जमीन लेनी थी लेकिन लोगों ने स्टे ली। स्टे वेकेट होने के बाद जमीन एक्वायर करेगे। इसकी लैथ चार किलोमीटर है इस पर 9.13 लाख रूपय खर्च होंगे। ओर चार हजार एकड़ जमीन को फायदा पहुंचेगा। इसके पेपर एल. ए. ओ. के नरा पास सबमिट कर दिए हैं अगले फलड सीजन से पहले इसको कम्पलीट कर देंगे। इसी तरह से किलोई ड्रेन सात मील लम्बी होगी ओर उस पर 11.72 लाख रूपये खर्च होंगे तथा 7600 एकड़ जमीन को फायदा पहुंचायेगी। इसके लिए सैक इन 4 का नोटिफिके इन हो चुका हैं अब आबजैक इन सुनने है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, ड्रेन नं0 8 का रोहतक के साथ बडा कंसर्न है। फलड के दिनों मे मुख्य मंत्री जी ओर सुरजेवाला जी रोहतक गए थे। इन्होंने देखा होगा कि उस ड्रेन में हरा घास आ जाता हैं ओर सिलटिंग हो जाती है। मै जानना चाहता हूं कि क्या अगले सीजन से पहले इसको डि-सिलटिंग करके मजबूत किया जायेगा?

चौधरी भाम रेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, अब तो इस ड्रेन को ओर डीपन तथा वाइडन कर रहे है। सिलट रहने का तो सवाल ही नहीं हैं जहां तक हरे घास का ताल्लुक है इस पर दो पुराने ब्रिज बने हुए हैं जो हिसार ओर जीन्द वाली सड़क के रास्ते में हैं वहां पर आकर घास अटक जाता हैं ब्रिज तो पी0

डबल्यू0 डी0 वाले बनायेगें। लेकिन ये अगले सीजन से पहले नहीं बन सकते। इसलिए हम ऐसे वक्त में टैम्पोरेरी इन्तजाम कर लेते हैं घास को हम लगातार निकालते रहते हैं बाकी डि-सिलटिंग वगैरह खुदाई के बाद नहीं रहेगी।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, किलोई कांस्टीच्युएन्सी में एक छपरा ड्रेन हैं जो किलोई कांस्टीच्युएन्सी को डूबोती हैं ओर यह मेरे हलके से भी गुजरती हैं मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस साल उसका भी इलाज करेगे।

चाधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ईसापुर खेडी ड्रेन को डाइवर्ट करने की परपोजल है इसका पानी डाइव र्नि ड्रेन में डालेगें ताकि रोहतक ओर इस एरिया का नुकसान न हो। इस पर तकरीबन 90-95 लाख रूपया खर्च होगा। यह स्कीम इस साल तो पुरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी लेकिन पार्टली हो जाएगी।

चौधरी धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, पिछले साल जब फलड आया था उस समय ड्रेन नम्बर 8 में स्कुल की 6 लड़कियां डूब गई थी। उस ड्रेन पर दादरी ओर मैनपुरा की बीच एक पुल बनाया हुआ है जोकि सबमि र्णियल पुल है जब भी फलड का पानी इस ड्रेन में आता है यह सारा पानी उस पुल के ऊपर से गुजरता है। जिस समय लड़कियां स्कुल में जाने के पुल से गुजरने लगी तो वे पानी में बह गईं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना

चाहता हूँ कि उस पुल को उठा कर ऊँचा करने का विचार है या नया पुल बनाया जाएगा?

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मैं उस गांव में गया था जहाँ की लडकियाँ पानी में बह गई थी वह सबमिग्रियल पुल है उसके परामिट गिर गये थे। इसके अलावा महकमे वालो का यह कहना था कि उस पुल पर जा पाईप लगाए हुए थे वे सारे पाईप गांव वाले उतार कर लेगये। मैंने उस समय यह कहा था कि जो पैरार्पट लगाए जाएं वे बहुत ऊँचे लगा दिए जाएं ताकि कितना ही फलड आ जाये ये पैरार्पट नजर नहीं आने चाहिए। ताकि यह पता चले कियहाँ पर पुल है। इसके अलावा पुल के दोनो तरफ जो रास्ता है उस को ऊँचा कर दिया जाये। स्पीकर साहब, वह सबमिग्रियल पुल है रैगुलर नहीं ह। ओर कोई ट्रैफिक वगरैह भी उसके ऊपर नहीं जाती है वह तो विलेज टू विलेज जाने के लिए रास्ते पर बना हुआ पुल है नया पूल बनाने का सरकार को कोई विचार नहीं है।

डा० ओम प्रकाश भार्मा: स्पीकर साहब, चीन के अन्दर पहले बहुत फलड आया करते थे। उन्होंने बांध बना बना कर उस सारे पानी को कन्ट्रोल करके इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करना भुरु कर दिया है मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हर साल फलड से बहुत भारी तबाही होती है बहुत ज्यादा पानी आता है उस पानी को बांध बना कर स्टोर करके इरीगेशन

के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इरीग ान डिपार्टमेंट की मारकण्डा रीवर के पास एक बांध बनाकर पानी इक्ठा करने की स्कीम है। वह स्कीम हरियाणा सरकार ने मंजूर करके ओर सी. डब्ल्यू. सी. से पास करवा करके प्लानिंग कमी ान के पास भेज दी है। अब वह स्कीम प्लानिंग कमी ान के पास क्लीयरेंस के लिए पैडिंग है। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है इसलिए जैसे पैसे उपलब्ध होगा उस योजना को पूरा करेंगे।

Marketing Barrage Project

***564. Ch. Phool Chand:** will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start construction work on Markanda Barrage Project; and

(b) if so, the time by which the aforesaid work is likely to be started?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes,

(b) Work can be started only after the planning Commission clears the project.

चौधरी फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उतर सुन कर मुझे एक कहावत याद आई हैं कि ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यह प्रोजैक्ट कई वर्षों से मंजूर हुआ है। इस प्रोजैक्ट के बनने से कुरुक्षेत्र जिले का फलड रुकेगा ओर उस पानी से अम्बाला ओर कुरुक्षेत्र जिले में इरीगे तन होगी। इन दोनों जिलों में टयूबवैल्ज का बाटर स्टैटा खत्म हो गया है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस प्रोजैक्ट को क्लीरेंस के लिए प्लानिंग कमि तन से काई एलीकेसन की गई हैं? क्या पहले इस प्रोजैक्ट की क्लीयरेंस करवायेगे फिर उसके बाद इसकी कम्पली तन के लिए बजट एलोकेट करेगे?

चौधरी भाम तरे सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, 1982 के आंकडों के मुताबिक इस स्कीम पर 32.32 करोड़ रूपये खर्च होने थे। यह स्कीम सी0 डब्ल्यू0 सी0 से पास हो कर प्लानिंग के पास क्लीयरेंस के लिए पैडिंग है ओर उम्मीद है कि अगले सीजन तक इसकी क्लीयरेंस मिल जायेगी। जहां तक एलोकैट करने का सवाल हैं जिस समय स्कीम भुरू की जायेगी। उस समय बजट अव य एलोकैट किया जाएगा। स्कीम के लिए अभी तक प्लानिंग कमि तन से क्लीयरेंस नहीं मिली हैं इसलिए इस बजट मे पैसा रखने का कोई औचित्य नहीं है।

डा0 ओम प्रका त भार्मा: स्पीकर साहब, पांच ड्रेनो मे फलड आने से हरियाणा के अन्दर बहुत जयादा नुकसान हुआ हैं

ओर बहुत तबाही हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस तबाही में कुल कितना नुकसान हुआ है?

श्री अध्यक्ष: इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री वीरेन्द सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट की स्कीम प्लानिंग कमिशन को कब सबमिट की थी? क्या प्लानिंग कमिशन ने कोई क्वायरी लगाई या कोई आबजैक्सन रज किया जिसके कारण इस प्रोजेक्ट की कम्पलीशन में डिले हुई हो?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इस स्कीम को हरियाणा सरकार ने 27.7.1980 को सैकशन किया था। उसके बाद प्लानिंग कमिशन को स्कीम सबमिट की थी। प्लानिंग कमिशन ने जो भी क्वायरीज लगाई थी उनका जवाब दिया जा चुका है प्लानिंग कमिशन के पास वेरियस किरम की जो स्कीम में पैडिंग है सरकार उनकी क्लीयरेंस के लिए पुरा प्रयत्न कर रही है। वहां से क्लीयरेंस मिलने के बाद ही काम शुरू किया जाता है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने फरमाया है। कि हरियाणा सरकार ने 1980 में यह स्कीम सैकशन की थीं ओर इस समय यह स्कीम प्लानिंग कमिशन के पास पैडिंग है। इसके अलावा मंत्री जी ने यह भी फरमाया है कि प्लानिंग कमिशन ने जो क्वायरीज लगाई थी उनका जवाब दिया जा चुका है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निश्चित जवाब चाहता हूँ कि

इस प्रोजैक्ट से किस किस एरिया को बैनीफिट होने वाला है। इसकी लोके ान क्या हे। ओर सरकार ने इस प्रोजैक्ट के लिए चार साल में क्या क्या कारगुजारी की हैं? इस बारे में मंत्री जो रो ानी डाले ताकि इनकी एफीि एसी का पता लगे कि ये स्टैट के इंटरैस्ट मे कितने फायेदमंद हैं?

चोधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार ने यह स्कीम 1980 में सैक ान करके सी0 डब्ल्यू0 सी0 के पास भेजी थी। वहां से पास हो गई ओर इस समय यह स्कीम क्लीयरेंस के लिए प्लानिंग कमि ान के पास पैडिंग है। इसके अलावा इन्होंने यह पूछा है। कि किस किस एरिया को इस स्कीम से फायदा होगा। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह प्रोजैक्ट मारकण्डा रिवर पर रिजरवायर बनाकर गांव धनोला से 11 किलोमीटर दूर बराडा की साइड मे पानी को इकटठा किया जाएगा। इसकी बाउंडरी इस तरह से होगी। मारकण्डा रीवर के साउदर्न वेस्टर्न साइड पर चुतंग नाला के साउदर्न ईस्टर्न साइड पर ओर जगाधरी रोड के साउदर्न साइड पर यह बाउंडरी होगी। इस स्कीम से 57,373 एकड़ जमीन सेराब होगी। इसकी इरीगे ान इन्टेसिटी 62 परसेन्ट है ओर पानी 2.4 क्यूसिक हैं टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 80,853 एकड़ फीट में होगी। यह प्रोजैक्ट मारकण्डा रिवर ओर टरीब्यूटरीज पर बनाया जाएगा। इसका कैचमेंट एरिया 228.54 सुकेयर माइल्ज होगा। मारकण्डा रीवर में हर सीजन में 70 हजार क्यूसिक्स पानी दो सप्ताह या

तीन सप्ताह बहता है। लेकिन सारे साल की एवरेज 10 हजार क्यूसिक्स हैं इस प्रोजैक्ट से कुरुक्षेत्र ओर अम्बाला के एरियाज को इरीगे इन का भी फायदा होगा ओर फलड से भी बचाव होगा। प्लानिंग कमि इन क साथ हमारी जो कोर्सपोडैस हुई है। अगर डा0 साहब वह देखना चाहे तो मै दिखा सकता हूं।

चौधरी फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, अभी तक एस0 वाई0 एल0 का मामला अनसर्टन हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रोजैक्ट को पर्सनल लेवल पर डील करने की कोशिश करेंगे ताकि पैसे का सदुपयोग हो सके?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, कल या परसों भी मैने कहा था कि दादुपुर से 590 क्यूसिक्स की एक नहर निकाले जाने की योजना है। इस नहर के निकलने से तकरीबन 4 5 कास्टीच्यूंएसीज को फायदा होगा। एक तो वह स्कीम हैं और दूसरी यह मारकण्डा बैराज की स्कीम है। मेरा ओर डिपार्टमेंट का यही ख्याल हैं कि दादुपुर वाली स्कीम ज्यादा लाभदायक होगी क्योंकि इस पर 15 करोड़ खर्च होने हैं ओर मारकण्डा बैराज पर 33 करोड़ रूपये खर्च होने हैं। यह सवाल यह है कि इन दोनो स्कीमों में से किस को प्रायोरिटी दी जाये। यह डिटरमीन किया जा सकता है। बैठकर फेसला किया जा सकता है। हाउस को मै बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे फण्डज उपलब्ध होंगे उसी हिसाब से सारी स्कीमों को लागू किया जाएगा।

श्री लक्षमण सिंह: यह बात ठीक है कि इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। जैसा अभी फूल चन्द जी ने कहा है कि एस0 वाई0 एल0 का मामला अभी लटका हुआ है। ओर पता नहीं कब फैसला होगा ओर कब कुरुक्षेत्र ओर अम्बाला जिले को पानी मिलेगा। एस0 वाई0 एल0 के मामले में बड़ी ढील चल रही है। मैं तो समझ रहा हू कि it may take years and years ओर इस विधान सभा की लाईफ में तो यह नहर बनने वाली है। नहीं। इन्होंने वहां पर 20 25 करोड़ रूपया खर्च कर दिया लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये इधर से उधर से पेसा निकाल कर इस स्कीम को पूरा कराने के लिए प्लानिंग कमी इन को कहेंगे कि हमारे पास इतने फण्ड अवलेबल है ओर आप भी अपनी कन्ट्रीब्यू इन इस में डाल दें ओर हमें इसे बनाने के लिए कलियरैस दे दे?

चोधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदयख एस0 वाई0 एल0 का मामला कोई बर्डन नहीं है। जो बात यह कह रहे हैं कि यह नहर बनेगी ही नहीं। यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि यह नहर कुछ अर्से में बन जायेगी। सरकार के पास ऐसे कारण मौजूद हैं जिनकी वजह से इस नहर पर काम बहुत तेजी से होगा ओर जल्दी ही तैयार हो जायेगी। जो बात इन्होंने यह कही कि इस विधान सभा की टर्म में यह पूरी नहीं होगी। यह इनकी गलत बात है वैसे देखा जाये तो एस0 वाई0 एल0 का पानी ज्यादातर उन स्थानों के लिए है जहां पर

पानी नहीं पहुँचा। सरकार दोनों स्कीमों को प्राथमिकता के आधार पर कम्पलीट करना चाहती है। ताकि सभी इलाकों को फायदा पहुँच सके।

चौधरी साहब सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कई जिक्र किया है कि नलवी लिफ्ट इरीगे 1 न ओर जोगना खेडा लिफ्ट इरीगे 1 न स्कीमों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या वे इन स्कीमों पर विशेष रुचि लेकर पूरा करवाने की कोशिश करेंगे ताकि अम्बाला ओर कुरुक्षेत्र जिले को अधिक से अधिक फायदा पहुँच सके?

चौधरी भाम सिंह सुरजेवाला: हम स्कीम में पूरी रुचि लेते हैं ओर इस स्कीम को भी पूरा करवाने में पूरी रुचि लेंगे।

सेठ राम दास धमीजा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा हैं कि इस स्कीम पर 33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पता नहीं सरकार क्यों घबरा रही हैं मैं कहना चाहता हूँ कि 33 करोड़ रुपये खर्च करने में यदि 100 करोड़ आते हों तो फिर 33 करोड़ रुपये खर्च करने में क्या दिक्कत हैं? इसीलिये क्या मंत्री जी मारकण्डा बैराज को टोप प्रायोरिटी देकर बनाने की कोशिश करेंगे?

चौधरी भाम देव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार हर स्कीम को प्रायोरिटी देती है। मौजूदा फाइनेंशियल रिसोर्सेज के तहत जो काम किया जा सकता है वह किया जा रहा है। इस बात को हाउस के मैम्बर भी नहीं चाहेंगे कि हरियाणा की जनता पर ओर टैक्स लगाये जाये। इस समय जो सीमित रिसोर्सेज हैं उसको ध्यान में रखते हुए हर स्कीम को प्राथमिकता देते हैं।

Sanjai Memorial POlytechnical Institute Bhiwani

*689. Shri. Hira Nand Arya: will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether an ycomplaint has been received by the Government or the Deputy Commissioner, Bhiwani against Sanjai Memorial POlytechnical Institute, District Bhiwani during the years 1981 to 1984 (to-date); if so, action , if any, taken thereon; and

(b) whether any grant has been given to the said institution during the period referred to in part (a) above; if so, whether it has been properly utilized?

उद्योग मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया):

(क) हां ि िकायते प्राप्त हुई थी। यह ि िकायते प्राप्त होने पर इस संस्थान के प्रबन्धकों को एक नोटिस दे दिया गया है। ओर आदेश दिये गये हैं कि भवन, म िनरी, अन्य उपकरण, फर्नीचर व स्टाफ की कमियों को भीघ्न दूर करे। ओर दिनांक 5.4.

84 तक रिपोर्ट दे। उन्हें यह भी आदेश दिया गया है। कि आगामी आदेशों तक इन कोर्सों में कोई दाखिला न किया जाये।

(ख) इस संस्थान के प्रबन्धकों को संस्थान के भवन निर्माण के लिए 5.00000 रूपये की राशि वर्ष 1981-82 (मार्च 1982) में अनुदान के रूप में दी गई थी। यद्यपि बाद में खर्च वर्ष 1982-83 में करने की स्वीकृति दी गई थी किन्तु अभी तक उनसे इस राशि के व्यय के बारे में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह ठीक बात नहीं है। कि भारत सरकार की एक टीम 11.11.83 को निरीक्षण के लिए वहां पर गयी थी? उस टीम ने निरीक्षण के समय इस इन्टीन्यूशन की न कोई बिल्डिंग न पुस्तकालय, न फर्नीचर और न हीं मीनरी आदि देखी। जुलाई 1983 में 40 बच्चों का स्टैनोग्राफी ट्रेड में एग्जाम हुआ था लेकिन उसका परिणाम आज तक घोशित नहीं हो पाया है। क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से उस इन्स्टीच्यूशन को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है यहाँ पर लाखों रूपया बच्चों से दाखले के वक्त इकट्ठा किया गया। यदि ये लिस्ट देखना चाहें तो मैं वह लिस्ट भी इन्हें दिखा सकता हूँ जिन से पैसा इकट्ठा किया गया।

श्री मती भाकुतला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय, ऐसी संस्थाएं भारत सरकार की सहायता से स्टेट गवर्नमेंट के तहत

चलायी जाती हैं उस टीम ने वहां पर जाकर निरीक्षण किया था। यदि सैन्टर की टीम निरीक्षण के बाद ठीक समझे तो उस संस्था को मान्यता दे सकती हैं अगर ठीक न समझे तो मान्यता नहीं दी जाती। हम मान्यता प्राप्त करने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताकि बच्चों का भविष्य ठीक हो।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं पूछा है कि क्या 11.11.83 को भारत सरकार की कोई टीम निरीक्षण के लिए गयी थी? यदि उस निरीक्षण के समय उस टीम ने इन्स्टीट्यूट का कोई भवन, लाईब्रेरी आदि पाई थी या नहीं?

श्रीमती भाकुतला भगवाडिया: मैंने बताया है कि ऐसी प्राइवेट संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने में पहले भारत सरकार की टीम आती है यदि वह ठीक समझे तो मान्यता मिल जाती है और ठीक न समझे तो मान्यता नहीं मिलती। लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को भारत सरकार से इस संस्था की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।

डा० भीम सिंह दहिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में माना है कि संस्था के खिलाफ कुछ कम्प्लेंट्स आयी है। और कम्प्लेंट्स के आधार पर नोटिस दिया गया था और उस 5.4.84 तक रिपोर्ट देने के लिए लिखा गया है मैं जानना चाहता हूँ कि यह रिपोर्ट कब आई? किसने दी तथा आपने उस संस्था को कब नोटिस दिया?

श्री अध्यक्ष: यह बात सरकार ने मानी है। कि रिाकायत आयी हैं ओर उनको नोटिस दिया हुआ हैं अगर अब आप यह पूछे कि कब रिाकायत आयी किसने दी ओर कब नोटिस दिया गया तो यह बात बनती नहीं। यदि इस तरह से एक एक डिटेल पर जायेगे तो सारे हाउस को तसल्ली नही हो सकेगी। आप ठीक सवाल पूछें। आप इनको बता दे कि कम्पलेट कब आयी थी।

श्रीमती भाकुतला भगवाडिया: जब मैं वहां ग्रिवेंसिज कमेटी की मीटिंग में गई थी तो यह रिाकायत मेरे नोटिस में आई थी मेरे साथ उस मीटिंग में आर्य साहब भी मौजूद थे। कोन सी तारीख थी यह मुझे ठीक याद नहीं।

श्री मंगल सैन: बहन जी, क्या आप यह बताने की कृपा करेगी कि जिस संस्था की रिाकायत आपके पास आयी हैं उसके पदाधिकारी कोन कोन है।

10.00 बजे

श्रीमती भुकतला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी के पदाधिकारी के नाम इस प्रकार हैं ठाकुर बीर सिंह, दुर्गा पैलेस, भिवानी, भूतपूर्व सहकारिता मंत्री, श्री सज्जन सिंह सपुत्र ठाकुर बलवन्त सिंह, लोहड, भिवानी, श्री भंवत सिंह कप्तान, लोहड बाजार भिवानी, श्री ब्रहमजीत सिंह सपुत्र श्री ठाकुर बीर सिंह, दुर्गा पैलेस, भिवानी, श्रीम सरजीत सिंह सपुत्र श्री आ गा सिंह, पी टी आई, वै य हाई स्कूल, भिवानी, मेजर राम सरूप सिंह, गांव

सिरसा घादेडा, भिवानी, श्री आ गपत सिंह सपुत्र श्री राय सिंह गांव व डाकखाना आजेका गांव सिरसा श्री अजीत सिंह एडवोकेट, भिवानी, श्री महीपाल सिंह सपुत्र श्री बाबू सिंह, मन्दिर, जिला करनाल, श्री सुरजपाल सिंह, चेयरमैन हरियाणा स्टेट लैण्ड डेवैल्पमेंट बैंक चण्डीगढ ओर कप्तान गनपत सिंह गांव केलंगा, जिला भिवानी। जहां तक संस्था के खिलाफ रिाकायत का ताल्लुक है इस संस्था में न पूरे निदेशक थे न प्रयोग माला थी न कोई सामान था न लडकों को बैठने के लिए कोई स्थान न था न कोई बिजली आदि की सुविधाएं प्राप्त थी ओर न ही यह संस्था रजिस्टर्ड थी यह बताया गया कि संस्था ने प्रत्येक छात्र से दाखिले केसमय दो हजार से सात हजार रूपए तक पैसे लिए। इसके इलावा जुलाई, 1983 में स्टैनो के पेपर हुए थे। लेकिन इसका परिणाम अभी तक नहीं निकाला गया ओर आगे के लिए छात्रों के पेपर होने की कोई आशा नहीं है।

श्रीमती चन्दावती: स्पीकर साहब, मैं खास तौर पर मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जिस संस्था को कोई मान्यता न हो, जिस में कोई मीनिरी हा, न सामान हो, न स्टाफ हो, क्या ऐसी संस्था को 5 लाख रूपये का अनुदान दिया जा सकता है? अगर सरकार ने दिया है तो किस कानून ओर कायदे के तहत दिया है?

मुख्य मंत्री (चोधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने बड़ी तफसील के साथ सारी बात हाउस को बताई है इस

वक्त बहुत सी प्राईवेट मैनेजमेंट की संस्थाएं चल रही हैं। केवल यही एक संस्था नहीं है और भी है। यह बात बिल्कुल ठीक है। कि भारत सरकार की एक कमेटी आई थी और उस कमेटी ने इस संस्था के बारे में कुछ इतराज किए कि इस संस्था में ये चीजें ओर होनी चाहिए इसलिये उन्होंने मान्यता नहीं दी। (व्यवधान) मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ आप सुन लीजिए। हमने नोटिस दिया कि 5.4.84 तक जो कभी कमी है पूरी करनी होगी।

श्रीमगल सैन: आपने नोटिस कब दिया था?

चौधरी भजन लाल: क्योंकि रिक्वायर्ड आई थी उनके आधार पर हमने उनको 1983 में नोटिस दे दिया। अब पता लगा है कि 16 कमरे कम्प्लीट हो चुके हैं। बहुत सा सामान भी ले लिया है और उनका कहना है कि 5.4.84 से पहले पहले भारत सरकार ने जो एतराज उठाए हैं उनको दूर कर दिया जाएगा और सारा काम पूरा कर दिया जाएगा। जहां तक पैसा देने का सवाल है। इस संस्था को 5 लाख रुपये की ग्रांट दी है। हर एक संस्था को ग्रांट देते हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्रीमती चन्दावती: जब उनको मान्यता ही नहीं है तो आपने पैसा कैसे दे दिया? (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: आप पूरी बात सुन तो लीजिए। पैसा देने से पहले सरकार ने यह देखना होता है कि जो पैसा हम दे रहे हैं वह ठीक तरह से खर्च होगा या नहीं? उनको पैसे का

हिसाब देना पड़ता है जहां तक इम्तिहान की बात है 32 लडको ने इम्तिहान दिया था उनका रिजल्ट आ चुका है ओर हम पूरी कोशिश कर रहे है। कि इस संस्था को मान्यता मिले। जयो ही यह संस्था भारत सरकार की कडी गन्ज को पूरा करेगी भारत सरकार इसको मान्यता दे देगी।

श्री सागर राम गुप्ता: स्पीकर साहब, मै मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हू कि जो अनलिमिटेड प्राईवेट कम्पनी को सरकार ने पांच लाख रूपये दिय हैं क्या इसके लिए सरकार के पास कोई रूलज हैं? यह पैसा क्या हरियाणा सरकार ने दिया है या भारत सरकार न दिया है? अगर हरियाणा सरकार ने दिया हे तो क्या सरकार बतायेगी कि क्या ऐसे कोई रूलज हे जिनके तहत पांच लाख रूपया दिया गया है।?

चौधरी भजन लाल: यह पांच लाख रूपया हरियाणा सरकार ने दिया है ओर देने से पहले सरकार यह देखती है कि यह पैसा ठीक ढंग से खर्च होगा या नहीं होगा, जब सरकार की पूरी तसल्ली हो जाती है तो पेसा देती है और इस केस में हमारी पूरी तसल्ली है इस संस्था ने अब 16 कमरे बनाकर तैयार कर दिये हैं और संस्था बाकायदा चल रहीं है।

चौधरी सुरेन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक बात बताई कि उन्हें यह पता लगा है कि 16 कमरे तैया हैं क्या वे बतायेगें कि वे कमरे कहां बने है? इस संस्था का सबसे

पहला प्रौस्पैक्टस मेरे पास हैं जिसको हिन्दी में विवरण पत्रिका कहा जाता हैं इस प्रौस्पैक्टस के अनुसार यह संस्था रजिस्टर्ड दिखाई गई है। यह सीरियल नं० 25 पर लिखा हैं इसके बाद दाखिला के सिलसिले मे जो एडवरटाइजमेंट इन्होंने ट्रिब्यून अखबार में दी हैं उस में भी इस संस्था को रजिस्टर्ड दिखाया हैं इसके बाद संस्था ने 40 लड़को के इम्तिहान लिए ओर जो पर्चा दूसरे आई टी आई को दिया गया था वह यहां नहीं आया था। और इन लड़को को साईक्लोस्टाईल्ड पर्चा दिया गया। जब ऐसी पोजी न हो तो परिणाम कहां से आयेगा। क्योकि वास्तव में यह एग्जाम नहीं था और न ही यह संस्था रजिस्टर्ड हैं न ही इसकी सैव न आई है न ही 5 लाख रूपये का यूटिलाइजे न सर्टिफिकेट आया हैं मुझे तो यह लगता हैं कि यह संस्था भिवानी जिले में बनी हैं जहां तक मै जानता हूं एक भी कमरा नही बना है। जहां पर मुख्य मंत्री ने पत्थर लगाया था वहां कोई कमरा नही बना। स्पीकर साहब, यह एक बड़ा सीरियल एलीगे न है कि मैक्सिम लडकों से दो हजार से लेकर सात हजार रूपये तक डौनेसन ली गई । लेकिन उनको कोई रीद नही दी गई। अगर कोई संस्था किसी व्यक्ति से डौने न ले तो उसकी रीद बहुत जरूरी हैं इसके अलावा सबसे बड़ा प्रूफ सबसे बडा डाकुमैट यूटिलाइजे न सर्टिफिकेट हैं जो गवर्नमेंट को संस्था की तरफ से मिलना चाहिए लेकिन वह नहीं मिला हो सकता हैं बोगस रसीदें दी हो। कया मुख्यमंत्री महादेय इस सारे मामले की इन्क्वायरी करवायेगे?

चौधरी भजन लाल: मैने कहा है 16 कमरे बने हैं यह बिल्कुल सही बात है 16 कमरे बनकर बिल्कुल तैयार हो गये है। जहां तक डोनेसन लेकर रसीद न देने की शिकायत है बहुत सी संस्थाएं डोनेसन लेती हैं ओर रसीद देती हैं अगर माननीय सदस्य को भाक है कि इसमें कोई गडबड हुई है। तो मेरे नोटिस में लाये हम इसकी इन्ववायरी करेगे (व्यवधान)

श्रीमती चन्दावती: किस तरह से आपके नोटिस में लाये। (व्यवधान) कैसे नोटिस में लाया जायेगा?(व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: मेरी अगली बात सुनिये(व्यवधान)

श्रीमती चन्दावती:

श्री अध्यक्ष: यह रिमाक्स रिकार्ड न किए जाये।(व्यवधान)

चौधरी देवी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष: क्वै यन आवर मे प्वायंट आफ आर्डर नहीं होता आप बैठ जाइए।

चौधरी देवी लाल:.....

श्री अध्यक्ष: मेरी परमिशन के बगैर जो कुछ बोला गया है वह रिकार्ड न किया जाये। (व्यवधान) जो मैम्बर बिना परमिशन से बोलेगा वह रिकार्ड नहीं होगा।

चौधरी देवी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के अन्दर जो बात कह रहा हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ माननीय सदस्य मेरी बात पुरी होने दे। चौधरी सुरेन्द सिंह जी ने डोने अन लेकर रसीद न देने की बात कही हैं इस पर मैं यह कह रहा था कि कोई भी मैम्बर इस बात को सरकार के नोटिस में पहले नहीं लाया आज ही यह बात इन्होंने हाउस में कही है। हम इसी बात पर इसकी इन्कवायरी करवा लेगे। अगर किसी का फाल्ट मिलेगा। चाहे कोई कितना ही बडा आदमी क्यों न हो सरकार उसके खिलाफ जरूर एक अन लेगी।

श्रीमती चन्दावती: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी का यह कहना हैं कि उनके नोटिस में नही लाया गया हैं सही नही है। जब इनकी मिनिस्टर साहिबा ग्रिवेसिज कमेटी की मीटिंग में गई थी तो वहां के लोगों ने इनसे रिक्वायत की थी। जब लोगों ने रिटन रिक्वायत की हो तो क्या मंत्री महोदया बतायेगी कि रिटन रिक्वायत के इलावा ओर कोन सा तरीका है। जिस के द्वारा उनके नोटिस मे लाया जाए? हम लोग इनके नोटिस में पहले ही लो चुके हैं ओर अब हम चाहते है। कि इसकी इन्कवायरी होनी चाहिए।

श्रीमती भाकुतला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय, इसी लिए तो इस संस्था को नोटिस दिया है मैं वहां गई रिक्वायतें सुनी। इसीलिये तो इस संस्था को नोटिस दिया है अन्यथा इससे पहले तो कोई नोटिस ही नही दिया था।

श्री हीरा नन्दआर्य: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ मुख्य मंत्री ने कहा कि यह सरकार के नोटिस में नहीं था ओर दूसरी तरफ मुख्य मंत्री महोदय कह रही है कि लोग उनके नोटिस में लाये थे क्या यह दोनो बातें कंट्राडिक्टरी नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष: आप दोनों बातें सुनिए। वे कह रही हैं कि ग्रिं वैसिज कमेटी में जब बात मेरे नोटिस में लाई गई तो मैंने इसका नोटिस लिया। दूसरी बात यह कही गई कि दो हजार से सात हजार तक का डोनेशन लिया गया था इस के बारे में मैं आप इनसे बात कर ले। अगर इनकी तसल्ली हो जायेगी। तो ये इन्क्वायरी के लिए तैयार है।

श्रीहीरानन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, 13 अगस्त, 1983 की ट्रिब्यून में एक एडटाइजमेंट छपी थी जिसके तहत यह दाखिला हुआ था उसे हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार की बात तो छोड़ी मान्यता नहीं दी थी इसके बावजूद भी 160 लडके दाखिल किए गए। क्या मुख्य मंत्री जी बतायेगें कि यह बात ठीक है फिर अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जो मैमोरेन्डम दिया गया था उसमें लाखों रुपये के घपले की बात लिखल हुई थी। उसमें यह भी लिखा था कि किस किस छात्र ने कितने कितने रूप्यें दिये थे। क्या मंत्री जी बतायेगें कि उन्हें इस तरह का मैमोरेन्डम मिला था।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का संबंध है कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करके दाखिला किया 247

लडकों के दाखिले हुए हैं यह ठीक बात है (विघ्न) जहां तक हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता देने का सवाल है यह मान्यता तब देती है जब पहले भारत सरकार मान्यता दे दे। भारत सरकार को हमने केस रिकामैन्ड करके भेजा कि इस संस्था को मान्यता दी जाय। इस के बाद भारत सरकार की एक टीम आती है उसने देखना होता है कि संस्था सारी कंडी ान्ज पूरा करती है या नहीं। चूकि इस संस्था ने सारी कंडी ान्ज पुरी नहीं की थी इसलिए उन्होंने इसे मान्यता नहीं दी अब सारी कंडी ान्ज को 5.4.1984 तक पुरा करने के लिए दोबारा समय दिया गया है उसके बाद कमेटी उसे देखेगी। अगर उसकी तसल्ली हो जायेगी तो मान्यता मिलेगी।

श्री वीरेन्द सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने आ वासन दिया है कि अब इंकवायरी हो जायेगी। लेकिन बहन जी ने जो कंप्लेन्ट पत्र पढ कर सुनाया उसमें स्पैसिफिक ऐलीगेशन है कि जो लडके दाखिल हुए उनमें दो हजार रूपयें से लेकर 7 हजार रूपये तक की घूस ली गई यह कम्प्लेन्ट इन्हें 1983 में मिली थी क्या मंत्री जी बतायेगी कि इस कम्प्लेन्ट पर क्या कोई इंकवायरी करवाई गई ? अगर करवाई गई तो वह किस स्टेज पर है ओर कोन आफिसर उसकी इंकवायरी कर रही है

श्रीमती भाकुतला भगवाडिया: स्पीकर साहब, मैंने सारी ि ाकायते हाउस को बताई है इस संस्था का निरीक्षण भी किया गया। जब मैं वहां गई तो लोगो ने ि ाकायते की थी 4 5

स्टुडेंट्स भी मुझे मिले थें। आर्य साहब भी वहां मौजूद थे। मैंने आ वासन दिया था कि मैं किसी आफिसर को भेजूगी। मैंने यहां आते ही डायरेक्टर को टेलिफोन किया ओर बुलाकर उन्हे बताया कि मैंने इस किस्म की रिपोर्ट कायते वहां सुनी हैं मैं इस समय यह तो नहीं बता सकूंगी कि किस तारीख को अधिकारी वहां गया लेकिन यह बात सही हैं कि इस संस्था में कुछ कमियां पाई गई हैं जहां तक पैसे का संबंध हैं कोई आदमी अब तक इस का प्रमाण नहीं दे सका हैं अगर कोई प्रमाण दे सकता हैं तो हम इंकवायरी के लिए तैयार है।

श्रीमंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी काबिल बहन जी से यह जानना चाहता हू कि सन् 1983 में रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी आपने अब तक इंकवायरी क्यों नहीं करवाई?

श्रीअध्यक्ष: वे कह रही हैं कि पैसे के मुतालिक कोई सबस्टांटिव बात नहीं मिली।

श्रीमंगल सैन: क्या इन की जानकारी में यह बात हैं कि उस मैमोरैण्डम में लिखा हुआ था कि जो लाखों रूपया सरकार ने दिया है। उसका सदुपयोग नहीं किया गया बल्कि दुरुपयोग किया गया? स्पीकर साहब, एक बात में इन से ओर पूछना चाहता हू। मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इन्होंने तो भारत सरकार को रिपोर्ट करके भेज दिया था कि इस संस्था को मान्यता दी जाये। लेकिन भारत सरकार की कोई गारण्टी वहां गई ओर उस

ने सारी कंडी एनज को देखा। मैं इन से यह जानना चाहता हूँ कि अगर सारी कंडी एनज सही थी तो उसे मान्यता क्यों नहीं मिली ओर अगर सही नहीं थी तो इन्होंने मान्यता देने के लिए क्यों रिकोमैन्डे एन की थी?

श्रीमती भाकुतला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि हरियाणा सरकार ने उस संस्था को 5 लाख रूपया दिया। सरकार का हमें प्रयत्न रहता है कि जो पैसा दिया गया है वह ठीक रूप में लगे। स्पीकर सर, यह बात भी सही है। कि भारत सरकार से जो टीम आई थी उसने देखा कि उस संस्था में जो चीजे चाहिए थीं चाहे वह मॉनिटरिंग थी चाहे अध्यापक थे यह बिल्डिंग थी उनमें कुछ कमी पाई गई हमने इस बात को लिखित में माना है ओर इसी वजह से उन्हें नोटिस भी दिया गया है।

श्री निहाल सिंह: क्या मंत्री जी बतायेगी कि कोन से ऐसे कंपैलिंग सरकमस्टॉसिज थे जिनकी वजह से अन-रजिस्टर्ड संस्था की कंडी एनज पुरी न होने के बावजूद भी 5 लाख रूपये की गारंन्ट दी गई है।? क्या गारंन्ट देते वक्त कोई ऐसी भार्त लगाई गई थी कि अगर यह पैसा सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया तो वापिस करना पड़ेगा?

चौधरी भजनलाल: अध्यक्ष महोदय, जब अनुदान देते हैं तो बहुत सी बातें देखते हैं क्या उनके पास जमीन मौजूद है या

नहीं हैं क्या ऊपर कुछ पैसा खर्च किया गया है या नहीं किया गया है? इन सारी बातों को देखकर जब सरकार की तसल्ली हो जाए तब हम अनुदान करते हैं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन देखना यह होता है कि आया ये संस्थाएं ठीक चल रहीं हैं या नहीं संस्था का परचज क्या है। इससे प्रांत के लोगों को प्रान्त के पढने वाले बच्चों को क्या लाभ मिलने वाला है। ये सारी बाते देखकर हमने भारत सरकार को इस संस्था को मान्यता देने के लिए रिकोमैन्डे इन की थी। हमने सोचा था कि इस संस्था से पढे लिखे बच्चों को आसानी से काम मिलेगा। (विघ्न) यह बात ठीक है कि हमने इस बात की स्वीकृति दी कि ये ये कोर्स आप चालू करे। हमारे आदे 1 से ही उन्होंने दाखिला भुरू किया है (गोर)

श्री ए० सी० चौधरी: स्पीकर साहब जिस तरीके से मंत्री साहिबा ने बताया कि इस संस्था की कमेटी के फलां फलां नाम है। उसको सुनने के बाद मेरे मन में एक वहम हो गया है कि ये एक ही फैमिली के लोगों के नाम हैं सरकार को इस मामले में तो छानबीन करनी ही चाहिए। यह एक पैक्यूलियर सवाल है जो मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, क्या एक ही बिरादरी के लोग इंस्टिट्यू इन रन नहीं कर सकते?

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर साहब, मैंने कुनबा कहा था बिरादारी नहीं। सरकार इस की इंक्वायरी कराये या न कराये यह इन की मर्जी है (विघ्न)। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि जिन मां बाप ने अपने खुन पसीने की कमाई से दो हजार रूपये से लेकर सात हजार रूपये तक उस संस्था को अनुदान के रूप में दिये हैं इस ख्याल से कि उनके बच्चे पढ लिखकर देश की सेवा करेंगे। क्या उन बच्चों के बारे में सरकार ने कभी सोचा कि आज के दिन उनका भविष्य क्या है? क्या इन्होंने यह चेक किया कि जिस इंस्टीच्यूट को मान्यता ही नहीं दी गई उसने इम्तिहान कैसे कंडक्ट किये और आज के दिन उस इंस्टीच्यूट से इम्तिहान दिए बच्चों के बारे में इन्होंने क्या फेसला लिया है? क्या सरकार उन्हें किसी और मन्जूर जुदा आई टी आई से सर्टिफिकेट दिलवा करके उनका भविष्य रोशन करेगी?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हम बच्चों के भविष्य को बिल्कुल उजज्वल रखेंगे। अगर इस संस्था को मान्यता नहीं मिली तो उन्हें आई टी आई में दाखिला करके उनका इम्तिहान दिलायेंगे ताकि उनका जीवन खराब न हो।

श्री सागर राम गुप्ता: मुझे इस बात की खुशी है कि इस इंस्टीच्यूट से जिन बच्चों का भविष्य खराब हो गया था उनके बारे में चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम सम्भाल लेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि वहां पर 16 कमरे बने हुए हैं मैं भिवानी का रहने वाला हूँ और वही पर रह रहा हूँ। वहां का

कंस्ट्रक्शन वर्क मेरे नोटिस में हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जगह मुकर्रर की थी वहां पर एक भी कमरा नहीं बना है मुझे पता नहीं कि यह रिपोर्ट इन्हें कहां से मिली है। कि वहां पर कमरे बने हुए हैं मैं चीफ मिनिस्टर महोदय से जानना चाहूंगा कि वे कमरे कहां पर बने हुए हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये जगह के बारे में कहते हैं कि कहां बने हैं? मेरे पास इस वक्त नक्शा नहीं है जो मैं यह बता सकू कि कहां बने हैं हो सकता है जगह चेंज कर ली हो। पहली जगह न बनाए हो लेकिन 16 कमरे बनने में कोई सन्देह नहीं है वे बने हैं।

श्री भागी राम: क्या यह बात सत्य है कि ठाकुर बीर सिंह जो पार्टी छोड़ कर इनकी पार्टी में आकर मिनिस्टर बने। ये पांच लाख रूपये की ग्रांट उनकी वजह से दी गई थी? क्या यह भी सत्य है कि वे इस संस्था के मालिक हैं?

चौधरी भजन लाल: इस में कोई दो राय नहीं कि वे मेरी कैबिनेट में मंत्री थे। मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि चौधरी देवी लाल और इनकी पार्टी के सदस्य इस पार्टी में नहीं रहेगे। और अगले सेशन में वे जिस पार्टी में आज बैठे हैं उसमें भी नहीं रहेगे। आप बे तक पिछला रिकार्ड निकलवा कर देख ले मैंने ऐसा कहा था और जो मैंने आज कहा है इसे भी नोट कर ले। अगला सेशन भी आ आयेगा।

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, मैं परसनल एकसप्लेने इन तो दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: जी हां।

चौधरी देवी लाल:.....मैं इनको क्या कहूँ चीफ मिनिस्टर कहूँ या लीडर आफ दि हाउस कहूँ। इनके लायक ये हैं नहीं लेकिन मुझ पर ये अल्जाम लगाते हैं कि अगली दफा में इस साइड मे नहीं हूंगा। मैंने आज तक गवर्नमैट से टक्कर ली है गवर्नमैट को छोड़कर अपोजी इन में आया हूँ। इनकी तरह से मिनिस्टरी की तरफ नहीं भागा हूँ इसलिए मैं आउंगा इस में कोई भाक नहीं मैं इधर नहीं रहूंगा। मैं अगली दफा उधर आऊंगा ओर सब को भगा दूंगा। (ओर) मैं आप से दरखास्त करता हूँ स्पीकर हैं जहां इतनी धांधली मची हुई है सारे भिवानी जिले के मैम्बर कह रहे कि कोई मकान नहीं बना। क्या इसकी इंक्वायरी नहीं करवा सकते? अगर आपको इनका डर लगता है तो मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि आपको इंडिपैटैड खडा कर सकता है। ओर आपके मुकाबले मे आदमी नहीं खडा करूंगा। बस मे यही अपनी एकसप्लेने इन देना चाहता था।

श्री अध्यक्ष: हालाकि क्वै न आवर में कोई परसनल एकसप्ले इन नहीं हो सकती फिर भी मैंने आपको समय दिया है।

चौधरी देवी लाल: इन्होंने इल्जाम लगाया। आप तो कह रहे है कि क्वै न आवर में प्वायंट आफ आर्डर भी नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: ये रूलज मेरे बनाये हुए नहीं हैं रूलज पार्लियामेंट के बनाये हुए हैं विधान सभा के बनाये हुए हैं दूसरी बात यह है कि आप सब को यह भी पता है कि क्वे न आवर में परसनल एक्सप्ले नेन नहीं होती है। फिर भी सीनियर मैम्बर होने के नाते मैंने आपको समय दिया जहां तक इस बात का संबंध है कि मैं डरता हूं चौधरी साहब, मैं आपसे भी कभी नहीं डरा। जब आप चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त भी मैं नहीं डरा। मैंने जूती के ऊपर रख कर आपकी मिनिस्टरी को फैंक दिया था। (गोर) मैंने जितना सप्लीमेंटरी करने का मौका अपोजी गिन को दिया है उतना किसी को नहीं दिया। इस क्वे न पर इधर से तीन मैम्बरज को मौका दिया है

चौधरी भाम गोर सिंह सुरजेंवाला: बहुत ही निहायत अफसोस की बात है जब चौधरी देवी लाल जैसे सीनियर मैम्बर से स्पीकर पर अस्पॉर्न कास्ट की है यह ठीक नहीं किया यह एक्सपोज होना चाहिए।(गोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, ये कैसे बोल रहे है?(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये पार्लियामेंटरी अफेयर्ज के इन्चार्ज है इन्हे भी कहने का हक है (गोर)

चौधरी भामेरी सिंह सुरजेवाला: बाकी सब कुछ बाते करने से पहले मैं यह दरखास्त करूंगा कि जो चेयर के बारे में अस्पष्ट निष्कास्त की गई है वह एक्सपंज कर देनी चाहिए।

श्रीमती चन्दावती: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह है कि मुख्य मंत्री जी ने सवालों के जवाब...(गोर)

श्री अध्यक्ष: क्या इस तरह से हाउस चलने की मैं इजाजत दूंगा? क्या आप मुकेबाजी चाहते हैं? (गोर)

श्रीमती चन्दावती: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह थी कि मुख्य मंत्री जी ने क्वैशन आवर में विरोधी दल को प्रोवोक किया.....।

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी भजन लाल: आपको याद होगा जब उन्होंने यह कहा कि ठाकुर बीर सिंह उधर से दल बदलकर चले गये थे। तब मैंने दल बदल की बात भुर्रु की वरना मुझे आवयकता नहीं थी पहले ये दल बदल की बात करते हैं। जब भी बोलते हैं दल बदल की बात करते हैं चौधरी देवी लाल ने कहा कि अगली बार तो मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा। जब अगली बार आ जायेंगे तो देख लेंगे।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Utilisation of water from S.Y.L. Scheme

***593. Ch. Balbir Singh Grewal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total amount of water falling to the share of Haryana under S.Y.L. Scheme;and

(b) whether any water out of the water, as referred to in part(a) above, is already being received in the State; if so, the total quantity of water actually received in the State, during the year 1981-82 1982-83 and 1983-84 separately togetherwith the manner of distribution and utilisation thereof in the State?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) total amount of surplus Ravi-Beas water falling of Haryana is 3.5 M.A.F.

(b) Yes, The total quantity of water actually received in the State during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84 are:-

1981-82 1.887 M.A.F.

1982-83 1.732 M.A.F.

1983-84(upto Dect. 83) 1.246 M.A.F

The manner of distribution and utilisation of the above water in the State of Haryana are as below:-

year	Utilisation in Bhakra area		WJC including lift canals	Gurgaon Canal	Total utilisation (M.A.F.)
	Tail BML area.	Narwana Br. area.			
1981-82	0.764	0258	0.613	0.252	1.1887
1982-83	0.636	0.215	0.678	0.203	1.732
1983-84	0.482	0.164	0.494	0.106	1.126

Widening and repair of the Roads

***600. Shri. Ram Bilas Sharma:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen and repair the road between Kanina and MOhindergarh;and

(b) if so, the timeby which the aforesaid proposal is likely to materialise?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हां, महेन्दगढ कनीना सडक किलोमीटर 0 से 18/10 को चौडा करने ओर मजबूत करने का प्रस्ताव है। सामायन्त मुरम्मत का कार्य चालू है।

(ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं अतः समय अवधि अभी निश्चित नहीं का जा सकती।

Scheme for Raising the Water Table

***606. Shri. Kitab Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleaded to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to raise the water table of such places in the States where the water has gone down to the extent of forty feet; and

(b) if so, the time by which the said scheme is likely to be implemented.?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala):

(a) &(b) Since 1974 Ground Water Directorate of Haryana State Minor Irrigation (Tubewells) Corporation has been studying water table fluctuations. According to their study water table has gone down in the following tracts:-

(i)	Abala block	5 to 6 feet
(ii)	Karnal Panipat tract	3 to 4 feet

(iii)	Shahbad Thanesar area	15 to 20 feet
(iv)	Ballabgarh	3 to 5 feet

Main reason would be lack of adequate rainfall to compensate the heavy drawal of sub surface water through shallow tubewells. Their number has increased tremendously.

No special scheme has been formulated. However, 80 syphons capable of contributing about 3000 to 3500 acre feet of water every season have been fitted to Narwana Branch to draw surplus canal water into Augmentation Tubewells.

**Draining out of Flood Water in Badli
Constituency**

***612. Ch. Dhir Pal Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there any villages in Badli Constituency which are still under flood water; and

(b) if so, the names of all such villages togetherwith the area of land still under flood water and the reasons for not dewatering such areas uptil now?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala):

Yes, there is only village viz Luksar where flood water is (a) & (b) still standing in small area of about 50 acres along Haryana Delhi Border. This could not be cleared because of locked up conditions due to non-construction of Chhudani

Bhupania outfall drain in the adjoining Delhi territory which is the only exit/disposal point available.

Lining of Kichhana Minor

***619. Ch. Nar Singh Dhanda:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for lining the Kichhana Minor; and

(b) if so, the time by which it is likely to be done together with the time by which the water is likely to be made available at the tail of the said minor.?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala):

(a) & (b) Yes. There is a proposal under consideration to commence the work of lining of Kichhana Minor during January, 1985 and to complete it by June, the same year.

Appointment of Lok-Ayukat in the State

***634. Shri Nihal Singh:** will the chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint a Lok-Ayukat in the state; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to materialise.?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) प्र न नहीं उठता।

Extension of Bus-Stand

*695. Seth Ram Dass Dhamija: Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the existing Bus-Stand at Ambala Cantt. and

(b) if so, the time by which the aforesaid Bus-Stand is likely to be extended?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh):

(a) yes.

(b) Work on the extension of bus stand Ambala Cantt. is likely to be taken during the next financial year 1984-85.

Free travel by school going children in Roadways Buses

*706. Shri. Fateh Chand Vij: Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) whether it is a fact the the travelling facility given to children in the rural areas for going to and returning

from the schools in State Roadways buses has been withdrawn; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative whether it is in the notice of the government that the said children are not allowed to travel in the State Roadways buses for the said purpose; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government in the matter?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh):

(a) No.

(b) No such complaint has been received.

Registration of Sale-deeds without Stamp Duty

***531. Prof. Samat Singh:** Will the Minister of State for Revenue be pleased to state-

(a) whether any sale deeds were executed in District Hissar without the prescribed stamp duty during the period from January, 1982 to November, 1983;

(b) if so, the number of such sale deeds togetherwith the names and addresses of the concerned persons/societies;

(c) whether any of the sale deeds out of those referred to in part (a) above, have been impounded or are proposed to be impounded; if so, the details thereof; and

(d) whether any action has been taken or isproposed to be taken against the officers/officials responsible for

registering the sale deeds without the prescribed stamp duty; if so, details thereof?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लक्षमण दास अरोडा):

(क) जी हाँ।

(ख) केवल एक विक्रय प्रलेख क्रंमाक 2441 दिनांक 5.1. 1983 गुरू जम्भेवर सल्फर व गुड एवम् खाण्डसारी उत्पादन औद्योगिक समिति लिमिटेड ढनीमाजरा तहसील फतेहाबाद के हक में लिखा गया था।

(ग) इस मूल विक्रय प्रलेख को मुल रूप में सब रजिस्ट्रार फतेहाबाद द्वारा रोका (इम्पाउड) गया था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारी 33 के अधीन इस पर उचित स्टाम्प भुल्क निधारित करने के लिए इसे कलैक्टर हिसार को भेजा गया। इस केस का फैसला दिनांक 2.3.1984 को ही चुका है।

(घ) जी नहीं।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री हीरानन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धयान एक जन महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज के अखबार मे आया है कि हरियाणा सरकार में पैस्टीसाईन्ज के सिलसिले में बडा भारी घोटाला है। ओर उसमे अनके

अनियमितताएं की गई है। इस खबर कर हैडिंग भजन इन पैस्टीसाईडज हैं (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर, इस के बारे में मैंने भी काल अटैन्शन मोशन दिया हुआ है। यह एक बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: मैं उसको कंसीडर करूंगा।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक अखबार दिखाकर मेरा नाम लेकर कह दिया इसीलिये मुझे भी इस बारे में कहना पड़ेगा। (व्यवधान)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट के लिए सब साहेबान बैठ जायें। जो भी चेयर के मुताबिक बातें कही गई हैं। उनको एक्सपंज कर दिया जाये तथा रिकार्ड न किया जाये।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

मुख्य मंत्री द्वारा

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन पैस्टीसाईड दवाईयों के बारे में एक हाई पावर्ड कमेटी के बारे में आज के अखबार में जिक्र आया है यह खबर मैंने भी पढ़ी है। अखबार में लिखी हुई बात की अगर हम इस तह में जाये तो ठीक

बात लिखी है। अध्यक्ष महोदय, पहले कया होता था जब दवाईयां या दूसरा कोई सामान हम खरीदते थे। तो बहुत सी पार्टियों मिलकर पूल करके टैंडर दे दिया करती थी और कान्ट्रैक्ट ऊंचे भाव पर ले जाती थी। सरकार ने यह महसूस किया कि इसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनायी जाये जिस का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर हो। जिस महकमें के लिए दवाई या कोई सामान खरीदता हैं तो उसे महकमे का मंत्री वित्त मंत्री तथा उद्योग मंत्री भी उस कमेटी में मैम्बर होता हैं इसके अलावा उस महकमें का सैक्रटरी और हैड आफ दि डिपार्टमेंट ये सारे के सारे उस कमेटी में आते हैं उस हाई पावर्ड कमेटी की जब कभी मीटिंग होती हैं तो कम से कम 14-15 मैम्बर्ज उस में आते हैं उन सब के सामने सारी बाते आती है। पहले खरीदने का ढंग दूसरा था। हमने एक चीज लेनी है। मान लो तीन पार्टियों ने टैंडर्ज भेजे लेकिन तीनों आदमी आपस में पूल करके एक ही रेट दे देते है। मै सदन को यह बताना चाहता हूं और मैम्बर साहेबान कोयह जानबूझकर खुशी होनी चाहिए कि इस हाई पावर्ड कमेटी के बनने के बाद करोड़ों रूपये का सरकार को फायदा हुआ है जो कि रिकार्ड की बात करता हैं (व्यवधान)

श्री हीरानन्द आर्य: आपको फायदा हुआ होगा।
(व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: यह रिकार्ड की बात हैं जिन्होंने टैंडर दिए हैं अगर उनमें से तीन पार्टियों ने पूल करके 100 रूपये

का किसी चीज का रेट कोट किया है। तो हमने उन पार्टियों में से किसी एक से 80 रूपये के भाव पर वह चीज ली है। सरदार लक्षमण सिंह ती भी यहां पर सदन में बैठे हुए हैं इनके पास भी पहले इन्डस्ट्रीज का महकमा था। अब यह बे एक मंत्री नहीं है। लेकिन वे भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमने इस तरह से एक ही आइटम में 20 लाख रूपये का एक ही दिन में स्टेट का फायदा किया है हमने तो स्टेट के हित में काम किया है। लेकिन यह कहते हैं कि साहब, इस तरह हाई पावर्ड कमेटी के सामने जब टैंडर आते हैं तो लोग ऊंचे टैंडर देने लग गए। इसमें उचे टैंडर का सवाल नहीं है। नेगोिएण्ड भी हम सबके सामने बैठकर करते है। फर्ज करो हमने एक च मा खरीदता है। एक आदमी अगर कहता है। कि मैं 5 रूपये मे दूंगा तो हम दूसरे से कहते है बोल भाई ते कितने में देगा वह कहता है साढे चार मे दूगा। तीसरा कहेगा कि चार में दूगा। चार रूपये से कम अगर कोई भी आदमी नहीं करता तो हम चार वाले से ले लेते हैं। ताकि कोई बेईमानी न हो सके। कोई कुरपान न हो ओर स्टेट का उसमें फायदा हो जाये।

श्री वीरेन्द सिंह: स्पीकर साहब, मैंने यह कहा है कि अखबार में जो खबर आई है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड काल अटैसन मोान दिया है। मुख्य मंत्री जी ने बोलते हुए यह कहा है कि मैंने कई करोड़ों रूपये का स्टेट का पैसा बचा लिया है और यह खबर इनको स्पोर्ट करती है। इन्होंने यह फरमाया है

कि अगर इसको डीपली पढा जाये तो यह पता चलेगा कि इससे स्टेट को फायदा हुआ है हमने एक बार नहीं तीन तीन बार इसको पढा है। स्पीकर साहब, इसमें स्पेसिफिक एलीगे एन्ज है कि जितनी भी फर्मो से नैगो एंजेन्ज की गयी उन सब फर्मो ने इस कमेटी के बनने के बाद रेट ड्योढे से दुगने कोट करने भुरु कर दिये है। मुख्य मंत्री जी ने कहा उनसे 10-15 रूपये घटवा लिये होंगे। अगर वह पहले किसी चीज को 118 रूपये के भाव पर सप्लाई करते थे। तो अब उसे 155-156 रूपये के भाव से देना भुरु कर दिया है इसके अलावा एक आइटम है। जिसके बारे में रूलज यह कहते है। कि हरियाणा बेस्ड फर्मज द्वारा अपने यह चीज सप्लाई होनी है। तो उस फर्म को प्रैफरेंस दिया जाता है। लेकिन उस फर्म को इग्नोर किया जाता है। जिस फर्म ने हाईएस्ट रेट दिया है। वह मल्टी ने एनल फर्म है। उसने इन्होंने डील किया है करोडों रूपये का घपला हुआ है करोडों रूपयो ये खा चुके है। लेकिन आज कहते है कि हमने करोडों रूपए बचा लिए हैं

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इन्होंने यह कहा है कि करोडों रूपए का घपला है। अगर यह साबित कर दे तो मैं अपना इस्तीफा दे दुगा।

श्री वीरेन्द सिंह: स्पीकर साहब, इस बारे में जुडी टायल इन्कवायरी करा ले। हाई कोर्ट के जज से इन्कवायरी करा ले। अगर हमचार्ज न प्रूव कर सके तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

चौधरी भजन लाल: इसमें एक आदमी की बात नहीं है। हाई पावर्ड कमेटी बाकायदा सब बातें देखती है। सबके सामने बैठकर बात होती है। (व्यवधान) छाज तो बोले छलनी क्या बोले जिसमें हजारों सुराख हो। आपने कहा कि स्टेट में लगी हुई फर्ज को प्रैफरेंस नहीं दिया गया। मैं यह बताना चाहता हूँ कि स्टेट बेस्ट फर्ज को हम पहल देते हैं। अगर उसके रेट 10 प्रति 100 ओरो से ऊंचे भी हो तो भी उनको प्रैफरेंस दिया जाता है। (व्यवधान)

(इस समय बहुत से मैम्बर्ज बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष: जब मैं आपको बोलने के लिए पूरा टाईम देता हूँ फिर भी आप ऐसे करते हैं मुझे एक बात बता दीजिए कि जब मैं टाईम दूँ तो पहले किसको दूँ। आप की पार्टी/गुप के मैम्बर्ज में कोई भी नहीं है। ओर न ही कोई डिप्लिनेट हैं। सारे मैम्बर्ज खड़े होकर एक साथ ही बोलना शुरू कर देते हैं। एक और बात है मुझे आज बार बार देखकर बड़ी हेरानी हो रही है। कि हाउस में कोई डेकोरम नहीं है। एलीगे इन लगाने के बारे में यहां तक बात हुई है कि मेरे तक भी मैम्बराज पहुंच गये हैं मैं यह चाहता हूँ कि सारा काम रोक कर पहले इस बात को देख लिया जाये कि कितने सप्लीमैट्रीज किस किस मैम्बर को अलाऊ किये गये हैं।

Shri Verender Singh: Sir, we are satisfied with the time you are giving to us. (interruptions)

श्री अध्यक्ष: वे मैम्बर जो इतने पुराने लीडर हैं वे खडे होकर मुझे यह कर दे कि मैं गवर्नमैट को स्पोर्ट करता हूँ और अपोजी उन को अपोच कर रहा हूँ यह बडे ही अफसोस की बात हैं चौधरी साहब, आपकी बात सुनकर मेरे जिस्म में आग लग रही है। आप यह बात कैसे कहते हो? अगर आप यह बात ठीक समझते हो तो रिकार्ड चैक करवा ले (व्यवधान)

चौधरी देवी लाल: आप हर बात को एकसंपंज कर रहे हो।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो एकसंपंज करने वाली बात होगी वह जरूर एकसंपंज होगी। दूसरी बात इन्होंने यह कह दी कि हम आपको बनायेगे। तभी बनाओगे जब मैं बनने के लिये तैयार हूंगा। तो सब की बात हैं बाहर बात कर लेंगे आपने मेरे पास अपने भाई को मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए भेजा था। मैंने उस वक्त भी आपको ऑफर टुकरा दी थी। कि मैं आपको बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर बनने के लिये तैयार नहीं हूँ आपका भाई चौधरी साहब राम मेरे पास आया और कहा कि मुझे देवी लाल ने भेजा है हमारे पास इतने एम0 ए0 एज0 हैं। कांग्रेस के मैम्बरज टुट कर आ रहे हैं। हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। मैंने आपकी वह ऑफर टुकरा दी थी। आज मैं आपको बताता हूँ। (व्यवधान)

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, हाउस में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इतने बडे एलीगे उन लग रहे हैं। ओ

भिवानी जिले के सारे के सारे एप0 एल0 एज0 यह कहते हे । कि वहां पर कोई मकान नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मै ईमानदारी के साथ इस कुर्सी पर बैठकर यह कहता हूं कि चोधरी साहब राम को इन्होंने मेरे पास भेजा था कि मै ओर कांग्रेस के कुछ मैम्बरज जिनक नाम उन्होंने लिये थे अपने साथ ले आऊं ताकि यह मुझे चीफ मिनिस्टर बना दे । मैने कहा कि ऐसी चीफ मिनिस्टर को मै ठुकराता हूं मै चौधरी देवी लाल के साथ मिनिस्टर रहना पसन्द नही करता तों मै । चीफ मिनिस्टर कैसे मन्जुर करूंगा? (व्यवधान) चौधरी साहब राम यह कह दे कि यह बात गलत है । (व्यवधान)

चौधरी देवीलाल: स्पीकर साहब, आपने भाोर मे उस चीज को भी गुजार दिया कि रूलिंग पार्टी के लोग यह कहते हैं कि वहां पर कोई मकान नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैने इधर से श्री सागर राम गुप्ता को बुलाया चौधरी सुरेन्द सिंह को बुलाया ओर श्री ए0 सी0 चौधरी को बुलाया । आपके मैम्बरज को भी बुलाया फिर भी आपकी तसल्ली नहीं हुई है ।?

चौधरी भाम रेर सिंह सुरजेवाला: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मैं यह कहना चाहता हं कि चोधरी वीरेन्द सिंह जी ने डाक्टर साहब ने ओर कुछ दूसरे सदस्यों ने पैस्टीसाईज की खदीद के बारे में काल अटैन् इन मो इनज दिये हैं । आपने

उनको न तो अभी एडमिट किया ओर न रिजैक्ट ही किया हैं । उससे पहले सारा कुछ लिखकर देने के बावजूद क्या कोई मैम्बर खडा होकर यहां पर उसके बारे में कुछ कह सकता है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं । कि चौधरी देवी लाल ने चेयर के बारे में एस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की है वह एक्पॉन्सिबल होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष: उसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया है ।...

.....

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: एक बात इन्होंने मैम्बरज के बारे में यह कह इसको भी एक्पॉन्सिबल करना चाहिए ।

चौधरी देवीलाल: मैंने गलत क्या कहा है?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल ने जो कुछ कहा है । वह एक्पॉन्सिबल होना चाहिए ।
(व्यवधान)

चौधरी देवी लाल: हाउस में आकर क्या करे?(गोर)

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मैं अपनी बात खत्म करने के पहले एक बात कहना चाहता हूं । जैसे कि आपने फरमाया कि इन्होंने अपना भाई आपके पास भेजा हैं यह कोई नहीं बात नहीं हैं । यह एक वक्त में दस आदमियों भेजते हैं यह इनका पुराना रवैया है । (गोर)

विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, आज पौने बजे मैंने दो काल अटैन्शन मोड दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस के फंट पेज पर न्युज आइटम है 'Bhajan in pesticides deals' इसके नीचे लिखा है (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो काल अटैन्शन मोड आपने दिये है वे मेरे पास अभी नहीं आये है। There should be no reading of the newspaper.

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत के बगैर जो कोई बोले वह रिकार्ड नहीं चाहिए। चौधरी देवी लाल आपकी इजाजत के बगैर बोले हैं यह रिकार्ड नहीं होना चाहिए।(गोर)

चौधरी देवी लाल: आप मिनिस्टर ओर चीफ मिनिस्टर के कहने पर हाउस में हर बात को एक्सपेंज कर दें यह कहां तक ठीक है। ? (गोर)

श्री अध्यक्ष: जब मैं आपको आर्डर करूंगा फिर मुझे कहना (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो मेरी परमिशन के बगैर बोला गया है। वह रिकार्ड नहीं होगा है।

श्रीमंगल सैन: दूसरे पैराग्राफ में लिखा है.....
(गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, नो प्लीज। कल भी यह बात हुई थी। कि क्या कोई आनरैबल मैम्बर अखबार पढ सकता हैं। ओर आपने खुद ही कहा था कि नहीं पढ सकता हैं आप जो पढना चाहते हैं ओर उसी सबजैक्ट पर आपने काल कटैक्सन मो इन भी दिया इसीलिए जो आप कहना चाहते हैं जबानी कह सकते है। (ओर)

श्रीमंगल सैन: स्पीकर साहब, हाई पावर्ड कमेटी बनाने के बावजूद मालप्रैक्टिस रूकी नहीं है। भ्रष्टाचार रूका नहीं है। पहले से मंहगी दवाई ली जा रही है। पूना की एक फर्म का लोएस्ट टैन्डर था उससे नहीं खरीदी गई है। बल्कि एक मल्टी नै इनल फर्म है। जिसका टेन्डर हाइएस्ट था उससे खरीदी गई है। दूसरा मेरा काल अटैन् इन मो इन यह है। कि सरकार ने 95 परसेनट ग्रान्ट कालेसिज के लिए दी थी लेकिन सरकार ने 33 परसेन्ट कट लगा दी हैं इस वजह से सारे टीचर में मैनजमैट में आम जनता में ओर स्टडैन्ट्स में बडा भारी अनरैस्ट है। ऐसा क्यों किया गया है। इस बारे में इनको स्टेंटमैट देना चाहिए। स्पीकर साहब, मुझे माफ करे। आज आपकी तरफ से कुछ ऐसी बाते आ रही हैं जो अच्छी नहीं लगरही है।। अगर चौधरी देवीलाल ने कोई एतराज उठाया है। तो सारे हाउस को उस बारे में सैटिसफाई किया जाए जिससे बाहर यह इम्प्रेरूान जाए कि हाउस बहुत अच्छी तरह से चल रहा हैं यह आपका पर्सनल मामला है। कि आपके पास कौन गया था और आप किसके पास गये। (ओर)

श्री अध्यक्ष: मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन के ऊपर अपोजीसन ने कितने सप्लीमेंटरी पूछे यह आप रिकार्ड से देख सकते हैं। चौधरी सुरेन्द्र सिंह भिवानी के हैं श्री सागर राम भी भिवानी के हैं और उधर से श्री ए० सी० चौधरी किसी ने भी कोई सरकार के हक में बात नहीं कही। आप मुझे से सहमत होंगे। कि कौन सा मैम्बर कैसे बोलेगा। क्या बोलेगा इसका मुझे पता नहीं होता। मैंने कोर्टों की कि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर इस सवाल पर सप्लीमेंटरी पूछ सकें और उनको टाईम दिया जाए। फिर भी कोई आनरेबल मैम्बर खड़ा होकर यह कह दे कि आप गवर्नमेंट को स्पॉर्ट कर रहे हैं। यह कहां तक ठीक है। मैं कोई धर्मात्मा सन्त या पुजारी तो हूँ नहीं। (गोर)

श्रीमंगल सैन: हम आपसे आशा करते हैं.....
(व्यवधान)

श्रीअध्यक्ष: मैं ऐसा इन्सान तो हूँ नहीं कि अपनी इंसल्ट करवा कर बदाँति कर लूँ। चौधरी साहब को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। (गोर)

श्रीमंगल सैन: आप बार बार फरमाते हैं कि मैं अपोजीसन वालों को टाईम देता हूँ आप तो बड़े कामयाब वकील रहे हैं। क्या सरकारी बैन्चिज पर बैठने वाले अपने घर का पर्दा उठा कर देखेंगे कि क्या हो रहा है? वह तो अपोजीशन वाले मैम्बर ही पूछेंगे? (गोर)

श्री अध्यक्ष: मै तो अपोजीसन वालेो को ही टाईम दे रहा हूं।

श्री मंगल सैन: अपोजी इन के मैम्बर्ज तो पूछेगें ही।

श्रीरामबिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, कल आपने फरमाया था कि जो मैने गौड ब्रंहामण कालिज के बारे में काल अटै इन मो इन दी हैं उसको मै कंसीडर कर रहा हूं (तोर)

श्रीम अध्यक्ष: वह मैनें डिसअलाउ कर दिया है।

श्रीराम बिलास भार्मा: उसका जवाब मेरे पास नहीं पहुचा हैं (तोर) मुख्य मंत्री जी इस कालेज के लिए सात लाख रूपय की ग्रान्ट देने का एलान करके आए थे लेकिन अभी तक नहीं की है। इन्होंनें खुद मंजूर की थी। (तोर) कालेज के प्रोफेसर को तनखाह नहीं मिल रहीं है। उनमें असन्तोश हैं

श्री अध्यक्ष: जब मैने आपको कह दिया कि वह मैने डिसअलाउ कर दी हैं तो आप बैठ जाइये। प्रोफैसर्ज को तनखाह मिलना न मिलना यह तो डे टु डे वर्किंग की बात हैं। (तोर)

श्रीम मंगल सैन: जब ग्रान्ट के लिए एलान किया था तो वह गांट मिलनी चाहिएं।

श्री अध्यक्ष: तनखाह न मिलना काल अटैन् इन मो इन का सब्जैक्ट नहीं बनता। (तोर)

श्री राम बिलास भार्मा: मैने कट मो ान्ज दी तो आपके आफिस ने जवाब दे दिया है कि कट मो ान्ज का आब्जैक्ट नहीं दिया गया । मैने कट मो ान्ज को डिसकस करने का आब्जैक्ट लिखा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह डिसअलाउ कर दिया हैं। (गोर)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मेरी डिमांड्ज के ऊपर कट मो ान्ज थी वह भी डिसअलाउ कर दी। मेरे बहुत सारे क्वै न थें वह भी रिजैक्ट कर दिये। इसी तरह काल अटैन् ान मो ान दिये थे उनके बारे में भी वेग जवाब लिखकर भेज दिया हैं। (गोर)

श्री अध्यक्ष: जब रूलज परमिट नहीं करते थे तो सवाल ओर काल अटैन् ान मो ान्ज कैसे एडमिट किए जा सकते थे? जहां तक कट मो ान्ज का ताल्लुक है वे विद इन टाईम नहीं दी गई थीं क्योकि जितना टाईम परस्क्राईब्ड हैं उसके मुताबिक नहीं दी गई थीं। इसीलिये ये डिसअलाउ कर दी गई है। ओर मैने रूल भी कोट किया है इसमें दो तीन रीजन्ज लिखे हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: आपने रूल 194 लिखा हैं।

Mr. Speaker: I have disallowed the notices of cut motions on the following grounds:-

(i) the notice is not in time as required under Rule 194(2).

(ii) the objects of the cut motions are not specific as required under Rule 195 (1); and

(iii) the hon. Member should have given notice of each cut motion for each demand separately.

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, on a point of order.

Mr. Speaker: I have given my ruling. Please of order.

श्री राम बिलास भार्मा: मुझे जो जवाब मिला है। उसमें कुछ ओर लिखा है (ओर)

श्री अध्यक्ष: मैंने रूलिंग दे दी है। (ओर) अब आप बैठिए।

श्री राम बिलास भार्मा: आप कुछ फरमा रहं है। ओर आप का औफिस कुछ कहता है।

श्री अध्यक्ष: जो कुछ भी मैंने कहा है वहीं औफिस ने लिख कर भेजा है। जो मैंने रूलिंग पढी है अगर उससे आपका डिफरेंस है। तो मेरे पास 11.30 बजे चैम्बर में आ जायें We will discuss it.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं एक महत्वपूर्ण बात की आरे आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 23 तारीख को पुलिस स्टे न सिवानी मैं एक डाक्टर को बुलाकर ओर बन्दूक की

नली दिखा कर सर्टिफिकेट लेना चाहा। (गोर) इस पर मैंने एक अटैन्शन मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष: उस पर मैंने 24 घंटे के अन्दर अन्दर गवर्नमेंट के कमेंट्स मंगवाए है।

प्रो० सम्पत सिंह: इस संबध मे मैंने भी एक काल अटैन्शन मोशन दी थी। बन्दूक की पर सर्टिफिकेट.....

श्री अध्यक्ष: मैंने कमेंट्स मंगवाए है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरी एक ओर सबमिशन हैं सरकार कालेजिज को 95 परसेन्ट ग्रांट देती है। मैनेजमेंट वाले कहते है। कि उस पर 33 परसेन्ट की कट लगा दी है। लेकिन यह सरकार कर रही है। कि नहीं लगाई है। इसको क्लीयर कर दे कि कोन सी बात ठीक है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: एक ही प्वायंट पर आप दोनों कैसे बोल रहे है। (व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: ये कल की कह रहे थे कि कट नहीं लगाई है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैंने एक्सीजन पब्लिक हेल्थ जीन्द के बारे में काल अटैन्शन मोशन

दिय था। वहां पर 25 करोड़ के लगभग घपला हुआ है मैं अपनी काल अटैन् इन मो इन का फेट जानना चाहता हूं कि उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: इस पर मैंने सरकार से कमेंट्स मंगवाये हैं।

चौधरी बलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में मैंने एक काल अटैन् इन मो इन दे थी। वह जमीन एक ही आदमी के पास है और वह उसका मिसयुज कर रहा है। इस बारे में बता दीजिए क्या बना।

श्री अध्यक्ष: इस पर भी मैंने 24 घंटे के अन्दर अन्दर कमेंट्स मंगवाये हैं।

श्री लक्षमण सिंह: स्पीकर साहब, पैस्टीसाइड दवाई खरीदने के सिलसिले में टैंडर आये थे। और यहां पर कहा गया कि इसमें सरकार को नुकसान हुआ है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय की हाजिरी में और भी बहुत से अफसर वहां मौजूद थे। मेरी नेगोिएशन से सब कुछ हुआ रेट घटे है। और सरकार को 20-25 लाख रूपये का फायदा हुआ है। इसी प्रकार पंजाब को भी भायद 50 लाख रूपये के करीब फायदा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। यह अच्छी बात है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

चौधरी देवी लाल द्वारा

चौधरी देवीलाल: स्पीकर साहब, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। आपने मेरी बावत यह कहा है कि मैंने अपने भाई को आपके पास भेजा था। यह आपकी बात बिल्कुल गलत है मैंने कभी भी किसी को आपके पास नहीं भेजा। (विघ्न) आप के बारे में मे स्पीकर साहब, जो कुछ मैंने कहा है वह बिल्कुल ठीक ही रहा है कोई गलत नहीं कहा है। आप हर मामले में हर बात को एक्सपंज करवा देते हैं और प्रोसीडिंगज में नहीं आने देते। जो कुछ यहां पद कहा जाता है वह सब कुछ हाउस की प्रोसीडिंगज में आना चाहिए क्योंकि पब्लिक सब कुछ सुन रही है। प्रैस भी यहां पर बैठी है अगर आप इस तरह से हाउस की प्रोसीडिंगज को एक्सपंज करवाते रहेंगे तो सरकार के खिलाफ पब्लिक ओपीजसन कैसे बन पाएगी? (गोर) मैंने कहा वह कोई गलत बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, मैं जो कुछ इस हाउस में बैठकर करता हूँ वह कोई अन्धेरी कोठरी में बैठकर नहीं करता, उसको पब्लिक भी देखती है। प्रैस भी देखती है। ओर आनरेबल मैम्बरज भी देखते हैं। मुझे यह कहने में बिल्कुल भी हिचकचाहट नहीं है कि लीडर आफ द ओपीजसन ने मुझे 10 दफा आकर यह कहा है कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर हमारे

मैम्बर्ज ठीक ढंग से बात नहीं करते हो हम आपके ऊपर किसी बात का गिला नहीं कर सकते । दूसरी बात आपने यह कही है । कि मैं यहां होने वाली हाउस की प्रोसीडिंगज को एक्सपंज करवा देता हूं । कोई ऐसी बात जो एक्सपंज न होने वाली मैंने एक्सपंज करवायी हो तो आप बता दें । आपको मैं बताना चाहता हूं कि पीछे अखबारों में भी यह आया था कि स्पीकर हरियाणा ने बैस्ट कंडक्ट किया है । तो आप चेयर के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं?

श्रीमती चन्दावती: स्पीकर साहब, मैं एक बात बताना चाहती हूं हमने पहले भी कहा है । कि हम किसी भी हालत में चेयर से झगड़ा नहीं लेना चाहते हैं । हम तो सरकार के गलत कामों पर सरकार से लड़ने के लिए नोटिस संरक्षण चाहते हैं । आप हमें इसके लिए संरक्षण दें । मैं कई बार आपके नोटिस में भी लायी हू कि फलां फलां मिनिस्टर साहब उठकर झट से यूर्हीं कह देते हैं । कि स्पीकर साहब, यह यह भाब्द एक्सपंज होने चाहिए । ओर हाउस की कार्यवाही में से निकाल दिये जाने चाहिए । फला फला भाब्द हाउस की कार्यवाही का पार्ट नहीं बनने चाहिए । वगैरह वगैरह जनाब मैं यह कहना चाहती हूं कि हाउस की कार्यवाही में से किसी ऐसे वेसे वर्ड को एक्सपंज करने के लिए हाउस के रूल्ज एंड रैगुले ान की एक किताब बनी हुई है । जिसके आधार पर एक्सपंज किया जाता है । कम से कम उस किताब को आधार माने कर हाउस की कार्यवाही चलनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, आप मुझे एक भी ऐसी इन्स्टान्स बता दीजिएगा कि फलां फलां जगह पर फंला वर्ड यू ही एक्सपंज करवाया जाता है।

चौधरी चन्दावती: स्पीकर साहब, सर इन्सटान्स तो मुझे याद नहीं लेकिन मैंने कई बार आपके नोटिस में ये सारी बातें लाने का प्रयत्न किया है। और कहा भी है कि ये भाब्द यू ही एक्सपंज करवाये जा रहे हैं। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

सब स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक औशधियां खरीदनें संबंधी।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, मुझे श्री किताब सिंह एम0 एल0 ए0 की तरफ से सब स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक मैडीसिन्ज के बारे में एक काल अटैन्डान्स का नोटिस मिला है। मैं इस एडमिट करता हूँ। आनरेबल मैम्बर कृपया अपना नोटिस पढ़ ले। उसके बाद महोदय, आज कोई जवाब देना चाहे तो दे दें।

श्री किताब सिंह: मैं सरकार का ध्यान एक अत्यधिक जन महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उद्योग विभाग हरियाणा ने अनुसूची ए टैन्डर नोटिस नं0 14/1982-83, टैन्डर का क्रमांक जी0एल/आर0सी/ 568/82-83 तथा टैन्डर खुलने की तिथि की दिनांक 7.10.82 के 2.00 बजे मध्याह्न पचास तक

थी। द्वारा आयुर्वेदिक ओशधिए जो कि किट में संख्या में चौबीस थी ऊंचे टेण्डर पर खरीदी जबकि दोनों ओशधियों जाति फलादि बटी तथा कपूर इस प्रयोग ाला में टैस्ट करने पर सब स्टैर्डड की पाई जाती है। अतः सरकार को इस प्रंकार की घटिया किस्म की दर्वायां नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि इस मे जीवन का सवाल है। अतः सरकार मामले की जांच करवा के दोशियों को सजा दे तथा इस बारे में सदन को सुचित करे।

वक्तव्य—

उद्योग मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

उद्योग मंत्री (श्रीमती भाकुतला भगवाडिया): आयुर्वेदिक औशधियों की किटों की पूर्ति हुते वार्षिक दर संविदा करने के लिए प्रैस विज्ञापन द्वारा निविदायें मंगवाई गई थी जोकि 8.10.82 को खोली गई थी। कुल मिलाकर निम्नलिखित 14 निविदाताओं ने इसमें अपने दर दिये:—

1	मै0 जन कल्याण आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार	रू0 54—80 प्रत्येक
2	मै0 अतरी आयुर्वेदिक फार्मेसी बेरूत	रू0 54—95 प्रत्येक
3	मै0 संजीवनी रिसर्च लैबोरेट्री गोहाना	रू0 58—80 प्रत्येक
4	मै0 भारत आयुर्वेदिक फार्मेसी अमृतसर	रू0 60—00 प्रत्येक

		लेस कमीसन 3परसैन्ट
5	मै0 हिमाचल ड्रगफार्मा अमृतसर	रू0 62-00 प्रत्येक लेस 2परसैन्ट डिसकाउट
6	मै0 काामीर आयुर्वेदिक वर्कस अमृतसर	रू0 62-60 प्रत्येक लेस 2 परसैन्ट डिसकाउट
7	मै0 दिल्ली स्टेट इण्डस्ट्रीयल डिवैपलपमेंट कारपोरे अन लि0 नई दिल्ली	रू0 63-60 प्रत्येक
8	मै0 परभात आयुर्वेदिक फार्मेसी अमृतसर	रू0 68-50 प्रत्येक
9	मै0 योगी फारमेसी हरदबार	रू0 69-69 प्रत्येक
10	मै0 नव अकित आयुर्वेदिक प्राईवेट लि00 भुसावल	रू0 71-68 प्रत्येक
11	मै0 िवालिक ड्रग कंखल (हरिद्वार)	रू0 75-10 प्रत्येक
12	मै0 पंजाब स्टेट समाल इण्डस्ट्रीज कारपोरेसन लि0 चण्डीगड	रू0 94-00 प्रत्येक (सेल टैक्स सहित)

13	मै० धनवन्तरी आयुर्वेदिक फार्मसी अमृतसर	रु० 94-00 प्रत्येक (सेल टैक्स सहित)
14	मै० जण्डु फारमैसटीकल वर्कस लि० मुम्बई	रु० 103-65 प्रत्येक लैस 1 परसैनट डिसकाउंट यदि अदायगी 30 दिन के अन्दर की जावें ।

2. उपरोक्त अनुक्रमांक 1 से 7 पर दी गई पहली 7 पार्टियों की निविदाओं का तकनीकी निरीक्षण आयुर्वेदिक विशेषज्ञों एवम निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं के 18 प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 25.10.82, 29/30.11.82, 12/13.01.83 और 27.1.83 की बैठकों में किया गया। फर्मों द्वारा दी गई निविदाओं तथा नमूनों का गहन निरीक्षण करने के उपरान्त तकनीकी समिति ने मै० हिमाचल ड्रग फार्मा अमृतसर तथा मै० का मीर आयुर्वेदिक वर्कस अमृतसर की निविदाओं को एन. आई. टी. की विनिर्देशियों के अनुसार पाया। निम्नलिखित 4 फर्मों जिनके दर इन दो फर्मों के दरों से कम थे। को तकनीकी समिति ने एन. आई. टी. की विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाया और इनको रद्द करने की सिफारिश की:-

1	मै० जन कल्याण आयुर्वेदिक हरिद्वार फार्मसी	रू० 54-80 प्रति	किटों में 23 दवाईयों में से 8 एन. आई. टी. की विशिष्टियों के अनुसार नहीं पाई गई।
2	मै० अतरी आयुर्वेदिक फार्मसी बेरुत	रू० 54-95 प्रत्येक	24 दवाईयों में से 6 एन. आई. टी. की विशिष्टियों के अनुसार नहीं पाई गई।
3	मै० संजीवनी रिसर्च लैबोरेट्री गोहाना	रू० 58-80 प्रत्येक	24 दवाईयों में से 16 एन. आई. टी. की विशिष्टियों के अनुसार नहीं पाई गई।
4	मै० भारत आयुर्वेदिक	रू० 60-00	9 दवाईयों में

	फार्मोसी अमृतसर	प्रत्येक लेस कमीसन 3परसैन्ट	से8 एन. आई. टी. की विशिष्टियों के अनुसार नहीं पाई गई।
--	-----------------	-----------------------------------	---

3. इस संबंध में विभिन्न निविदाओं की ओर से प्रतिवेदन भी प्राप्त हुये जिन पर विचार करने के पश्चात् कोई सार नहीं पाकर रद्द कर दिये गये।

4. 21.3.83 को राज्य सरकार ने इन दो फर्मों में हिमाचल ड्रग फार्मा अमृतसर ओर मै0 आयुर्वेदिक वर्कस अमृतसर के साथ 62.60 प्रति किट लैस 2 परसैन्ट डिसकाउंट पर दर संविदा करने की अनुमति प्रदान कर दी ओर दर संविदा 29.3.83 को जारी कर दिया गया। यह दर संविदा 31.3.84 तक लागू है।

5. निदेशक स्वास्थ्य सेवायें हरियाणा ने इस दर संविदा के आधार पर इन दोनों फर्मों पर बराबर बराबर अनुपात में 25525 आयुर्वेदिक ओशधियों किटों का पूर्ति आदेश 29.3.83 को इस भाव पर दिया कि 31.3.83 को माल वे प्रस्तुत करेगे उसी का ही निरीक्षण किया जायेगा।

6. तदानुसार 5 आयुर्वेदिक विशेषज्ञों तथा निदेशक राज्यल स्वास्थ्य सेवाओं के दो अधिकारियों को इन फर्मों की फारमेशियों

में निरीक्षण हेतु भेजा गया और उनहोंने 16200 किटों का निरीक्षण किया। और उन्हें पूर्ण रूप से विनिश्चितियों के अनुसार पाया जिन्हें स्वीकार किया गया है। इन किटों का कुल मूल्य ₹0 10,30,288.88 था। यह फण्डज भारत सरकार द्वारा एक हैल्थ गार्डन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को दिया गया था और इसका प्रयोग 31.3.83 तक किया जाना आवश्यक था इसलिए यह राशि तत्सदीक भुदा बिलों के आधार पर खजाने से निकालवा ली गई परन्तु वास्तव में फर्मों को इस राशि की अदायगी 28.4.83 को की गई थी। जब फर्मों ने सारा माल सभी सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पहुंचा दिया था।

7. एक आयुर्वेदिक औषधियों की किट में 24 दवाईयां होती हैं जिनमें जाति पलादी गुटी तथा करपूरस भी शामिल हैं दर संविदा के साथ आई हुई फर्मों ने अपनी निविदाओं के साथ जो नमूने प्रस्तुत किए उनमें पाई गई उपरोक्त वर्णित दो दवाईयां को गवर्नमैट ऐनालिस्ट हरियाणा से विनिश्चय करवाया गया था। तकनीकी समिति द्वारा यह दोनों निविदाओं इन टैस्ट रिपोर्ट के आधार पर विनिश्चितियों के अनुसार पाई गई। यह किटें आयुर्वेदिक विशेषज्ञों द्वारा पूर्ण निरीक्षण के पश्चात ही खरीदी गई थी। और यह कहना बिल्कुल निःसार है कि निम्न स्तर की दवाईयां सरकार द्वारा खरीदी गई है। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री किताब: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि मै० जन कल्याण आयुर्वेदिक फार्मसी हरिद्वार मै० अतरी आयुर्वेदिक फार्मसी बेरूतमै० संजीवनी रिसर्च लैबोरेट्री गोहानामै० भारत आयुर्वेदिक फार्मसी अमृतसर की औशधियां ठीक नहीं पाई गई । क्या मंत्री महोदय बताएंगी कि इन चार फर्मों की औशधियों के अलावा दूसरी फर्मों की औशधियों ट्रैस्ट क्यों नहीं करवाई गई? दूसरे ऊंचे रेट पर दवाईयां क्यों खरीदी गई? इसके साथ ही साथ यह भी बतायें कि यह दवाईयां किस लैबोरेटरी में किस तारीख को टैस्ट हुई और उसकी रिपोर्ट क्या है ।

श्रीमती भाकुतला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय जिन् अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। अगर वे चाहते हैं तो मैं उनके नाम बता देती हूँ इसमें विभाग के टैक्नीकल वि शैक्षण उद्योग विभाग के वि शैक्षण मैडिकल कालेज के वि शैक्षण ओर आई एस आई के वि शैक्षण थे। जहां भी आव यकता होती है। हम इन वि शैक्षणों को बुलाते हैं जहां पद सैम्पल आदि की बात हो वहां चौकसी विभाग के पुलिस उप अधीक्षक भी भाग लेते हैं। एक किट में 24 सैम्पल होते हैं ओर गोहाना वाली फर्म के 24 में से 16 सैम्पल ठीक नहीं पाए गए थे। यदि किट में दो सैम्पल भी खराब हो तो उसे वि शैक्षण मानते नहीं हैं।

श्रीकिताब सिंह: स्पीकर साहब, मैंने यह भी पूछा था कि यह दवाईयां किस लैबोरेटरी में टैस्ट करवाई गई थी ओर उसकी रिपोर्ट क्या है?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, ये ऐसी दवाइयां हैं जिनको चख कर या सूघ कर टैस्ट करते हैं। आयुर्वेदिक की दवाइयां को चैक करने के लिए हमने 18 आदमियों की टीम बुलाई जिनमें काबिल हकीम ओर वैद्य भी थे। इन्होंने कहा कि हमने कम पैसों वाली दवाई क्यों नहीं खरीदी? उसका कारण यह था कि जिन फर्मों के रेट कम थे उनकी दवाइयां पास नहीं हुईं वि. शेषों ने चार मीटिंगें की। वे अलग अलग से चख करके बताते हैं। कि दवाइयां में हर चीज की मिकसदार ठीक है या नहीं? दवाई सही है। या नहीं। उन्होंने कह दिया कि ये दवाइयां ठीक नहीं हैं। इसीलिये हमने उन फर्मों से दवाइयां न लेकर दूसरों से 62.60 रूपये के हिसाब से ली। यह दवाइयां का मामला है। अगर ठीक दवाई न हो तो उसे लेने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री किताब सिंह: स्पीकर साहब, यह भी बताएं कि किस लैबोरेटरी में दवाइयां चैक करवाई गईं ओर उनकी रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती भाकुतला भगावडिया: यह दवाइयां स्टेट ड्रग लैबोरेटरी चण्डीगड में टैस्ट करवाई थी।

श्रीकिताब सिंह: उस लैबोरेटरी की रिपोर्ट तो दिखा दे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये हमारे आफिस में आ जाये वहां इनको रिपोर्ट दिखा देगे।

श्रीकिताब सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इन दवाइयां की चख कर या सूंघ कर देखते हैं क्या चख कर मुआवना हो जाता है।

चौधरी भजनलाल:अध्यक्ष महोदय, मैंने जातिपलादी घूटी तथा कपूर रस के बारे में कहा था इनको टैक्नीकल कमेटी ने भी रिजैक्ट कर दिया ओर लेबोरेटी ने भी रिजैक्ट कर दिया।

श्रीमती भाकुतला भगवाडिया: स्पीकर साहब, इस काम के लिए 8 वैद्य बुलाए गए थे ओर वे स्वास्थ्य विभाग के माने हुए वैद्य है। आयुर्वेदिक की कुछ दवाईयां ऐसी होती है जिनमें अफीम की कुछ मात्रा शामिल होती है। वैद्य यह चैक करते हैं कि वह मात्रा सही है। या नहीं। उन वैद्यों के नाम डा० आर०एस० जैन, सत्य पाल भार्मा, सतय बीर, बलदेव सिंह—

श्रीकिताब सिंह: स्पीकर साहब, नाम तो मैंने पूछे ही नहीं थे। मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जो जो दवाईयां खरीदी गईं क्या उनमें अफीम वगैरह की मात्रा सही निकली?

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कहा है कि अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इनके आफिस में देख लें।

श्रीमती भाकुतला भगवाडिया: तकनीकी कमेटी में जो विशेषज्ञ बैठते हैं वह इस चीज की जांच करते हैं कि दवाई स्वास्थ्य के लिए कितनी फायदेमंद है। ओर कितनी नुकसानदायक

हैं यदि कोई दवाई नुकसानदायक होती है। तो वह पास नहीं करते चाहे वह दवाई कितनी ही सस्ती हो।

वर्ष 1984.85 के बजट की डिमांडज फार गांटस पर चर्चा
तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान अब वर्ष 1984.85 के बजट की डिमांडज फार गांटस पर डिसकूट होगी।

पहली प्रैक्टिस के मुताबिक ओर हाउस का टाईम बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज एक साथ पढी तथा मूव की गई समझी जायेगी। आनरेबल मैम्बर किसी भी डिमांड पर बोल सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

That a sum not exceeding Rs. 11,51,46430 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No. 2- General Administration.**

That a sum not exceeding Rs. 38,5060,795 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No. 3- Home.**

That a sum not exceeding Rs1,18,11,42,365 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges

that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.9 -Education.**

That a sum not exceeding Rs. 88,69,82,850 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No. 10- Medical And Public Health.**

That a sum not exceeding Rs. 7,73,93,280 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No16- Industries.**

That a sum not exceeding Rs. 15,69,57,765 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No. 20- Forest.**

That a sum not exceeding Rs. 78,27,43,200 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No. 23-Transport.**

That a sum not exceeding Rs. 72,00,290 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No1- Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. 40,85,64,25 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges

that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No. 5-Excise and Taxation.**

That a sum not exceeding Rs. 179519080 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No. 6 Finance.**

That a sum not exceeding Rs. 201159425 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No. 7-Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. 27840620 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No. 11- Urban Development.**

That a sum not exceeding Rs. 67303915 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No. 12- Labour and Employment.**

That a sum not exceeding Rs. 156418215 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No. 13- Social welfare and Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. 20552440 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No. 14 Food and Supplies.**

That a sum not exceeding Rs. 22445380 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No. 19- Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. 9392175 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No.24 Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 1225063500 for revenue expenditure be granted to the Government to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges **under Demand No. 25 Loans and Advances by State Government.**

श्री ओम प्रकाश महाजन(हिसार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 3,9,5 ओर 12 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर 3 के बारे में कहना चाहूंगा कि जो कि होम डिपार्टमेंट के बारे में है। अध्यक्ष महोदय आप भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे पड़ोस में गुरुयों की धरती पर पंजाब राज्य बसता है। वह बलिदानियों की भूमि है। जिसका कण कण हमारे लिए पवित्र ओर पूजनीय है। आज इस धरती को दूषित करने के लिए कुछ नासमझ लोग किन्हीं निहित

स्वार्थों के कारण ऐसा ाडयन्त्र रच रहे है। जिसके कारण भाई भाई मे नफरत की दीवार खडी हो रही है। पंजाब पिछले दो सालों से एक जवालामुखी बन कर खडा हुआ है आरे उसकी लपटें चारों ओर फैल रहीं है इसी जवालामुखी के धुएं ने हरियाणा के अन्दर भी अपना लकीरें छोडी है। एक बार तो ऐसा एहसास हुआ था कि भायद सारा हरियाणा ही जल उठेगा। लेकिन मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं ओर खास करके अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हू जिन्हानें निहायत सूझबूझ के साथ आतंकवादियों पर इस प्रकार का अकुं ा लगाया हैं मैं यही कह सकता हूं कि यह एक चमत्कार हो गया। चमत्कार ऐसा हो गया जैसे एक बिजली का बटन दबाने से एक बडी भारी म िन चलते हुए भांत हो जाती हैं उसी तरह का भान्त वातावरण आज हरियाणा के अन्दर है। यह श्रेय जिस व्यक्ति को जाता हैं वह है हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी भजनलाल जी क्योकि जनता के दिलों को जिस आदमी ने जीत रखा हो उसकी बाणी में इतना सामर्थ हो जाता हैं कि वह व्यक्ति जो भी बातें लोगों से कहेगा उसी बात को लोग तरुत मानेगे। मैं ये भाब्द केवल प्रंस ा के लिए ही नहीं कह रहा हूं और न ही मैं यह कह रहा हूं कि हरियाणा के अन्दर राम राजय आ गया है। ऐसा कहने से तो आति योक्ति होगी। रामराजय के अन्दर भी कुछ आलोचक थे मैं यह कह सकता हूं कि जिस बूझ के साथ हरियाणा सरकार ने इस सारे मामले को कन्ट्रोल किया उसके कारण ही हरियाणा के लोग सुख ओर भाति की सांस ले रहे है। आलोचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ वजन हो ओर दे ा व

प्रदेशों के हित में हो। उपाध्यक्ष महोदय, संसार में दो प्रकार की वृत्तियां देखने को मिलती हैं एक साकारात्मक और दूसरी नाकारात्मक। जैसे एक किलो भर वजन का लोटा हो और उसमें आधा किलो दुध हो। उसको देख कर एक व्यक्ति यह कहेगा कि अरे इसमें तो आधा तो लोटा खाली है। और दूसरा व्यक्ति यह कहेगा कि आधा लोटा दुध भरा है। उपाध्यक्ष महोदय, लोटे में दुध उतना ही है और लोटा भी वही है। लेकिन एक व्यक्ति ने उसमें कमी निकाल दी और दूसरे ने उसमें सन्तोश मान लिया। मैं यह कह सकता हूँ कि जिस देशभक्ति का सबूत हरियाणा के मुख्य मंत्री जी ने दिया है वह बहुत सराहनीय है उनकी हर सांस देश और प्रदेशों के हित की बात कह रही है। इसलिये मैं उनको दाद दिये बिना नहीं रह सकता। उन्होंने हरियाणा के हितों के लिए चाहे वह एस वाई एल नहर का मामला है। चाहे चण्डीगड का ओर अमृतसर फाजिल्का का मामला है उन मामलों में हरियाणा के केस को बहुत मजबूती के साथ सैन्टर के सामने रखा है। उन्होंने कभी कमजोरी नहीं दिखाई इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि हरियाणा सरकार के हित आज सरकार के हाथों में सुरक्षित है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 5 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह डिमांड एक्साइज एंड टैक्सों के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भाक नहीं है कि सरकार टैक्स लगाती है। ओर टैक्स इसलिये लगाये जाते हैं। क्योंकि उस पैसे से कमजोर ओर गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाता है। लेकिन टैक्स लगाते समय सरकार को इस

बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वे टैक्स कहीं जनता को भ्रष्टाचार की ओर न ले जाये और हमारे हरियाणा प्रान्त के अन्दर पाप न पनपे। हमारे हरियाणा के अन्दर कुछ ऐसे व्यापारी हैं। जो बिजली का काम करते हैं। उन पर चुंगी की दर दो प्रकार से लगाई जाती है। कुछ चीजों पर वजन के हिसाब से और कुछ चीजों की कीमत पर 4 परसेंट दर लगाई जाती है। इस तरह टैक्स दर लगाने से यह होता है कि जब कोई व्यापारी 10 नग बिजली के सामान के लाता है तो कमेटी का आकट्राय क्लर्क या इन्सपैक्टर उस भारीक आदमी के सामान को सरेबाजार खुलवा कर देखते हैं। ऐसा करके वह अपना ओर उस भारीक व्यापारी का वक्त बर्बाद करते हैं। वह भारीक आदमी इस तरह से अपनी काफी बेंडिज्जती महुसस करता है। आकट्राय क्लर्क ओर इन्सपैक्टर उसका सामान इसलिये देखते हैं कि कहीं उसमें चार परसेंट टैक्स की दर का सामान ता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज इस जमाने में जब इस प्रकार के कानून लागू हो तो उस महकमें के कर्मचारी ओर व्यापारियों के बीच में भ्रष्टाचार जाग उठता है। इसके सरकार को तो नुकसान होता है ही इसके साथ साथ व्यक्तियों का चरित्र भी ना होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से पुरजोर अपील है। कि वह ऐसे टैक्स लगाए जिससे भ्रष्टाचार न पनपे ओर एक जैसे सामान के लिए टैक्स की दर एक जैसी हो। मैं यह भी कहना चाहुगा कि सरकार हरियाणा के अन्दर पडोसी प्रदेस पंजाब ओर दिल्ली से ज्यादा टैक्स न लगाए जिससे हरियाणा का व्यापार प्रभावित न हो। उपाध्यक्ष

महोदय, इस बारे में मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ आजकल हजारों की संख्या में जो लोग टीवी खरीदते हैं वह ऐसा करते हैं कि दिल्ली में एक आदमी के नाम से बिल बनवा लेते हैं। हरियाणा में एक टीवी खरीदने पर उसे 200-250 रुपये फालतू देने पड़ते हैं। टीवी खरीदने वाले लोगों द्वारा इस तरह से दिल्ली में बिल बनवाकर हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपये का टैक्स कम आता है। हरियाणा के लगभग 80 परसेंट टीवी के बिल दिल्ली से कटते हैं। यदि सरकार हरियाणा में टैक्स कम कर दे तो सारे के सारे लोग हरियाणा से ही टीवी खरीदे और सरकार के खजाने में काफी आमदनी हो सकती है।

इस के अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 9 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। यह डिमांड एजुकेशन के बारे में है। सरकार ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि हम बच्चों को अध्यापिका शिक्षा देने का प्रबन्ध कर रहे हैं। जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा उठे। स्कूलों में इस तरह की शिक्षा देने के लिए दो पीरियड लगाने की बात है यह बहुत ही अच्छी बात है। इस संबंध में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो बच्चे बीए या एमए करके कालेज से निकलते हैं उनके मन में एक ही बात रहती है कि उनको नौकरी मिल जाये लेकिन सभी लड़कों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाती है। इस बारे में मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि सरकार कुछ सोच विचार करे और स्कूलों तथा कालेजों में टेक्नीकल शिक्षा दे ताकि स्कूल या कालेज छोड़ने के

बाद उसको यह समझ आ जाये कि वे अब काम करने के लिए तैयार है। यदि कोई लडका स्कूल या कालेज से ही अपने धंधों में निपुण हो जायेगा तो उसको नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। ओर वह अपना ही धंधा कर लेगा। इस प्रकार सरकार की सरदरद्री भी कम हो जायेगी ओर लडके सडकों पर दर दर की ठोकरें नहीं खायेगे। इससे उनके माता पिता जिन्होंने उन की पढाई पर खुन पसीने की कमाई लगाई है उनकी आत्मा ठण्डी होगी। इस बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई विचार करे और चार पांच आदमियों की कोई टीम मुकर्रर करे जो ऐसी योजना बनाए जिससे बेकारी का मसला हल हो ओर लडको को एजुकेशन ठीक ढंग से मिले। डिप्टी स्पीकर साहब, इस विशय पर मैं एक ओर बात कहने जा रहा हूं भायद वह कईयों को कडवी लेगे। लेकिन मुझे सच बोलने में न तो आज तक मेरे मां बाप ने मुझे रोका ओर न ही मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा दी गयी है। हरियाणा के अन्दर हजारों ऐसे आदमी है। जिनका ठीक प्रकार से गुजारा हो रहा है। हरियाणा के अन्दर ये लोग कितने है यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हिसार के अन्दर ऐसे केसिज है कि पति बहुत बडा व्यापारी है। बडा उद्योगपति है उसे हर महीने 20-25 हजार रूपये की आमदनी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ उसकी पत्नी भी 1400 रूपये 1500 रूपये पर टीचर या ओर पदों पर लगी हुई ह। मैं यह नहीं कह रहा कि दोनों क्यो कमा रहे है? इस संबंध मे मेरा सरकार को सुझाव है कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जाये

जिससे गरीब आदमी या जो एम ए पास लडका बेरोजगार घुम रहा है। उसको रोजगार मिल जाये।

श्री उपाध्यक्ष: आप जल्दी खत्म कर ले क्योंकि आपका समय खत्म हो रहा है।

श्रीओम प्रकाश महाजन: ठीक हैं जी। जो बात मैं कह रहा हूँ वह मेरी व्यक्तिगत बात है मेरा अपना सुझाव है एक तरफ तो भगवान की दया से ऐसे परिवारों के पास सब कुछ है ओर दूसरी तरफ हजारों की तादाद में लोग नौकरियों के घूम रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे दोनों को नौकरी न करनी पड़े। अब मैं समाज कल्याण की बात करता हूँ। समाज कल्याण विभाग के जरिये बहुत ही विधवाओं को पेंशन दी जा रही है। यह बहुत अच्छी बात है ऐसी विधवाओं की बहबूदी के लिये सरकार ने आश्रम भी खोले हुए हैं। लेकिन फिर भी इस काम में काफी कमी है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार को हर जिला स्तर पर ऐसा कोई प्रावधान करना चाहिए जिससे ऐसे कालेजिज चण्डीगढ़ में न आए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही डोल हो जाये। कई ऐसे केसिज होते कि चण्डीगढ़ रूलिंग पार्टी का एम0 एल0 ए0 है। इन को पता होता है। इस संबंध में मेरी प्रार्थना है कि सरकार हर जिला स्तर पर ऐसा कोई प्रावधान करे जिससे उन्हें तत्काल सुविधा मिल सके। ओर वे अपना जीवन सुधार सकें। इतना कहते हुए ओर डिमांडों का समर्थन करते हुआ अपना स्थान लेता हूँ।

श्री हरिचन्द हुड्डा (किलाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले डिमांड नं 16 पर जो इण्डीस्टीज से संबंध रखती है। बोलना चाहता हूँ। इस मांग के तहत सरकार सदन से 3 करोड़ 16 लाख रुपये के करीब पैसा मांग रही है। आज यदि कोई डैम बनाया जाये तो उस पर 700-800 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। ओर यदि कोई बांध बनाया जाये तो उस पर 10-12 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यहां पर इन्होंने इण्डीस्टीज की मांग तो रख दी लेकिन इन्हे यह पता नहीं है। कि इण्डीस्टीज तो दे 1 का जीवन है। ये दे 1 के जीवन को सिर्फ 3 करोड़ रुपया ही दे कर इण्डीस्टीज की डिवाल्पमेंट करना चाहते हैं। आज सारे हरियाणा में अन-एम्पलायमेंट की प्रॉब्लम है। आज सारे दे 1 में दुःख का वातावरण फैला हुआ है। इण्डीस्टीज की तो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया जा रहा था। जबकि यहां पर न जाने कितने तीन करोड़ के सकैण्डल हो जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं जनरल बातों पर आ रहा हूँ। यह मांग वह मांग नहीं जिससे लोकतंत्र की खुा ाबू आती है। यह वह मांग है। जिससे नोअतंत्र की बदबु आती है। डिप्टी स्पीकर साहब, इससे ओग मैं कहना चाहता हूँ कि मक्कार की चालों से बाजी ले गया सरमाइदार। इन्तहाए सादगी से खा गया मजदूर मात। अब हाउस के सामने ये डिमोडे बजट मे से बचचों की तरह निकलती है। आज फीडिज्म मे इस दे 1 को धोखा दिया जा रहा है। मैं। यह कहना चाहता हूँ कि जो मांगे निकाली गई है। इनका डिस्टीब्यू ान ठीक नहीं हुआ है। अगर बजट को ठीक डिस्टीब्यू ान होती तो दे 1 के अन्दर न

अन-एम्पलायमैट होता न बेराजगारी होती न भुखमरी होती ओर न ही क्र० न पैदा होती।

चौधरी भामेरी सिंह सुरजेवाला: हुड्डा साहब तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वे भिवानी स्टेण्ड पर बोल रहे हों न कि उसैम्बली में।

श्री हरिचन्द हुड्डा: यहाँ पर क्र० न है भूख है ओर गन्दगी। मुझे भिवानी स्टेण्ड पर ही बोलते हुए आप समझ लें। मैं जनता में जाता हूँ जनता मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं सिद्धांत की बात कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: असैम्बली वाली बात को एक्सपंज कर दिया जाये।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी हुड्डा साहब ने कहा है कि वे जनता में जा रहे हैं। यह देख लें कि अब इनकी सीट वहाँ के लिए चेन्ज करनी पड़ेगी।

श्री हरिचन्द हुड्डा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो ऐसा बीज हूँ कि यदि इस बीज को इस्तेमाल कर लिया जाये तो सारा देश ऊपर उभर जायेगा। मैं यहीं रहूंगा की नहीं जाऊंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, सिद्धांत की बात यह है कि सारा देश या सारी दुनिया के लोग ऊपर उठें। यह तभी हो सकता है जब धरती की पैदावार बढ़ेगी। जब पैदावार बढ़ेगी। तो देश की इन्डस्ट्रीज भी बढ़ेगी जिससे किसी देश की रोजी रोटी

का मसला हल होगा। इससे बेकारी भुखमरी नहीं होगी। आज सरकार की 34 साल से चली आ रही नीति ओर नीयत से सारा काम खराब हुआ है। आज हिन्दुस्तान के किसान को जिन्दा मार दिया जा रहा है। अमेरिका से गेंहू मगा कर यहां के किसान को बेकार कर दिया है। इस सरकार को अपनी नीति ओर नीयत को बदलना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमारी पैदावार नहीं बढ़ेगी तो रोजी रोटी का मसला हल नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: कुश्ट वाली बात एक्सपंज कर दी जाये।

श्री हरिचन्द हुडडा: सरकार ने बड़े बड़े कारखाने लगा कर अपनी पैदावार को ओर किसानों की पैदावार को नीचे ला दिया है। यदि किसान से पैदावार लेते तो सारे देश का मसला हल हो जाता। जहां तक इंडस्टीज का सवाल है इस बारे में मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि यहां पर जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज ने यहां की मलमल को उजाड कर दिया था। इसी प्रकार इस सरकार ने धानक चमार ओर कुम्हार के घर को उजाड दिया है। गांवों में जो गरीब लोग काम करते हैं। उनके काम को उजाड दिया। आपको मालूम है ढाका की मलमल सारे हिन्दुस्तान में मालूम हैं यह गवां के गरीब लोग बनाते हैं। आज यह काम बड़े बड़े इंडास्ट्रियलिस्ट्स ने सम्भल लिया है। जो काम हमारे दादा पडदादा करते थे जिस काम को गांव के अनपढ़े लडके करते थे बिना पढ़े लिखे एक्सपर्ट बनकर पीएच डी की डिग्री लेते थे। अब वे बेकार हैं। जो इंडस्टीज लगाते हैं। किसी को 3 करोड़ रुपया दे

दिया किसी को दो करोड़ दे दिया ये इंडस्टीज उस वजह पैसे को खा जाती है। एक इंडस्टी मारुति है यह इंडस्टी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह बात रिकार्ड न की जाये।

श्री हरिचन्द हुड्डा: बे तक निकाल दीजिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि घानक जिनका घर में कपडा बुनने का काम था। ओर नोजवान लडके घर बैठे अपनी रोटी कमाते थे। पिछले चालीस साल से जो काम ये कर रहे थे सरकार इनके काम को इनके घर से निकाल कर ले गई ओर ये घर पर आज रोटी के लिए परे गान है। इसी तरह जुती बनाने वाले चमार पिछले 40 साल से बडे आराम से जुती बनाकर रोटी रोजी कमा रहे खाते थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करते थे। उनका रोजगार छीन कर उनको घर से निकाल दिया गया है। इस सारे काम को इंडस्टीयलिस्ट्स ने सम्भाल लिया है। इस तरह इंडस्टीयलिस्ट्स को बचाने के लिए इन गरीबो को बरबाद कर दिया है। (चौधरी भले राम जी की तरफ से विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, भले राम जी चमार है लेकिन ये खुद चमार नहीं बनना चाहते है। मै चमार बनना चाहता हूं मै तो कहता हूं कि मुझे चमार बनाकर श्री भले राम जी को कांस्टीच्युएसी में भेज दो ताकि मै वहां पर सारी जिन्दगी भर एम0 एल0 ए0 बनता रहू। इसकी कांस्टीच्युएसी वाले इससे इतने रूश्ट है कि इस बार इसका पता तो वे साफ कर देंगे डिप्टी स्पीकर साहब, मै कह रहा था कि आज सरकार बडी बडी इंडस्टीज की तरफ ध्यान दे रही हैं अगर

गांव की इंडस्टीज की तरफ ध्यान दे तो सारे हिन्दुस्तान के लोगों की हालत अच्छी हो सकती है। ओर हर गरीब आदमी अपने घर में बैठ कर आराम से रोटी कमा सकता है। लेकिन इस सरकार ने देहात से सारी इंडस्टीज निकाल ली ओर उसको टाटा एंड बिरला खा गया।

श्री भले राम:..... ।

श्री हरिचन्द:..... ।

श्री उपाध्यक्ष: पर्सनल चार्जिज अगर किसी के खिलाफ कहे जाये तो वे रिकार्ड न किए जाये। आपका टाईम हो गया है। आप वाइड अर्प करे।

श्री हरिचन्द हुडडा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अब दो मिनट ही लुगा। मेरा एक सुझाव है मारकंडा बैरेज 5700 एकड़ जमीन को सैराब करता है। (व्यवधान) 7 करोड़रूप्या लगाकर सिर्फ 5700 एकड़ जमीन को सैराब किया जाता है। मेरे इलाके में एक छोटा सो डैम है। इस पर एक लाख रूपया लगा रहे है। पिछली दफा यह डैम बनाया था ओर तीन करोड हजार एकड जमीन सेराब करती है। मारकंडा बैरेज पर आप 7 करोड रूपया लगा रहे है। लेकिन इस डैम पर बहुत कम पैसा लगेगा। करोडों में नही हजारों में ही खर्च होगा। इस की तरफ सरकार थोडा सा ध्यान दे। इस का काम बहुत कम रूपय में हो सकता है। जहां तक इंडस्टीज लगाने का सवाल है इंडस्टीज का नाम लेकर सरकार को

हरियाणा के लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जहां तक पानी का सवाल है ल एस वाई एल पा पानी आया ओर न ही झाकडी का प्रोजैक्ट बन गया। एस वाई एल पर 20 करोड रूप्या बरबाद हो गया लेकिन पानी नही ले सके। एस वाई एल का नाम लेकर सरकार किसान के साथ धोखा कर रहीं है। पिछले दस साल से इसकी यही पोजी तन हैं इन्होंने एस वाई एल को ओर नाथपा झाकटी प्रोजैक्ट को पुलिटिकल इ ़ु बना कर रख दिया है। यही कारण है कि यह नहर नहीं बन पर रहीं है। सरकार किसानों को मजदूरों को धोखा दे रहीं है। इस लिए यह सरकार हैं मै। सरकार को साउड करना चाहता था । कर दिया । धन्यवाद ।

श्रीमती भारदा रानी (बल्लभगढ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आज आपने कितने कई दिनों के बाद बोलने का मौका दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने बजट की कुछ मांगें पास करने के लिए आई हैं वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण मांगे थी। उनके ऊपर कल डिस्क तन हो चुका हैं लेकिन राज्य की कोई भी मांग हो वह दूसरी मांगों के साथ संबंधित रहती है। एक बजट तक दूसरे बजट पर एक क्षेत्र की गरीबी के ऊपर हमें ता असर पडता है। इस लिए मै सोचती हूं कि हम सब बातों पर इन मांगों पर बोलते हुए डिस्क तन कर सकते है। जहां तक मांगों का ओर बजट का प्र न है। हमें यह देख कर खु ़ी हुई है। कि जो प्रायरिटी

सैक्टर है। सिचाई का बिजली का इन सैक्टर के लिए बजट में काफी अच्छा प्रावधान है ग्रामीण इलाकों की हालत सुधारने के लिए बजट में काफी अच्छा प्रावधान किया है और सब से बड़ी खुशी की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी अधिक ध्यान दे रही है। जहां तक सिचाई और बिजली के प्रायोरिटी सैक्टर का ताल्लुक है इनको भारत सरकार ने 20 सुत्री कार्यक्रम के अन्दर पहले ही महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना पड़ेगा कि जो बजट इन कामों के लिए निर्धारित किया जाता है उसको अगर उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाये। बजट का सही ओर पूरा इस्तेमाल है सतुलित इस्तेमाल हो तो यह बजट हरियाणा स्टेट को बहुत अधिक फायदा दे सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां सिचाई और बिजली वगैरहा की मांग है। वहां उद्योगों की मांग भी आई है। फरीदाबाद बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन इस के विकास में सब से बड़ी कमी जो आ रही है। वह बिजली की वही से आ रही है। वहां बहुत सारे उद्योग बिजली की कमी के कारण ठपे पडे है। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि छोटी इंडस्ट्री लगाने वाले नौजवान को 25000 रूपये ग्रांट के रूप में दिये जायेगे। इस रूपये को लेने की बहुत ही कन्डीशन होती है। जिनकी वजह बहुत ही कम लोगों को पैसा दिया जा सकता है। एक उद्योग को चलाने के लिए पूरा पैसा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को 25000 रूपये की जरूरत होती है। ओर उसको केवल 5000 रूपया दे

दिया जाता है। तो इससे उसका कार्य सफल नहीं होता। आप चाहे थोड़े लोगों को पैसा दे लेकिन कम से कम इतना पैसा जरूर दिया जायें जिससे वे किसी न किसी काम की स्थापना कर सकें। कहीं ऐसा न हो कि सारा पैसा बरबाद चला जाये और वे कर्ज से दब जायें। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है। कि अगर बिजली और पानी के वितरण की व्यवस्था सही हो जाये तो उद्योगों की व्यवस्था भी ठीक होगी। आज कोई भी उद्योग ऐसा नहीं है जिसमें बिजली की आवयकता नहीं है। जो उद्योग गावों में लगाये जाते हैं उन में ग्रामीण लोग न डीजल इंजन लगा सकते हैं। और न ही उद्योग वाले जनरेटर ही लगा सकते हैं। इसलिए उनके लिए यह नितान्त आवयक है। कि बिजली का वितरण अच्छी तरह से किया जाये। और बिजली ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जाये। इसके लिए चाहे हमें भारत सरकार से प्रार्थना करनी पड़े चाहे दूसरी स्टेट से प्रार्थना करनी पड़े कुछ भी करना पड़े हमें इस काम को वार फुटिंग पर चलाना है। हमें चाहिए कि हम चारों ओर अपने टैक्नोक्रेट्स भेज कर हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी के रिसोर्सिज को एक्सप्लायट करे ताकि हरियाणा सरकार से ज्यादा बिजली उपलब्ध करवाई जा सके है। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के अन्दर आप जानते हैं। कि थर्मल युनिट्स हैं लेकिन उनके पास कुछ जगह कम है। उनसे जो मलबा निकलता है उसको डालने के लिए उनके पास कुछ जगह कम है। अच्छा होता यदि इस प्लान के अन्दर फरीदाबाद में एक ओर थर्मल युनिट जमुना के किनारे या नहीं ओर जगह जहां ठीक समझा जाता लगाने का प्रावधान किया

जाता । यदि यह प्रावधान अब भी कर लिया जाये तो बहुत अच्छा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बात अब मैं कहने जा रही हूँ इसे मैंने कई बार इरीगेसन एंड पावर मिनिस्टर साहब से कहा है और यह कोई टालने वाली बात नहीं है । यह कहकर कि अब इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह तो पुराने एग्रीमेंट है हमारी सरकार को तो इस और वि. शेष तौर पर ध्यान देना चाहिए । भाखडा से डेगू को बिजली जाती है । भाखडा में डेसू का हिस्सा नहीं आता लेकिन फिर भी इसे बिजली दी जाती है । स्वाभाविक है वह बिजली दूसरी स्टेट्स के हिस्से की है । जिसमें हरियाणा भी शामिल है बिजली डेसू को दी जानी चाहिए क्योंकि दिल्ली हमारे देश की भान है । दिल है और राजधानी है । यह भी ठीक है । कि उसे अन-इंट्रिडिक्ट सप्लाई होनी चाहिए । लेकिन यह नहीं होना है कि हरियाणा सरकार बिजली बोर्ड तो उसके हिस्से की बिजली न मिलने के कारण निरंतर घाटे में चलता रहे और डेसू के सब पदाधिकारी तथा चेयरमैन वगैरा पूरी भान और अकड से रहें ताकि कभी कोई घाटा नहीं होता । होगा भी कैसे? वह हमारी सस्ती हाइड्रो बिजली लेते है । और बदले में हमको इन्दपस्थ या बदरपुर से थर्मल प्लांट की महंगी बिजली देते है । इस बारे में भायद एक बार 1977 में हरियाणा सरकार की बात उपरी लेवल तक हुई थी यह ठीक है कि हमारी प्रधान मंत्री और सारा देश यह चाहता है कि दिल्ली के बिजली देने के लिए किसी

दूसरी स्टेट को हमारी प्रधानमंत्री जी की यह कोई मं 11 नहीं थी कि दिल्ली को बिजली देने के लिए किसी दूसरी स्टेट को नुकसान उठाना पड़े। इसलिये अगर हमारी सरकार सारी बारीकियों की छानबीन कर के इस बात को भारत सरकार के सामने रख तो हरियाणा के बिजली बोर्ड को काफी फायदा हो सकता है

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का जो फ्लैट रेट सिस्टम चालू किया गया है। मैं नहीं समझती कि इस से लोगों के साथ न्याय होता हो। कुछ लोग कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनके उपर पुरा बोझ पड़ जाता है और जो लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके उपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप घाटा बोर्ड को उठाना पड़ता है। इस घाटे की वजह से बोर्ड के पास न खम्भे होते हैं। न ट्रांसफार्मर होते हैं न बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। न ही छोटे पुर्जे और तारे आदि होती हैं। जिसके कारण बिजली की सप्लाय निरन्तर रूप से नहीं चलती है इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हर क्षेत्र में बिजली के सामान की मांगों की तरफ अगर पूरी तरह से ओर तुरन्त ध्यान दिया जाये तो सारे हरियाणा में खु 1हाली आ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि अगर नहरों से सिंचाई के लिए पूरा पानी मिल जाये तो उद्योगों के लिए बिजली की बचत हो सकती है। हम खु 1 हुए थे कि फरीदाबाद के अन्दर 100 एम0 आई0 टी0 सी0 के

ट्यूबवैल्वज लगने वाले है। वे लगे भी लेकिन साथ ही एक ओगमैन्टेसन कैनल बना दी गई ओर वह सारा पानी निकाल कर के दूसरे क्षेत्र मे डाल दिया गया। नरवाना ब्रांच से जमुना में से हो कर आगरा कैनल के जरिए जो पानी मिलता था फरीदाबाद को वह कम कर दिया गया । सिवानी जुई ओर जवाहरलाल नेहरू कैनलज में पानी जा रहा है। लेकिन हमारे यह पानी बहुत कम जा रहा है। (ओर) मै गलत नहीं कह रही हूं। इस संबंध में सिचाई मंत्री जी ने आकंडे दिये है कि फलां फलां नहर में पहले इतना पानी चलता था। ओर अब इतना पानी चलता है। पानी की मात्रा जो इन्होने बताई वह काफी बढी हुइ है। एस वाई एल का पानी या ओर पानी जो हरियाणा को मिलता है। उस का प्रपो र्नेट हिस्सा हमारे इलाके को भी मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, वह एरिया बहुत ज्यादा बारानी है। लोगों ने पानी की भावल नहीं देखी है। उस एरिया को अब य पानी मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक हैं कि हरियाणा के सूखे क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि किसी हरे भरे क्षेत्र को सुखा कर दिया जाये। आज ही आई पी एम साहब ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि बल्लभगढ में 3 से 5 फुंट तक पानी का स्टैटा नीचे गया है। लेकिन वह सिर्फ 3 से 5 फुट तक ही नीचे नही गया (विध्न) हम मोटी बात करते है। कि जिन कुओं में पहले 10-15 फुट पानीह खडा रहता था। वे अब सुखने लगे है। अतः हमारी दृशिट में पानी बहुत नीचा चला गया है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, जिन डिपार्टमेंट की डिमण्डज पर चर्चा चल रही है। उन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्ज को तो यहां प्रेजेंट रहना चाहिए (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: फाईनेस मिनिस्टर साहब बैठे हैं।

श्रीमती भारदा रानी: उपाध्यक्ष महादेय, मैं कह रही थी कि फरीदाबाद में 100 एम० आई० टी० सी० के ट्यूबवैल्ज लगाये गये लेकिन सारे के सारे पानी को दूसरी तरफ से जाया गया। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जितना पानी आज तक मिलता रहा है। उतना पानी अब य मिलता रहना चाहिए। इस के अलावा नया पानी आने पर दूसरे हिस्सों को जिस प्रपो र्शन से पानी मिले तो उसी प्रपो र्शन से फरीदाबाद के क्षेत्र को खास कर के आगरा कैनल के पूर्वी क्षेत्र को अधिक मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक क्षेत्र हैं ओर है जो बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। जिसे खादर को क्षेत्र कहते हैं। वहां पर 12 गांव हैं पहले तो उसे जहर नाला के उस पर कहते थे। लेकिन अब उसे जमुना के उस पार कहना चाहिए। क्योंकि वास्तव में अब जमुना जहर नाला न रह कर के जहर नाला पूरी जमुना हो गया है। उस की वजह से यह है कि यू पी० सरकार ने पूरी जमुना के किनारे किनारे बांध बना दिये हैं। ओर हमारी तरफ केवल स्पर्ज बनाए गए हैं आज उन स्पर्ज का भी नामोनि ान नहीं है क्योंकि

जमुना मे अब पानी आता है। तो सब स्पर्ज टुट जाते है। ओर जमुना के किनारे बसे हुए गावों में विकट स्थिति पैदा हो जाती है। उनकी आबादी फसल ओर कुएं का पानी आदि बरबाद हो जाते है। अगर यही स्थिति रही हो तो कुछ सालों के बाद उन गांवों का कुछ पता नहीं रहेगा। इस लिए उपाध्यक्ष महादेय, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बजट में और डिमांडज में उस क्षेत्र को प्रायरिटी मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि मुख्य मंत्री जीने हमारे पर जहर नाला के ऊपर एक लोहे का पुल बना दिया है। लेकिन वास्तव में वह सीजनल पुल है। बाद में इस पुल को हटाना पडेगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पक्के पुल की व्यवस्था की जाए। हमारा यह एरिया काले पानी की तरह है। वहां हस्पताल ता है। लेकिन डा0 नहीं जाता स्कूल हैं पर टीचर्ज नहीं जाता। बिजली की लाईन जब खराब हो जाती है। तो ठीक करने वाले नहीं जाते उस क्षेत्र के लोग एक तरह से आदिवासियों की तरह गुजारा करते है। अगर वहां पुल बन जाये तों वे लोग भी रोानी वाली दुनिया में आ जायेगे। अभी उन 12 गावों के लिए कुछ भी कार्य हमारी हरियाणा सरकार ने नहीं किया हैं कहा जाता है कि हरियाणा सरकार पहला प्रान्त है जहां सारे गांवो को सडको से जोड दिया है। लेकिन उस क्षेत्र के 12 गावों में से एक गांव भी सडक के साथ नहीं जोडा गया है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं पर्यटन विभाग के बारे में कहना चाहती हूँ कि इसमें रैवन्यू साईड में काफी पैसा रखा जाता है। कैपिटल साईड में भी इन्हें कुछ पैसा रखना चाहिए था। बल्लभगढ़ के अन्दर जी टी रोड पर एक बहुत अच्छा प्लायट है। वहाँ बस स्टैंड बनाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यटक केन्द्र बनने के वहाँ पोटैन्शियल भी मौजूद है। उसके लिए बजट में व्यवस्था होनी चाहिए। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, वह पर्यटक केन्द्र सरकार करनाल लेक के ओसिस की तरह सस्ता ओर सामान्य जन की पहुँच के भीतर होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सामान्य प्रशासन के बारे में भी कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों कुछ सर्विसिज के लिए सिलैक्सन हुआ अच्छी बात है। अगर जगहें खाली हो तो सिलैक्सन होनी चाहिए। लेकिन मुझे इस में एक रियलिकयत है लोग अपने बच्चों को पढाते हैं उनको कहते हैं कि मेहनत कराते है। ओर फर्स्ट डिविजन लाओ। रात दिन उन के साथ बैठ कर उन्हें मेहनत कराते हैं क्यों? किस बात के लिये? इसीलिये कि बच्चे यदि अच्छे लायक होंगे तो अच्छी जॉब्स पाएंगे लेकिन जब जॉब्स पाने की बात आती है तो उनकी क्वालिफिकेसन को महत्व नहीं दिया जाता। अभी पिछले दिनों नायब तहसीलदारों की सिलैक्सन हुई पहले तो हमें बता नहीं था लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में जब यहाँ जवाब आया तो उस में हम ने देख लिया। उपाध्यक्ष महोदय, अधिकतर नायब तहसीलदार जो सिलैक्ट हुए वे

थर्ड डिविजनर्ज है। अगर थर्ड डिवीजन सिलैक्ट किये है। तो गांव के फर्स्ट डिवीजनर्ज को क्यों छोड दिया गया। टैस्ट मे तो वे पास हुए हैं पता नहीं इन्टरव्यू मे किस आधार पर और कैसी परसनैलेटी देखते है। उन्हे छोड दिया गया।

प्रॉ० सम्पत सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। बहिन जी पर डबल भार हो रहीं है। एक तरफ इन कोमंत्री पद से हटा दिया गया है। योग्य मैम्बर होते हुए भी हटा दिया गया। साइड सर। सर्विसीज मे बडे डिवीसिनर्ज सिलैक्ट कर लिये ओर उनके हल्के के मैरिट वालों को सिलैक्ट नहीं किया गया।

श्रीमती भारदा रानी: मुझे आपकी सिफारि । नहीं चाहिए। मै अपने आप बात कर लूगी । मेरे कहने का मतलब यह है। कि इस से हमारे विद्याथियों में बडी भारी फस्ट्रेसन आयेगी। अगर फस्ट्रे इन रहेगी तो वे क्यों पढाई करेगे? कोई मां बाप अपने बच्चे से दिन रात इसलिए मेहनत कराता है। कि वह अच्छे नम्बर ले कर पास हो आरे कम्पीटिसन में आये लेकिन फर्स्ट डिवीजनर को छोड कर थर्ड डिवीजनर को सिलैक्ट कर लिया जाये तो समाज में फस्ट्रे इन आयेगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, सडके बनाने, रिपेयर करने ओर वाइडिंग के लिए बजट मे पैसा रखा जाता है। मान लीजिए दस लाख रूप्या इस काम के लिए मंजूर हैं तो वह सही टाईम पर मिलना चाहिए। लेकिन कभी पचास हजार ओर कभी एक लाख

रूपया दे दिया जाता है। जिससे पब्लिक पर अच्छा इम्प्रं इन नहीं पडता। अगर वह पैसा एक बार इक्टडा ही समय पर दे दिया जाये तो काम भी समय पर ही हो जाये। ओर गवर्नमैट की भी बचत हो जाये। दूसरे जो सडको के लिए अलाइमैट की जाती है। उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे सडक मे किसान की कम से कम जमीन आये। आज हरियाणा के किसानों के पास बहुत थोडी जमीन रह गई है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं ओर प्रार्थना करती हूं कि सरकार के नोटिस में जो बाते लाई गई है उन पर गौर किया जाये।

श्री निहाल सिंह(अटेली): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने समय दिया। मैंने जो अभी चिट लिख कर भेजी थी तुरन्त ही आपने समय दे दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, आज भुरु में सब से पहले श्री महाजन बोले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ला एंड आर्डर सिचुए इन खराब हो गई थी वहपूरी रफतार से ठीक हो रही है। जैसे बिजली का बटन दबा दिया जाये जा रोानी या अन्धेरा हो जाता हैं हरियाणा की ला एंड आर्डर की सिचुएसन क्यों बिगडी क्या कारणथे? पंजाब के हालात तो इतने खराब हो गये कि आज वे काबु से बाहर है। पंजाब में वहां की कांग्रेस पार्टी की सरकार फेल हो गई है वहां पर प्रेजीडेन्ट रूल भी फेल हो गया। ओर लोगों को जान माल ओर प्रोपर्टी महफूज नहीं रही। उसी का असर हरियाणा में हुआ।

मैं उसके लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार करार देता हूँ अगर सैन्ट्रल गवर्नमेंट सही वक्त पर कदम उठाती तो ये हालात न होते । (विघ्न) हमारा सीधा ला एंड आर्डर का ताल्लुक पंजाब से है । अगर पंजाब ओर हरियाणा के पानी ओर टैरेटरी के झगडे को सही वक्त पर सुलझा दिया जाता तो यह हालत न होती । सन् 1966 से यह बात चली आ रही है । कि क्यों इतना समय लगा । नतीजा यह हुआ है कि आज हालात फैसले किये गये लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया । नतीजा यह हुआ कि आज हालात इस लेबल पर पहुच गये जो काबू से बाहर है । हरियाणा मे जो कुछ हुआ उसके लिए हमारी सरकार ओर सैन्ट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है । मैंने उस वक्त कहा था कि हमारे सिख भाई जाते है उन्हें क्यों रोकते हो? पंजाब के बार्डर पर उन्हें क्यों नहीं रोका जाता है । दिल्ली के बार्डर पर क्यों रोका जाता है । पंजाब ओर दिल्ली ने सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी है । हमने ऐसे हालात पैदा कर दिये जैसे हमारा ओर पंजाब का बहुत भारी झगडा है इसी कारण से आज नौबत यहांतक पहुच गई है । कि हिन्दु ओर सिख के झगडे की एक भाक्ल अख्तियार कर ली है । आज हरियाणा में जिस तरह से दुकाने लूटी गई आदमी मारे गए तो सरकार ने कौन सा तरीका अख्तियार किया । जिससे ला एंड आर्डर की हालत सुधरे? क्या यही तरीका है कि इस झगडे को आग के बुझाने कि लिए पैट्रोल ओर डीजल का इस्तेमाल किया जाये? पंजाब में जो कुछ हो रहा है उनके साथ दे । का कोई भी आदमी नहीं है । यह बहुत निन्दनीय है वह रोका जा सकता था । लेकिन रोका नहीं

गया। आज हरियाणा में दुकाने लूटी गई हजारों रुपये का कपडा लूट कर ले गये। लेकिन पुलि वहां खडी खडी देखती रहीं। पुलिस ने कोई एक्सन नही लिया। प्रधान मंत्री को पालियामैट में यह मानना पडा कि हरियाणा की पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नही हुई। पुलिस को जितना एक्सन लेना चाहिए। था उतना नहीं लिया गया। अगर कहीं चोरी हो जाती हैं या लूट मार हो जाती है। तो माल बरामद किया जाता हैं लेकिन यहां पर लाखों रुपये का माल रेडियों में भर कर ले गए कोई माल बरामद नहीं किया गया है। मैं। हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं क्या आपने कोई कदम उठाया है कि इस माल को बरामद किया जाये। पंजाब में हिन्दु सिख का झगडा फैला। पंजाब में ही एकस्टीमिस्ट नहीं है। बल्कि यहां भी मौजूद है। वे लोगों को भडका कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं चौधरी भजन लाल पर आरोप लगाया हुआ कि यह कम्युनल है। चौधरी भजनलाल कम्युनल नहीं है। वह तो सीधा सा बिजनैसमैन हैं। उसे धर्म कर्म से क्या लेना है। अगर कोई फाईन्स की बात हो तो उसमें इन्ट्रैस्ट हो सकता है। लेकिन उन्हें कम्युनल कहना उचित नहीं। मैं नहीं मानता।हैं हरियाणा में ला एंड आर्डर की जो सिचुए ान खराब हुई है।
(विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: जो परसनल बात कही है वह रिकार्ड न की जाये।

Shri Nihal Singh: What is unparliamentary about it, Sir? There is nothing objectionable about it.

Mr. Deputy Speaker: It is certainly offensive.

Shri Nihal Singh: It is not at all an offensive remark.

Mr. Deputy Speaker: It is so.

12.00 बजे

श्री निहाल सिंह: अगर सैन्ट्रल गवर्नमैट चाहती तो ये दगें हो नही होते । सैन्ट्रल गवर्नमैट का मतलब था कि जहां पंजाब के हालात खराब है वहां हरियाणा के भी खराब हो । कहीं से भी आती है उसके साथ लगा देते है । कि पंजाब और हरियाणा में ला एंड आर्डर की सिचुएसन खराब है । अब हमें यह देखना है कि हरियाणा में ला आर्डर के हालात पंजाब के हालात से कैसे खराब हुऐ? उसके साथ हरियाणा को क्यों जोडना चाहते हैं? इसीलिये कि सैल्ट्रल वाले चाहते है । कि ये आपस में झगडे । दिल्ली वाले चाहते है । कि यह फैसलान हो । इसीलिये मैं सुझाव देता हूं कि यह मामला कैसे हल हो सकता हैं? पंजाब एंड हरियाणा का मसला हल नही हो सकता । आप जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार फेल हुई है । दिल्ली की सरकार का नुमायंदा भी पंजाब में भी फेल हुआ । जहां पर ऐसे हालात हो तो हरियाणा और पंजाब के हालातों को सुधारने के लिये मैं । यह सुझाव देता हू कि हमें पार्टी पार्लियामैट से ऊपर उठकर बात

करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार की ओर प्राईम मिनिस्टर को इस बात के लिये मनाना चाहिए। ओर कोई न कोई ठासे कदम उठाना चाहिये। जिस तरह से भोख अब्दुला की जेल से निकाल कर फिर उसे जम्मू क मीर का मुख्य मंत्री बनाया गया था उसी तरह से आज वहां भी इसी तरह से सरकार कायम करनी चाहिए। फिर न तो पानी का झगडा होगा ओर न हीं टैरीटरी का । यह तो पोलिटिकल झगडा है। पोलिटिकल झगडे को पोलिटिकल लैवल पर ही तय करना चाहिए। मेरा इस बारे में सुझाव है। कि पंजाब में जो सरकार कायम ही वह सत लोगावाल ओर अटल बिहारी वाजपेयी दोनो मिलकर बनाये। इन दोनों को ही इंदिरा गांधी को यह देना चाहिये कि आप सरकार बनाओ। जब यह सरकार बनायेगें तभी यह झगडा हल होगा। फिर कोई झगडा नहीं उठ सकता। मेरा कहना यह कि इनकी सता सौप दी जाये फिर हरियाणा का झगडा अपन आप हल हो जायेगा (व्यवधान) हरियाणा में जो मौजूदा हालत हैं हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेशन मे जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा की हिस्टरी मे आज से पहले केबिनेट नहीं रहीं है।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह भाब्द एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री निहाल सिंह:.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप ऐसी बातें पब्लिक मीटिंग में तो कह सकते हैं। लेकिन यहां पर नहीं। हमें रूलज के अनुसार चलना पड़ता है।

श्री निहाल सिंह:..... इसमें कौन सी ऐसी बात है जो अनपार्लियामेंटी है। ओर रिकार्ड में नहीं आ सकती?

श्री उपाध्यक्ष: अगर यह बात अनपार्लियामेंटी नहीं है तो दूसरी कोई बात अनपार्लियामेंटी नहीं हो सकती।

श्री निहाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर देखेंगे तो आप को यह पता चल जायेगा कि इसमें कोई अनपार्लियामेंटी भाव नहीं है। अगर किसी सरकार को इन एफ़ी गियैट कहा जाये तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप इन एफ़ी गियैट तो कह लो यह तो ठीक है।

श्री निहाल सिंह: मैं सब मिनिस्टर्स के बारे में तो नहीं कहता। इस कैबिनेट में कुछ अच्छे मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं। जिन्होंने सारी स्टेट में इस कैबिनेट को बदनाम किया हुआ है। आपने भी सुना होगा। आपके भी ध्यान में यह बात होगी कि इस सरकार के ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिन में भ्रष्टाचार की विकायतें हैं। पिछले साल मेरे पास ट्रांसफ़र्ज के बारे में काफी लोग आये थे। ये बताते हैं कि एक एक डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र्ज के लिये 14-14 ओर 15-15 लाख रुपये ट्रांसफ़र्ज के

लिये गये है। उनका नाम चीफ मिनिस्टर साहब भी जानते है नाम बताने की यहां जरूरत नहीं है। यदि जानना चाहे तो आम उनसे पुछ ले। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा इस बारे में एक सुझाव हैं यह ट्रांसफर्ज की पावर्ज उस महकमे के मिनिस्टर से ले लेनी चाहिए। ओर सैक्रेटी को या फिर चीफ मिनिस्टर को दे देनी चाहिए। ये महकमे है हेल्थ डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्से इन बी० एंड आर० (व्यवधान) रैवेन्यू मे तो ऐसी कोई बात है नहीं (व्यवधान) कोआप्रे इन विभाग भी इसमें शामिल है। मेरे नोटिस मे ऐसे वाक्यात भी हैं कि पैसा तो ले लिया जाता है। लेकिन कईयों की ट्रांसफर्ज नहीं होती। ट्रांसफर्ज के लिये 20-20 30-30 हजार रूपया ले लिया जाता है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर के कारण या किसी दूसरे हालात के कारण वह रुक जाये या सैक्रेटी किसी वजह से उन ट्रांसफर्ज को ब्लाक कर दे तो वे लोग जब अपने पैसे मांगने जाते है। तो उनके पैसे नही लौटाये जाते। बल्कि उलटा धमकाया जाता है। कि अगर पैसे मांगोगे तो हम तुम्हारी इन्कवायरी करायेगे कि यह पैसा तुम्हारे पास कहां से आया है। ?

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी बीरेन्द सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, राव साहब बहुत पुराने लैजिस्लेटर है लेकिन whenever he speaks he should be specific about the Minister concerned and the instance which he is quoting.

मै इनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि यह नाम बताये कि कोआप्रे इन में किस ट्रांसफर मै पैसे लिये गये है। अगर यह

उसको प्रुव कर दे तो मैं इस हाउस की मैम्बरी से भी इस्तीफा देने के लिये तैयार हू।(व्यवधान) अगर वे यह कहते हैं कि इनकी बात झूठ नहीं है तो ये इस्तीफा देदे। He should be specific. He cannot drag all the Ministers. This is an aspersion on the House and on the Cabinet as a whole. (Interruptions & notice). This is altogether undesirable.

श्री निहाल सिंह: मेरी बात तो पूरी सुन लो। मैंने आपके बारे में नहीं कहा। (व्यवधान)

Ch. Birinder Singh: No, I do not want to listen.

Shri Nihal Singh: If you do not want to listen, kindly go out.

Ch. Birinder Singh: No, you should go out.

श्री राम बिलास भार्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। राव साहब बोल रहे हैं और चौधरी बीरेन्द्र सिंह का इन्होंने नाम भी नहीं लिया है यह तो बड़े ही नौजवान आदमी है। इनको इस तरह से थैटन नही करना चाहिए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अगर यह गलत बात ऐसे ही कहेंगे तो मैं बिल्कुल थ्रैटन करूंगा।

शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत अपने विरोधी साथियों से एक अर्ज करना चाहता हूँ। कि वे अपनी बात कहें। लेकिन ढंग से। मैं विशेष रूप से राव साहब से यह कहूंगा कि वे

भ्रष्टाचार के बारे में सरकार की नुक्ताचीनी तो करे लेकिन यह नुक्ताचीनी अच्छे ढंग से कही जा सकती है। ये बड़े ही बुजुर्ग आदमी है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वे ठीक ढंग से बात कहें। हम यह जानते हैं कि आप विरोध करेगे। इनको विरोध करना भी चाहिए। क्योंकि अपोजीसन का काम ही विरोध करना होता है। लेकिन इनको हैल्दी किटीसीजम करना चाहिए। अन्त में मैं आपके माध्यम से उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वे कृपा करके ठीक ढंग से विरोध करें और अपनी बात कहे।

श्री निहाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, बीरेन्द्र सिंह को गुस्सा आ गया। मेरी लिस्ट में तो कोआप्रेसन का नाम नहीं था। कुलबीर सिंह बोले थे जिनकी लिस्ट में कोआप्रेसन का नाम था। (गोर) मैंने वहां से पढ़ दिया। मैं एक ओर क्राईटेरिया रखता हू।

श्री उपाध्यक्ष: यह रिकार्ड पर नहीं आयेगा।

श्री निहाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी कोई बात ओबजैक्टिव नैबल नहीं है।

श्री जगदीश नेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, वे किसी भी डिमान्ड पर नहीं बोल रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि माननीय सदस्य बड़े लरनड व्यक्ति हैं और काफी सालों से एम एल ए चले आ रहे। कृपा करके कोई ऐसी बात न कहे जिससे कटुता पैदा हो। मैं आपसे फिर रिक्वैस्ट करता हू कि वे ठीक ढंग से बोलें।

श्री राम बिलास भार्मा:

श्री उपाध्यक्ष: राम बिलास भार्मा ने जो कुछ कहा है वह बगैर परमो न के बोला गया है।। वह रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मै राव साहब के बारे में नहीं कहता। मै सिर्फ यह कहना चाहता हू कि बहुत से भाई बाहर से बात सुनकर आते है। और यहां कह देते हैं वे सभी का नाम ले लेते है। इनकी लिस्ट बन जाती है। कि मै उसका नाम ले दूंगा तुम इसका नाम ले लेना यह तरका ठीक नहीं है। किसी बात को कहने से पहले तसल्ली कर ले कि यह बात ठीक है या गलत है।

श्री निहाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, जब चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने थोडी सी सडक भिवानी में बनवा दी थी तो अपोजीसन वालो ने उस सडक का नाम जवाई रोड रख दिया था (हंसी) डिप्टी स्पीकर साहब, मै एक भाहर में गया। मेरा मतलब फरीदाबाद से है वहां के लोग कहने लगे कि इस भाहर मे मिनिस्टर के जवाई अफसर लगे हुआ है। इसलिये इसका नाम फरीदाबाद से बदलकर जवाई नगर रख दो क्योकि जवाई यहां इक्ठे हो रहे है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): डिप्टी स्पीकर साहब, मै हाउस के मैम्बर साहिबान से एक प्रार्थना करना चाहती हू कि सभी के जवाई हरियाणा में कही न कही लगे हुए। कोई

भाहर मे लगा हुआ है और कोई गांव में लगा हुआ है। उनके बारे मे कोई बात कहना जो जवाब हाउस में न दे सके अच्छी बात नहीं है। जवाई तो इनके भी लगे हुए। इनकी बहु भी लगी हुई है जवाई भी लगा हुआ है अच्छी बात होगी कि पर्सनल बातो मे न जांय। किसी भी साईड के मैम्बर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब किसी का जवाई हरियाणा का रहने वाला है। और हरियाणा में नौकरी करता हैं तो वह हरियाणा में कही न कही लगेगा ही। वह चाहे गांव में नौकरी करे चाहे भाहर में करे। राव साहब काफी पुराने सदस्य रहें है। इनको कोन नही जानता है। कि ये कितनी पानी मे रहे है। हरेक के जवाई होते है।

श्री निहाल सिंह: मैने बहन जी के बारे मे कोई पर्सनल बात नहीं है। फरीदाबाद के लोगों ने जो कुछ मुझे कहा वह बात मेने यहां कह दी है।

प्रो० सम्पत सिंह: बहन जी िाक्षा दे रही थी कि जवाई हरेक के है। ठीक है। होते है। लेकिन उनको सरकार के दामाद नहीं बनना चाहिए। जो लोग सरकार के दामाद बने हुए है। यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: इस तरीके से दोनो तरफ के मैम्बर्ज ट्रेजरी बैचिज के और अपोजी ान बैचिज के सारा टाईम खराब कर देगें ओर फिर कहेगें कि मुझे टाईम नही मिला। इसलिए मेरा सब मैम्बर्ज से यह कहना है कि they should be very brief and to th point. (Interruptions)

श्री निहाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक छोटी सी बात ओर कहना चाहता हूँ अगर मेरे भाई नाराज होते हैं। तो मैं इस बात को यही छोड़ता हूँ। मैं एजूके इन के बारे में कहना चाहता हूँ कि एजूके इन का बैकवर्ड एरियाज के लिए खास ध्यान रखा जाना चाहिए। महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स कालेज बैकवर्ड एरिया हैं वहां नारनौल में एक कालिज हैं ओर उस कालिज में सब से ज्यादा विद्यार्थी हैं। मेरी दरखास्त है कि वहां पर दो रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। गलर्ज की हायर एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी हैं कि वहां पर एक गलर्ज कालिज खोला जाए। जब तक गलर्ज कालिज की बिल्डिंग का इंटरनल न हो तब तक जहां ओल्ड कोर्ट्स थी। उसके कम्पाउन्ड में गलर्ज कालेज खोल देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नारनौल में एम एस सी जियालोजी की क्लासिज हैं यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि उन क्लासिज को उठाकर रोहतक बदल दिया जाय। डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार कहती है। कि बैकवर्ड एरियाज को हम ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देंगे सहूलियते देंगे लेकिन एक बैकवर्ड एरिया में जा क्लासिज भुरु चल रही है। उनको उठाकर रोहतक ले जाना कहां तक उचित है? रोहतक में एडमिशन क्लासिज खोली जा सकती है। आप युनिवर्सिटी में नई क्लासिज भुरु करे दें अगर नारनौल में ये क्लासिज उठा ली गई है। तो वहां पर हालात खराब होंगे। कल भी वहां के स्टूडेंट्स यहां आये थे। कुछ न कुछ कदम लोगों को उठाना पड़ेगा। मेरी सरकार से दरखास्त है कि एम एस सी जियालोजी की क्लासिज वहीं पर रखी जायें। उनको रोहतक न

ले जाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, एजुकेशन के बारे में दो सुझाव ओर देना चाहता हूँ आजकल जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स दिये जाते हैं। उनसे जाति का और डोमोसालि का पता नहीं लगता। जब नौकरी के लिए लडके जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि डोमोसाइल सर्टिफिकेट लेकर आओ। कि तुम बैकवर्ड क्लास या रिजर्व क्लास स हा। मेरा इस बारे में सुझाव है कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसमें दो कालम ओर बना दिये जाये जिसमें लिया जाये कि यह लडका हरियाणा का रहने वाला है। और इस जाति का है। अब तो दिल्ली के रहने वाले भी हरियाणा का डोमोसाइल बनवा लेते हैं सर्टिफिकेट में नाम बाप का नाम रैजीडैन्ट आफ एंड बिलोंगज टू रिजर्व क्लास या बैकवर्ड क्लास जैसी भी पोजीशन हो। अगर इस तरह से कर दिया जाये जो उनको परे पानी नहीं होगी। क्योंकि आजकल तहसीलदार या मैजिस्ट्रेट उनके सर्टिफिकेट अटैस्ट नहीं करते। उनको काफी दिक्कत उठानी पडती है। अगर सर्टिफिकेट में ये सारे कालम हो जायेगे जा सारी प्रोब्लम हल हो जायेगी। इतना कहकर मैं अपना स्थान लेता हूँ।

चौधरी कुन्दन लाल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बोलने का समय दिया है। सबसे पहले मैं अपने हल्के सफीदों के बारे में कहना चाहता हूँ मेरा हल्का एक बैकवर्ड एरिया है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर ज्यादा दस्तकारी बनाई

जाये। ताकि वहां के बेरोजगार लोग अपना कोई न कोई धनधा भारु कर सके। और अपनी रोजी कमा सके। दूसरी बात यह है कि मेरे हल्के मे कनक ओर जीरी वगैरह की बहुत ज्यादा पैदावार होती हैं कीडो की रोकथाम के लिए सरकार को चाहिए कि मेरे हल्के मे बढिया से बढिया दवाईयां सप्लाई की जायं। ताकि किसानों को फसलों को किसी किस्म का कोई नुकसान न हो और पैदावार भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, कोआपरेटिव बैंकों द्वारा जो लोगों को कर्जा दिया जाता है। उसकी वसूली हमारे हल्के में 72 परसेन्ट की जाती हैं जबकि दूसरी जगहों पर कही पर 10 परसेन्ट कही पर 40 परसेन्ट और कही पर इससे भी कम वसूली की दर को ध्यान मे रखते हुए हमारे हलके में सरकार को उतनी ही परसेन्ट के हिसाब से दवाईयों बढिया बीज जमीदारों को सप्लाई करने चाहिए। किसानों को हर तरह की सहूलियतें दी जानी चाहिए। ताकि किसान ज्यादा फसल उगा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक बजट का ताल्लुक है बजट बहुत अच्छा है बजट में इन कामो के लिये काफी प्रोवीजन रखा गया है लेकिन बैंकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिये मेरे विचार मे इस बजट में कोई खास प्रोवीजन नहीं है। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन है कि सरकार इस तरफ ज्यादा ध्यान दे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा अगला प्वायंट हस्पतालों के संबंध में है। मेरे हल्के में एक 16बैड का हस्पताल है। इस बारे में मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था कि वहां पर एक्सरें की जो मशीन पड़ी हुई है वह पुराने समय की है। काम नहीं कर रही है। उसको रिप्लेस किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ मेरा एक ओर निवेदन है हस्पताल की बिल्डिंग बड़ी खसता ढंग की है। जो लोग अपने मरीजों को लेकर आते हैं। वे सर्दियों और गर्मियों में दरख्तों के नीचे पड़े रहते हैं। उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए सरकार इस तरफ खास ध्यान दें। इस सिलसिले में मेरी हेल्थ मिनिस्टर और मुख्य मंत्री महादये से भी बात हुई थी। उन्होंने मेरे से वायदा किया था। कि इस हस्पताल को ज्यादा बैडज का हस्पताल बना दिया जायेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस हस्पताल को जैसा कि दूसरे सभी सबडिवीजनों में 50-50 बैडज के हस्पताल है उसी तरह से बना दिया जाए। अगर 50 बैड का हस्पताल बनाने में सरकार की कोई असमर्थता है तो कम से कम 30 बैडज का ही बना दिया जाए ताकि लोगों को कुछ सहूलियतें मिलें और लोगों को किसी दूर के हस्पताल में इलाज के लिये न जाना पड़े। यह हस्पताल इसी मार्च के महीने में चालू कर दिया जाना चाहिए।

मेरा अगला प्वायंट यह है कि सफ़ीदों में एक बसों का सब डिपो बनाया जाये। क्योंकि इस इलाके के लोगों को अगर

अपने किसी लडके की भाादी के लिये बसे बुक करवानी हो तो उन्हे 70-80 किलोमीटर का चक्कर काट कर बुकिंग के लिये पानीपत या जींद डिपो मे जाना पडता है। जिससे असुविधा होती है। ओर लोगों को 70-80 किलोमीटर का किराया मुफ्त में देना ही पडता हैं इसीलिये मेरा निवेदन हैं कि वहां एक सब डिपो जल्द से जल्द खोला जाना चाहिएं। ताकि इस इलाके के बैकवर्ड लोगो को लाभ हो सके।

श्री मनफूल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायट आफ आर्डर है कि भाई कुन्दन लाल जी बैकवर्ड क्लास भाईयों के भले की बात करते है। लेकिन बैकवर्ड क्लास के लिये सरकार के दिल में कोई स्थान नहीं है। अगर बैकवर्ड लोगों कि लिए भलाई का कोई काम हो सकता है। तो वह तो लोकदल सरकार के द्वारा ही हो सकता है। ये तो फालतू मे दूहाई दे रहें है।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी कुन्दन लाल: इसके बाद में ऐजुकेशन से संबधित कुछ बाते कहना चाहूंगा। मेरे हल्के में सरकार की तरफ से शिक्षा के लिये बडे कम साधन अवेलेबल है। वहां पर बहुत कम स्कुल खोले हुआ है। जो है उनकी बिल्डिंग गिरी पडी हैं इनकी कई सालों से मुरम्मत नहीं हुई है। नेहरा साहब ने मुझ से वादा किया था ओर अब से 10 तारीख को कई स्कुलों का उद्घाटन करने कि लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों मे जा रहे

है। मेरी इन से रिकवैस्ट है कि इस बारे में मेरे हलके सफ़ीदों का पूरा पूरा ध्यान रखे। मुझे आता है कि मेरे हलके में और स्कुल खोले जायें। इन भावों को साथ में इन डिमांडज का समर्थन करता हुआ सदन से यह निवेदन करूंगा कि इनको पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब श्री लश्रमण सिंह कम्बोज बोलेंगे। लेकिन कम्बोज साहब आप इस बात का ध्यान रखें कि पांच सात मिनट में ही अपनी बात कहकर बैठ जाईये।

प्रो० सम्पत सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है। कि आज से जो मैम्बर बोलें हैं वे 10—10 15—15 मिनट बोलें हैं। जब हमारी बारी आई तो आपने यह कहना भुल कर दिया कि 5—6 से मिनट से कोई ज्यादा नहीं बोलेंगे। आपसे मरी सबमिशन है कि आप जा टाइम हमारी पार्टी के सदस्यों को देंगे। हम उसी के अन्दर बोलेंगे और हम उसी पर बाँड रहे हैं। कल भी जब मैंने बोलना भुल किया था तो उसी समय आपने टाइम के बारे में कहा था। जब उधर से कोई सदस्य बोलने लगता है तब आप उनको 10—15 मिनट का समय बोलने के लिये देते हैं। इसीलिये मेरा आपसे सादर नम्र निवेदन है कि आप कम से कम दोनों तरफ के मैम्बरज को बोलने के लिये बराबर समय दें। धन्यवाद।

Ch. Phool Chand: Deputy Speaker, Sir, while speaking on budget my time was cut by your goodness. I

want to know from the Chair whether I will be able to get time today or not?

Mr. Deputy Speaker: You will get time.

श्री लछमन सिंह कम्बोज (इन्दरी): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं फलड के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ मैं हर सै उन में फलड की बात को उठाता आया हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, आपका इलाका भी खादर के एरिया में पडता है। यह इलाका हमें 11 से पिछडा हुआ है इसमें कुछ कुरुक्षेत्र जिले के और कुछ करनाल जिले के इलाके है। पिछला बजट में यू ही चला गया ओर बजट भी यू ही चला गया। लेकिन इस इलाके के फलड के बचाव के लिये बहुत कम पैसा रखा गया है। जमना के किनारे किनारे हरियाणा को कई हजार एकड जमीन यू पी में चली गई ओर बहुत से लोगों के ट्यूबवैल तक भी उधर चले गये। कई लोग बँधर हो गये। लेकिन इस सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यू पी सरकार ने अपनी तरफ से बहुत बडे बडे बांध हुए है। जहां तक सडकों का सवाल है। आपने भी देखा होगा कि जमना नगर से लेकर करनाल तक सडके बिल्कुल टूट गई। नई सडके तो क्या बननी थी पुरानी भी टुट गई ह। मेरे हलके मे ऐसे भी लोग है जिन्होंने आज तक सडक का मुह भी नहीं देखा है जैसे छपरा ओर चानन म्यूरी गांव है। इन गांवो के लोगों को 15-20 किलोमीटर का चक्कर काट कर आना जाना पडता है। इस बजट में इन गांवों की सडकों के लिये कोई प्रोवीजन नही है। जहां तक हस्पतालों का सवाल है केवल इन्दरी में 10 बिस्तरों का

एक हस्तपाल हैं अगर 20 मरीज चले आये तो केवल 10 को ही जगह मिलेगी। ओर बाकी 10 करनाल जाते हुए रास्ते में ही मर जाते है। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले साल मच्छर मारने की मैलाथीन दवाई खरीदी गई थी। सरकार ने लोगो रूप्ये खर्च किए थे लेकिन सप्रे करने पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इस बार वहां मच्छर इतना हुआ कि मलेरिया से बहुत से लोगो की मौत हो गई । इस तरह से हैन्थ डिपार्टमेंट का भी बहुत बुरा हाल है। गरीब लोगो को दवाई के एक बट्टी भी नहीं मिलती है। करनाल के हस्पताल के बारे में मैने पिछले सैसन में कहा था कि उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है। बिल्डिंग मे बदबू फैली हुई है। जिस की वजह से मरीज ओर भी बीमार हो जाते है। करनाल में मिनी सैक्रैरियट की नई बिल्डिंग के लिये मुख्य मंत्री जी ने पत्थर रखा था। लेकिन उस पर अभी तक कोई काम भुरू नहीं हुआ । यह बजट तो कागजों तक ही सीमित रहता है। वास्तव में कुछ नहीं होता है। पता नहीं बजट कहां रह सकता है।? इसी तरह से पुलिस विभाग का बहुत बुरा हाल है। हर थानेदार पैसा मांगता है। बिना पेसे लिये गरीब आदमी की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती । इस समय सरकार के बारे में कहने के लिये बाते ता बहूंत है लेकिन समय के अभाव में मै इस बजट का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

मास्टर िव प्र ाद (अम्बाला भाहर): उपाध्यक्ष महोदय, मै डिमांड नं. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 16 ओर 23 के बारे में

बोलना चाहता हूँ । डिमांड नं. 5 और 23 पर विशेष तौर पर बोलूंगा। सब से पहले मैं डिमांड नं. 5 के बारे में कहना चाहता हूँ जो एक्साइज एंड टैक्स इन डिपार्टमेंट के बारे में है। अधिक टैक्स लगाने से हरियाणा के व्यापार को नुकसान पहुंचा है। मैं एक्साइज एंड टैक्स मिनिसटर का ध्यान केवल एक ही मिसाल देकर दिलाऊंगा कि अम्बाला भाहर में एक बहुत छोटा सा व्यापार है। बाहर से चूड़ियां लाने का। पिछले साल बजट में कांच की चूड़ियों पर 10 प्रतिशत सेलज टैक्स था। अब उसको बढ़ाकर 12 परसेंट कर दिया गया है कांच की चूड़ी आम गरीब घरों की रहने वाली महिलायें पहनती है। अमीर महिलायें जो सोने और चांदी की चुड़ियां पहनती है। लेकिन इनके ऊपर तो केवल 2 परसेंट टैक्स है। ओर कांच की चूड़ियों के कोई टैक्स नहीं है। वे प्रान्त हैं अन्ध प्रदेश । कर्नाटक तमिल नाडू उड़ीसा पश्चिमी बंगाल महाराष्ट्र गुजरात ओर राजस्थान । हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब में केवल 4 परसेंट टैक्स है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां ज्यादा टैक्स होने की वजह से लोग चुड़ियों बाहर से मंगवाते हैं। जिसकी वजह से हरियाणा के व्यापार को घाटा हो रहा है। दूसरी बात यह है। कि भाराब के ठेकेदारों के पास सरकार की रिकवरी का करोड़ों रूपया बकाया है। इसके लिये ठेकेदारों ने एक नया तरीका अपनाया है मान लो किसी ने सरकार को 50000 रूपया लेंना है। वह ठेकेदार किसी ओर के साथ मिल कर ठेका ले लेता है। ओर सौ दो सौ रूपये की किमत बांध लेता है। ऐसा करने से सुद के रूप में उसे एक हजार रूपया महीना बचता है। वे लोग

किसी को हजार दो हजार रूपया देकर कि त बांध लेते है इस बारे में मै मिनिस्टर साहब से भी मिला था। कोणिक साहब तथा दूसरे अधिकारियों से भी मिला था। उनको मैने नाम भी बताये। थे कि फला फला आदमी लखपति हैं अगर आप इनसे बकाया पैसा लेने की कोणिका करैतो ये फौरी तोर पर पेमेंट कर देंगे। ऐसाकरने से करोडों रूपये की रिकवरी हो सकती है। ओर वह पैसा डिवैल्पमेंट पर खर्च हो सकता है। अब मैं एजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं मै कुछ सुझाव दुगां ताकि एजुकेशन मे सुधार हो सके। ओर उसमे कुछ न कुछ बढोतरी हो। मैने पिछले बार भी कुछ सुझाव दिये थे। जैसे हर एक जिले में बी ई ओ के पास 25 स्कूल किसी के पास 30 स्कूल ओर किसी के पास 56, 60 स्कूल होते है। मेरा सुझाव हे कि स्कूलों के बीच एक सैट्रल प्लेस हो जिसमें बी ई ओ का आफिस होना चाहिए। वरना वह ठीक तरह से स्कूलों की सुपरवीजन नहीं कर सकता। कोन टीचर समय पर नहीं आता। और कोन आता। मै समझता हूं कि मंत्री जी इस बारे में ध्यान देगे। दूसरे कई बार अगर हमें कोई टैलीफोन करना होता है तो हमें एस डी ओ के दफतर में जाना पडता है क्योंकि बी ई ओ के दफतर में कोई टैलीफोन नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि बी ई ओ के दफतर में टैलीफोन होना चाहिए। जहां तक चैकिंग का सवाल है इसमें बहुत दिक्कत है डिप्टी स्पीकर साहब पहले इन्सपैक्टर आफ स्कूल होते थे। डिस्ट्रिक्ट इन्सपैक्टर आफ स्कूलज होते थे वह स्कूलों को एग्जामिन किया करते थे ओर यह देखते थे कि बच्चों की पढाई

में कही कमी तो नहीं आ रही है। अगर कही कमी होती हैं तो वे सुझाव दे कर जाते थे ओर नोट लिख कर जाते थे। कि इस बार यहां पर यह कमी पाई गई आयंदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज एक मंत्री चला जाये। तो एस डी एम बी ई ओ। ओर डी ई ओ का आफिस बिल्कुल खाली हो जाता है। मंत्री चाहें तो किसी भी विभाग का हो वे उसकी सेंवा करने के लिए आफिस खाली करके चले जाते है। परिणामस्वरूप उनके आफिसों का काम सफर करता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा एक सुझाव देना चाहूंगा कि स्कूलों का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा अलग कर दियाजाये। ऐसा कर दिया जाये कि मिनिस्ट्रों की सेवा के लिए फलां फला अफसर जाएंगे स्कूलों की इंस्पैक्सन की दृष्टि से डीईओ ओर बीईओ जाये ओर शिक्षा में सुधार लाने के लिए रजिस्ट्रों में सुझाव लिख कर जायें। अगली बार जब वे चेकिंग करने आये तो उस समय उस चेक करे कि जो सुधार बताये थे आया वह सुधार हुआ है या नहीं। इसके अलावा मैं एक बात ओर कहना चाहूंगा कि देहातो में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो सडकों से नहीं मिले हुए जबकि यह आर्डर है कि स्कूलों तक सडकें जरूर जानी चाहिए। एक नहीं बहुत से स्कूल ऐसे है जो सडको से नही मिलाये गये। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जिन स्कुलों को सडक से नहीं मिलाया हुआ उन तक हर हालत में सडक पहुंचाई जानी चाहिए। ताकि स्कूलों में जाने वाले बच्चों को कोई दिक्कत न हो। डिप्टी स्पीकर साहब, यहां सदन में कहा जाता हैं कि स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी नहीं है। इस बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं

अम्बाला भाहर में एक गवर्नमैट हायर सैकैण्डरी स्कूल हैं उसमें 225-250 बच्चे पढते हैं ओर वहां पर स्टाफ भी पूरा हैं लेकिन बिल्डिंग के बंधुत से कमरे बंद पडे रहते हैं। इस बारे में मे एक सुझाव देना चाहुगा उस बिल्डिंग मे एक गवर्नमैट कालेज खोल दिया जायें। ताकि वह बिल्डिंग भी काम मे आये ओर सुरक्षित भी रहें। उस बिल्डिंग के साथ साथ चण्डीगढ दिल्ली जाने वाली सडक लगती है इस सडक पर बलदेव नगर कैम्प मे एक हाई स्कूल हैं जिसमें लगभग 1800 बच्चे हैं उस स्कूल में को-एजुकेशन है और इतने ज्यादा बच्चे हैं। कि कंट्रोल नहीं हो पाते। पिछले दिनों ट्रक के नीचे आ कर एक बच्चा मर गया था। इस सारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि बलदेव नगर कैम्प मे जो प्राइमरी स्कूल है उसको अपग्रेड करके लडकियों का मिडल स्कूल बना दिया जाये। ऐसा करने से हाई स्कूल के आठवीं तक के बच्चों के संख्या कम हो जायेगी। बच्चे कम होने के कारण वहां का एडमिनिस्टेटिव ढांचा भी ठीक होगा ओर बच्चों पर कंट्रोल होगा। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर अब य विचार किया जाये। इसके अलावा मैं एक बात ओर कहना चाहूंगा कि कालेजों के लिए जा अलग डायरेक्टोरेट बनाया गया हैं इस पर सरकार दोबारा गम्भीरता से विचार करे। प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी अलग डायरेक्टोरेट बना दिया जाय। प्राइमरी एजुकेशन में लगभग 45-50 हजार टीचर्स हैं। अगर इन के लिए अलग डायरेक्टोरेट बना दिया जाए तो शिक्षा मे काफी सुधार आएगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो डीपीआई

तक की परमोशन है वह डिपार्टमेंटल परमोशन होनी चाहिए। एजुकेशन की लाइन से निकले हुए आदमी को यह मालूम हो जाता है कि किस स्कूल में क्या क्या कमी हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है। हर आई ए एस आफिसर को स्कूलों की हर कमी का पता नहीं होता। और न ही इसका इलाज कर सकते हैं। आई ए एस आफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ढाचें में जो चाहे मर्जी कर ले लेकिन एजुकेशन की लाइन में उनको पता नहीं होता है। इसीलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा को ध्यान में रखते हुए डीपीआई तक की परमोशन डिपार्टमेंटल परमोशन देनी चाहिए।

इस के अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हरियाणा राज्य परिवहन के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। आप किसी भी बस स्टैंड पर चले जायें। वहां की हालत खराब होती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे धरौड़ा और सम्भालखा के बस अड्डों पर ठहरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहां पर चाय भी काम की नहीं मिलती है। और जो मिलती है। उसका एक कप का कम से कम एक रूपया चार्ज किया जाता है। मैं परिवहन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इन दुकानों का किराया फिक्स कर दें। और मिना बना दें। ताकि मिना के मुताबिक लोगों को सही रेट पर चीज मिल जायें। सरकार आठ न कर के दुकानदारों से पैसे लेती है। लोगों को वहां पर कोई चीज नहीं मिलती है। अगर कहीं चाय वगैरह मिलती है वह ठीक नहीं होती है। और एक कप चाय का

एक रूपया चार्ज कर दिया जाता हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, आगे गर्मी का सीजन आ रहा है। आप किसी भी बस स्टैण्ड पर ठंडे पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। सरकार को हर बस स्टैण्ड पर ठंडे पानी का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी बस स्टैण्ड पद युरिनल की हालत देखे। आप को मालूम होगा कि वह यूरिनल उसी समय अच्छा बना होगा जिस समय बस स्टैण्ड बनाया होगा। उसके बाद उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन की सफाई की आरे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। और न ही मुरम्मत की ओर ध्यान दिया गया है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान दिया जाये।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस्टीज के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। पिछले सै। न में अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीली बैकवर्ड एरिया घोशित करने के लिए एक रेजोल्यु। न आया था। लेकिन उस तरफ अभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया हैं। मैं सरकार से प्राथनाकरूंगा कि अम्बाला भाहर की डिवैल्पमेंट ओर ध्यान दिया जाए। जो 25 हजार रूपये पढे लिखे नौजवानों को अपना धंधा भुरू करने के लिए ग्रांट के रूप में देने का सिलसिला सरकार ने चलाया है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इस 25 हजार रूपये के लोन मे भी गडबड हो रही है। जिन लोगों को अपना धंधा भुरू करने के लिए 25 हजार रूपए का लोन दिया जाता है। वह ठीक ढंग से नहीं दिया जाता हे।

उस की इन्कवायरी होनी चाहिए। जो आदमी अपना धंधा भुरु करने कि लिए लोन लेता है। उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। या नहीं। उस ने लोन लेने के बाद अपना काम भुरु किया है। या नहीं। इसकी इन्कवायरी होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत से आदमी इस लालच से लाने लेते हैं कि सरकार की तरफ से इस लोन पर 6250 रूप्ये की सबसिडी मिलती है। बहुत से लोग सबसिडी के लालच में आ कर लोन ले रहे हैं। वास्तव में कोई धंधा भुरु नहीं कर रहे है। मै सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और इस चीज की इन्कवायरी करवाये कि आया वह लोन ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। या नहीं।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मै जनरल एडमिनिस्ट्रेरान के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। विकास की दृष्टि से अम्बाला भाहर की हालत बहुत बुरी है। डिप्टी स्पीकर साहब, मै चाहुगा कि वहा पर एक भी विकास का काम नही हुआ हैं आप अम्बाला भाहर में जाये। मैं यह नही कहता कि आप पैदल जायं आप अपनी कार में बैठ कर भाहर के अन्दर जायें जब आप सडक पर चलेगे तो अनके बार कार मे बैठें उछेलेंगे। अम्बाला भाहर के अन्दर सडके टूटी पडी है। ओर बहुत गहरे गडढे है। वहां पर पैदल चलते समय आदमी का और स्कूटर का किसी का किसी भी समय एक्सीटैट होने का खतरा रहता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि अम्बाला भाहर में सडको

की हालत बहुत बुरी है। ओर सफाई का बहुत बुरा हाल है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वे अम्बाला मयूनिसिपल कमेटी की अम्बाला भाहर की डिवैल्पमेंट के लिए कम से कम एक करोड रूपया दे। अम्बाला भाहर को मेनटेन करना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा पुलिस के बारे में सदन के अन्दर बहुत सी बातें कही जाती हैं। जिनके कारण सरकार की बदनामी होती है यहाँ पर पुलिस के बारे में तरह तरह की चर्चा होती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो डाके पडते हैं। चोरियाँ होती हैं। ओर कत्ल होते हैं। यदि उनके बारे में पुलिस एकदम एक्सन ले ले तो मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से सरकार का वकार बढेगा। पोलिटिकल आदमियों का भी वकार बढता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको सिढौरा के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। पिछले दिनों जब सिढौरा के अन्दर रामलीला हो रही थी। उस समय एक बाल्मीकि की 8-9 साल की नाबालिक लडकी को अगवाह किया गया ओर उसके साथ बलात्कार भी किया गया। बाद में उस लडकी की लाश कुएं से मिली थी। अभी तक पुलिस ने उस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। जिनका पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के पास एक गांव कुराली है। जिसको भायद एसी चौधरी साहब भी जानते होंगे। वहां पर एक पंचायत है पंचायत का वह संरपच किसी मिनिस्टर का रि तेदार हैं उसने कुराली गांव की 180 एकड जमीन जो पैदावार की जमीन हैं उसमें से 61 एकड जमीन लेकर एक प्राईवेट संस्था बनाकर उस संस्था के नाम करना चाहता है। जबकि वहां पर कोई ट्रस्ट नहीं हैं और न ही उसका कोरम है। इसी तरीके से एक ओर ट्रस्ट है मैं बताना चाहता हूं भायद यह बात मुख्य मंत्री जी के नोटिस में नहीं होगी अब उनहें भी पता चल जाएगा और वे इस बुराई को दूर कर देंगे। इससे उन्ही का नाम होगा। इसी प्रकार अब मैं अम्बाला जिले के बारे में कहना चाहता हूं वहां एक ट्रस्ट हैं। उस ट्रस्ट का नाम माता समला देवी है। इस ट्रस्ट का एक ही आदमी है। मैं बताना चाहूंगा कि उस व्यक्ति ने गलत तरीकों से 40 लाख 48 लाख 8 लाख 30 लाख रूपए कमाये है। इस प्रकार उसने डेढ करोड रूपए बना रखे है। यदि मैं उस व्यक्ति का नाम लुंगा तो आप उस कहेंगे कि कार्यवाही में से काट दें। वे पहले पब्लिक हैल्थ में इंजीनियर इन चीफ हुआ करते थे वहीं अकेला इस ट्रस्ट का मालिक बना हुआ है। अगर आप इस की इक्वायरी करा लें। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: नाम को एक्सपंज कर दिया जाये।

मास्टर वि प्रसाद: उस आदमी ने डेढ करोड रूपए कमाए हुए है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जायं।(गोर) अब श्री रो लाल जी बोलेगे।

मास्टर शिवा प्रसाद:(गोर)

श्री उपाध्यक्ष: मेरी परमि लाल जी कि बगैर जो बोला जा रहा है। वह रिकार्ड न किया जायें।

मास्टर शिवा प्रसाद:

चौधरी रो लाल आर्य (छछरोली): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले डिमांड नं. 3 जो होम की हैं पर बोलना चाहूंगा। मैं जो बातें कहूंगा वे स्पैसिफिक कहूंगा। नोट करने वाले मंत्री जी यहां पर बैठे नहीं हैं। होम डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी काबलियत तो यही हैं कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया था ओर ये इस बात को मानने कि लिए तैयार नहीं हैं। न ही इनहोने स्पीकर साहब को मेरी कोई खबर दी। दूसरी बात मैं किताब सिंह जी के बारे में कहना चाहता हूं। इन्होंने इनको भी पिछले दिनों पकड़ लिया था लेकिन उस बारे में भी आज तक कुछ नहीं कर पाये। इसके अलावा ओर भी बहुत सी प्रमाणित बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसका कोई इलाज होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बावल के पास गुजरी वास गांव है। वहां पर रिवाडी का एक आदमी उस गांव के एक आदमी की जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा करना चाहता है जिस व्यक्ति की जमीन थी वह एक दिन खेत में काम कर रहा था। उस पर पुलिस की मदद से हमला किया गया।

परिणाम स्वरूप एक 22 साल का जवान मारा गया ओर दो व्यक्ति घायल हुए। लेकिन आज तक गोली चलाने वाले आफिसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें कई शिकायतें करतें हैं। ओर वे सारी की सारी जैनुबन होती है। लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। सरकार समझती है। कि हम कोई ठोस बात नहीं कहते ओर बिना प्रमाण के बात कहते हैं। जो बातें मैं कह रहा हूँ ये सारी की सारी प्रमाणित बातें हैं इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। किसानों के साथ आज क्या व्यवहार किया जा रहा है। वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। नूरहद गांव का एक नायब सिंह व्यक्ति है इस व्यक्ति ने एम आई टीसी द्वारा दिए गए पैसों की रसीद मेरे पास हैं लेकिन जब वह बराडा तहसीलदार के पास गया तो उस किसान को जबरस्ती उठवा लिया गया। आरे उससे 400 रूपये ले लिये। इन बातों से पता चलता है कि सरकार किस तरीके से किसानों को मारना चाहती है दूसरी बात मैं वकीलों की करना चाहता हूँ वकीलों की जो गिरफ्तारी की गयी थी उस सिलसिलें में वकील यमुनानगर मे धरना देगे। मैं। बाई चानस वहां पर चला गया। ओर वहीं पर एक जगह पर पानी पीने के लिए चला गया। मैंने देखा कि कुछ आदमी खिडकी से झांक रहें है और बाहर से ताला लगा हुआ है। मैं देखकर हैरान रह गया किये कोन आदमी है ओर कहां के रहने वाले है बाद मे पता चला कि चारो आदमी मेरे हल्के के ही थें। उनको बिना किसी वॉरंट के को-आप्रेटिव डिपार्टमेंट वाले वसूली के चक मे पकड लाये थे। जबकि आज कल वैसे भी वसूली

स्थगित की हुई । को-आप्रेटिव विभाग वाले लोगों से कुछ खाने पीने के लिए लुटने के लिए दह आत फैलाने कि लिए ओर रि वत लेने के उदे य से किसानों की बन्द करते रहते है। यह सभी प्रमाणित बाते है । जिन लोगों ने ऐसा गलत काम किया है उनको दण्ड दिया जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महादेयय प्रैस को भी हमारे लोकतंत्र के अन्दर जिन्दा रहने का अधिकार हैं एक श्री ओएन गर्ग इण्डियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर है । उन्होनें अम्बाला की एक सही खबर लिख कर किसी गैग का भण्डा फोड कर दिया हैं अब उसके पीछे पुलिस लगी हुई है । रात को भी मेरे पास उनका टेलीफोन आया था । उन्होनें कहा कि आप विधान सभा मे इस बात को उठायें क्योंकि मेरी जान को पुलिस वालो से खतरा है । यदि इस तरीके से किसी को गिरफ्तार किया जाता हैं तो यह बुरी बात है । किसी भी रिपोर्टर को डराया धमकाया नही जाना चाहिए । दूसरी बात मै होम की यह कहना चाहता हूं कि ये हमें कहते हैं और समझते है कि लिख कर दे । मैने लिखित मे एक रि कयत इन्जीनियर इन चीफ ओर मुख्य मंत्री जी को भी भेजी हुई है कि मेरे हल्के मे एक एस डी ओ है । मेरे हलके के अन्दर जितनी सडके मन्जुर हुई थी । वे सब की सब कागजो पर ही है । वह एसडीओ तारकोल ओर दूसरा सामान खा गया । कागजों के अन्दर सडके बनी हुई ओर पुल बने हुए हैं लेकिन वास्तव में मौके पर कुछ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: जिस आफिसर का नाम लिया गया है उसे एक्सपंज कर दिया जाये।

चौधरी रोान लाल आर्य: यह सब कुछ तब होता है। जब हम लिख कर देते हैं। प्रमाणित करके देते हैं ओर बकायादा नम्बर देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी जब कोई कार्यवाही नहीं होती तो हमें संदेह होता है कि जो पैसा नीचे वाले लोग खाते हैं। वह जरूर ऊपर तक पहुचता है। जहां कार्यवाही करने वाले बैठे हैं यही कारण है उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता।

दूसरी बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूँता हूँ उपाध्यक्ष महोदय शिक्षा किसी भी समाज का आधार होती है। जिस समाज में शिक्षा की ठीक प्रबंध नहीं कर सकता। आज हमारी शिक्षा के अन्दर नैतिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। बच्चों को शिक्षा देते समय संस्कार नहीं बताये जाते आप चाहे किसी को आईएस आईपीउस बना दे। या किसी को टैक्नीकल एजुकेशन दे दे। जब तक उसको कोई नैतिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। अच्छे संस्कारों के निर्माण का वातावरण नहीं बनाया जायेगा। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। तब तक कोई विद्वान हाते हुए भी समाज में फेल हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, रावण चारों वेदों का विद्वान था। लेकिन उसको नैतिक शिक्षा का ज्ञान न होने के कारण वह फेल हो गया। क्योंकि उसके संस्कार अच्छे नहीं थे। नैतिक शिक्षा का ठीक प्रकार से ज्ञान न होने की वजह से चोरो वेंदों का ज्ञाता होते हुए भी वह धर्म की बातों पर नहीं

चल सका। जबकि वह भासक था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मौजूदा शिक्षा है वह समाज में अनेक प्रकार से रावण पैदा कर रही है। जितने भी लोग पढ़ लिख जाते हैं। वे गरीब और पिछड़े हुए लोगों का खून पीने की कोशिश करते हैं। यदि नैतिक शिक्षा भुरू से दी जाये बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया करते हैं। योग विद्या भुरू से सिखाई जाये। जीवन चरित्र का सारा अभ्यास सिखाया जाये तो मैं समझता हूँ कि समाज का चरित्र बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है। और समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है।

उपाध्यक्ष महादेय, अब मैं इण्डस्ट्रीज के बारे में एक लाईन कहना चाहूंगा। इण्डस्ट्रीज विभाग की तरफ से बेरोजगार लडकों को 25 25 रूप्यें तक लोन देने की स्कीम चलायी हुई है। इस लोन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत सी शिकायतें आई हैं। मेरी गुजारिश है कि इन शिकायतों पर गौर करनी चाहिए। यमुनानगर एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रीयल एरिया है। मेरा सुझाव है कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई आफिस अवश्य होना चाहिए। ताकि वहां के लोग उनको गाइडेंस का लाभ उठा सकें। और इण्डस्ट्रीज का बिस्तर कर सकें।

13.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं फोरैस्ट के बारे में कहना चाहूंगा। फोरैस्ट के लिए इस मांग के माध्यम से पैसा मांगा जा

रहा है। फोरैस्ट के बारे में प्र नोतर काल के दौरान भी प्र नोत्तर चले थे। फोरैस्ट के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा लेकिन अगर सही बात कहूंगा तो वह कडवी लगेगी। ये कूद पड़ेगे इसलिए मैं कोई भगदड मचाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महादेय, मैं फोरैस्ट के बारे में कह रहा था कि जो आफिसरज फोरैस्ट के अन्दर बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो धपला फोरैस्ट बोर्ड में हो रहा है। उसकी जांच कर लेनी चाहिए। क्योंकि सरकारें तो आती रहती है। कोन एमएलए बन गया ओर कोई एमएलए नहीं बना। कही ऐसा न हो कि जनता का दाव लग जायें ओर सरकार बदल जाय या इसी सरकार के अन्दर कोई परिवर्तन आ जाये। फोरैस्ट में जो करोड़ों रूपये के घपले हुए हैं बाद में अगर जांच हो गयी तो उस जांच के दौरान बेकसूर लोग न मारे जाये। जांच हो गयी तो न जाने कितने आदमी ओर आफिसर जेलों की सीखों के अन्दर होंगे। आफिसरज को लोगों के दवाब में आ कर काम करना पडता है ओर मंत्री लोग फोन करके पीछे हट जाते हैं स्पीकर साहब, मैं यह चाहूंगा कि फोरैस्ट बोर्ड में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है इसको चैक करने के लिए एक सेल बनाया गया। इस सेल के जरिए इस भ्रष्टाचार को अनायुक्त किया जाये। आज इस बोर्ड के जरिए जनता के गाढे पसीने की कमाई को लुटाया जा रहा है। ओर यह लूटने का एक अड्डा है। इस लुटाई पर कोई न कोई रोक लगाई जानी चाहिए। जो भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी इन्कवायरी किसी हाई कोर्ट के जज के द्वारा करवाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त फोरैस्ट बोर्ड में कई काबिल आफिसर हैं उनको

सरकार ने खुडडे लाईन लगा दिया है। इनके साथ ज्यादाती नहीं करनी चाहिए।

अब मैं मांग नं. 23 पर बोलना चाहूंगा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में है स्पीकर साहब कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक प्रकार की आध्यात्मिक राजधानी है। यहां पर नया बस स्टैंड बनाया गया है। यह अड्डा ऐसी जगह बनाया गया है। जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं होता। खास तौर पर भाहर के लडके जो पढने के लिए आते हैं। बड़े परे गान है। बहुत से छात्र आसपास से पढने के लिए आते हैं। उनको बड़ी भारी दिक्कत है। खास तौर पर जो गरीब छात्र हैं उनको आने जाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पडता है। यह अड्डा पिपली के पास बनाया गया है। यह छात्रों का दूर पडता है। बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा रात को ट्रांसपोर्ट का भी कोई साधन नहीं मिलता। इसीलिये मेरी सरकार से दरखास्त है कि इस अड्डे का निर्माण ऐसी जगह किया जाये जहां से लोगों को आते जाते हुए कोई दुविधा न हो।

इसके अलावा स्पीकर साहब, बहुत से लडके कालका से पंचकुला पढने आते हैं। लेकिन सरकार ने उनके बस पास की फीस में वृद्धि कर दी है। यह इनके साथ ज्यादाती है। इस वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, मेरे इलाके में एक बस स्टैंड बनना था। पिछले साल इसके लिए बजट में 40 हजार रुपया रखाथा। लेकिन यह रुपया खर्च नहीं किया गया ओर लेप्स

हो गया है। फिर मैंने कहा कि पिछले साल 40 हजार रुपया लेप्स हो गया था। इस साल तो लेप्स नहीं होना चाहिए। कम से कम ईंटे वगैरहा ही डलवा दो। वंहां पर ईंटे वगैरहा डाल दी गई लेकिन ये ईंटे खा गए ओर बस अडडा नहीं बन सका। इसके इलावा मेरे इलाके में कलसर ओर कोट जैसे गांव है। इनमें छोटे छोटे भौल्टर बनाये जाये ताकि लोग बारि । ओर धूप में न बैठे जरूरत पडने पर इन भौल्टर्ज का इस्तेमाल कर सके।

चौधरी भाकरूल्ला खां (फिरोजपुर झिरकां): जनाब साहब आपका भुक्तिया जो आपने मुझे बोलने का टाईम दिया। मैं मांग नं. 3, 9, 10, 14 पर बोलना चाहूंगा। जनाब मेरा इलाक मेवात का इलाका है। यह बहुत पिछडा हुआ इलाका है। सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा बैकवर्ड इलाक मेरी कांस्टीच्युएसी फिरोजपुर इलाका है। जहां तक शिक्षा का तालुक है यहां पर जो स्कूल है उस मे कोई भी मास्टर नहीं है। ओर इसका कारण यह है कि इस इलाके के लडको को मास्टर नहीं लगाया जाता हैं सब बाहर के लडके है। इसके अलावा सरकार ने फिरोजपुर झिरका में जेबीटी की ट्रेनिंग के लिए कालेज खुलवाया है। मेरी सरकार से दख्वास्त हैं कि इस कालेज से जो लडके पास होकर निकले उनको मेवात के एरिया मे भी मास्टर लगाया जाये। ताकि स्कूलों मे मास्टरों की कमी दूर हो सके। स्पीकर साहब, उद्योग धन्धों की तरफ हमारी सरकार ने बहुत तरक्की की है। इसके लिए मैं चौधरी भजनलाल जी का बडा अभारी हूं इन्होने मेवात की डिवम्लपमैट के

लिए मेवात बोर्ड बनाया और इस बोर्ड के बन जाने से जा तरक्की हुई है। वह बहुत ही सहानीय हैं इसमें कोई भाक की बात नहीं है। मेवात के एरिया मे उद्योग कि लिहाज से फिरोजपुर झिरका बहुत पिछडा हआ है। इस इलाके के साथ राजस्थान का इलाका अलवर लगता है। यहां पर दिल्ली ि लोगों ने बडी बडी फ़ैक्ट्रियां लगा रखी हैं टाटा ने मरसरी गाडी बनाने की फ़ैक्ट्री लगाई हुई है। ओर यह दिल्ली के इडस्टियलिस्टस ने लगाई है। अगर दिल्ली के लोग फ़ैक्ट्री लगा सकते है। तो झिरका के लोग क्यो नही लगा सकते। इस लिए मैं सरकार से रिक्वैसट करूंगा कि फिरोजपुरा झिरका नुह ओर पुनहाना में उद्योग लगाय जाये। ओर इन उद्योगों को लगाने की इजाजत यहां के लोगों की ही होनी चाहिए। अब मैं स्वास्थ्य के बार में थोडा सा अर्ज करना चाहता हू। फिरोजपुर झिरका में केवल 30 बैट्स का हास्पिटल है यह छोटा हस्पताल है। ओर मरीजों की तादाद मेवात का काफी बडा इलाका है। लेकिन यहां पर बडा हस्पताल नहीं है। इस इलाके में हस्पताल बनाने के लिए 20 एकड जमीन देने को तैयार है। सरकार इस जमीन को ले ले ओर यहां पर 50 बिस्तरी का बडा हास्पिटल बनाया जाये। मैं आपका बहुत भुक्रगुजार हूंगा। अब मैं मांग नं. 23 पर जो परिवहन के बारे मे थोडा से अर्ज करना चाहता हूं मेवात के एरिया में बसे बहत कम चलती है। जिस प्रकार गुडगांव का डिपो हरियाणा में सब से बडा डिपो है। उसी प्रकार का डिपो फिरोजपुर झिरका मे बनाया जाये। ताकि इस एरिया ज्यादा से ज्यादा बसें चलाई जा सके। अब मैं डिमांड नं. 3 पर बोलना चाहूंगा पुनहाना थाना

हरियाणा के बार्डर पर लास्ट थाना है। इस थाने की बिल्डिंग बहुत कच्ची हैं जब कोई कोई कांड होता है। तो थाने वालो को आने जाने मे भी दिक्कत होती है। इसलिए मेरी सरकार से दुख्वास्त है कि इस थाने को एक जीप दी जाये थाने वाले असानी से इधर उधर जा सके। इसके साथ ही थाने की बिल्डिंग कची हैं इसको भी पका किया जाये। इसके अलावा सरकार ने वंहा पर आई टीआई खौला है। ओर इस में काम चल रहा है। सारे मेवात में के इलाके मे तीन आई टी आई है लेकिन इनमे मेवात के बच्चे भर्ती नहीं किये जाते बाहर के बच्चे लिये जाते है। मै सरकार से रिकवैस्ट करूंगा कि एडमी इन करते समय मेवात के बच्चो को भर्ती करने की अलग परसैटज फिकस की जाए। इसके इलावा मै हरियाणा में उर्दू पढाई जाने के लिए मांग करूंगा। सारे स्कूलों मे उर्दू पढाई जानी चाहिए। अगर सारे हरियाणा मे नहीं पढाई जा सकती है। तो कम से कम मेवात के एरिये में तो पढाई जाए। ताकि जो बच्चे भाोक रखते है वे इस मीठी जबान को पढ कर अपना भाोक पूरा कर सके। इन भाब्दों को साथ मै आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे टाईम दिया है।

मास्टर राम सिंह (रादौर): स्पीकर साहब, मै डिमांड नं. 9, 10, 23, 14 पर बोलना चाहता हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया है सबसे पहले में एजुके इन पर बोलूंगा। मेरे हल्के में 10-12 गांव ऐसे है। जहां पर प्राईमरी स्कूल भी नहीं है। रादौर में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है जहां

को-एजुके ान है । लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बच्चे पढते है । यहां पर अलग से एक गलर्ज स्कुल खोला जाए ताकि बच्चों की एडजस्टमेंट हो सके । वह को-एजुके ानल स्कुल हैं लडको का स्कुल अलाहिदा होना चाहिए । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस काम को अव य करे ।

स्वास्थ्य विभाग की डिमांड के बारे में मैं यह कहूंगा कि मेरे हल्के के अन्दर एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर है । उसकी बिल्डिंग पूरी है । उसको यदि अपग्रेड करके 30 बैड्स का बना दिया जाए तो उस इलाके को बहुत ज्यादा फायदा होगा । इसी तरह से बबैन के 12-13 मील के रेडियस के अन्दर चुकि कोई हस्पताल नहीं है । केवल एक रूरल डिसपैन्सरी है प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनाने की कृपा की जाये क्योंकि लोगों ने इसके लिए जमीन भी दी है ।

स्पीकर साहब, हमारा जिला कुरुक्षेत्र इंडस्ट्रीज में बहुत बैकवर्ड है जो थोड़ी इंडस्ट्रीज है उनको बिजली नहीं मिल पाती । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन इंडस्ट्रीज को बिजली दी जाये । स्पीकर साहब, रादौर हल्के के लिए एक इंडस्ट्रियल कंप्लैक्स मंजूर किया गया था । उसके लिए जमीन भी ऐक्वायर कर ली गई है । लेकिन चार पांच साल से वह ऐक्वायर की हुई जमीन खाली पडी हैं अभी तक सरकार ने इंडस्ट्रियल कंप्लैक्स चालू करने का कोई प्रावधान नहीं किया है मेरा सरकार से अनुरोध है कि रादौर के अन्दर जो बेकार जमीन पडी है उसका इस्तेमाल

किया जाय और इंडस्ट्रियल कप्लैक्स जल्दी से जल्दी चालू किया जायें ।

स्पीकर साहब, पिपली में कोई बस स्टैंड नहीं है। वहां पर चारों तरफ जैसे पेहावा कैथल जमुनानगर ओर करनाल आदि जगहों से सवारियों आती है। बारि 1 ओर धूप में लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर भागीघ्न बस स्टैंड बनाया जाए। इसी तरह रादौर के अन्दर भी प्रौपर बस स्टैंड नहीं है। वहां पर चारों तरफ से सड़के मिलती है। वैसे भी रादौर एक कस्बा है। इसीलिये वहां भी बस स्टैंड की सुविधा होनी चाहिए।

स्पीकर साहब, रादौर के अन्दर एक छोटी सी मंडी है। इसके आस पास ओर कई छोटी मंडियां है। लेकिन इनको पेमेंट लेने के लिए डीएफसी कुरुक्षेत्र के पास जाना पड़ता है। वहां पर कई वारदात ऐसे हुए है। कि रास्ते में कई लोगों के पैसे छीन लिए गये या जेब काट लिए गए। मेरी रिकवैस्ट है कि लोगों को पैमेंट मंडी में आकर ही की जाए। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हैफड द्वारा रादौर मंडी के अन्दर भी अनाज की खरीद की जानी चाहिए। क्योंकि यह मंडी काफी डाउन जा रही है। इन भाब्डों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हू।

Ch. Phool Chand (Mullhana): Sir, I will take only two minutes. I would like to speak just on few demands. First of all, I would

comment on Demand No. 9 Sir, that for every school in the villages after having some coordination with the P.W.D. B&R the Government should try to arrange approach roads. (Interruption) there is a great derth of teachers in the school. Not only this that the sanctioned staff is not posted there but we require certain more teachers in the schools so that people could give better education to the children. So, I would recomend that certain more staff should also be sanctioned.

Then I come on Demand NO. 10. In this connection, I would like to suggest that in Ambala and particularly in Mullana constitiency we require more hospitals in the villages because we do not have hospitals and the population of the constituency is more than 2 lacs. Even at Ambala the construction work of hospital building has not yet been started. So Iwould like to recommend and suggest that the work of hospital builidng should immediately be started. Now I want to take up Demand NO. 23. The is regarding Transport. One great difficulty which the boys of Haryana are facing while coming to Chandigarh is that their pass fares have been doubled for the last few days. I do not know why? I would request the Transport Department to look into the matter and relieve the boys of higher charges while coming to Chandigarh because we have certain types of colleges at Chandigarh which we do not have in Haryana. So, this facility should be given to the boys.

I would also like to say one thing regarding Social Welfare. There are hundreds and thousands applications for the grant of old age and widow pension in the Social Welfare Department. They are still pending. We do tell people that they should apply for pension. but the funds are not available. I would request that the weaker sections of society demand in this regard be met. So this amount should also be increased.

Now I come to Public Health. There are certain pockers in the hilly areas where we do not have the drinking water facilities, which is the basic necessity of the common masses. One of these villages is Nagli-Kochi. Speaker, Sir, if you kindly find some time and go there you will find that they take water from the same pond from where their animals take water .

Mr. Speaker: if you invite me, I will go there.

Ch. Phool Chand: you are cordially invited, Sir, So I would say that certain villages like Nagi Kochi and other hilly tracts (from Naraingarh to Tajewala) require this facility of water works as is provided in Naraingarh Tehsil and Kalka Tehsil. I would request that this area should be investigated and public health schemes should be sanctioned keeping in view all the circumstances stated by me.

Mr. Speaker: Please wind up.

Ch. Phool Chand: All right, Sir, I do not want much of the time unnecessarily. Thank you.

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): स्पीकर साहब, कुछ मैम्बर्ज साहेंबान ने गवर्नर ऐड्रैस बजट ओर डिमांड्ज पर बोलते हुए कहा कि हस्पतालो में दवाईयां नहीं हैं। यह बात ठीक नहीं है दवाईयों काफी मात्रा में दी जाती हैं। इस साल भी बजट में दवाईयों के लिए 125 लाख रूप्ये का प्रोविजन किया गया है। 25 लाख रूपया मलेरिया की रोकथाम के लिए केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत मिला है ओर 150 लाख रूप्ये बाढ पीडितों क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार से मदद मिली। हमने काफी दवाईयों हस्पतालों में दी हैं मै समझती हूँ कि सभी जगह काफी मात्रा में दवाईयां दी जाती है। हो सकता है। आबादी ज्यादा बढने से सैट परसैट दवाई न मिल पाती हो लेकिन बहुत हद तक दवाई देने की कोशिश की जाती है।

अध्यक्ष महादेय, भाई कुन्दन लाल जी ने सफीदों के हस्पताल की बात कही थी। मै उन्हे बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी वहां 30 बिस्तरों को हस्पताल बन जाएगा। केस एफ डी मे गया है ओर उम्मीद है कि इसी साल या अगले साल वह चालू हो जाएगा।

भाई लक्षमण सिंह जी ने कहा कि उनके एरिया में कोई हस्पताल नहीं है लेकिन मै उन्हे बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले गांव खुकनी में 10 बिस्तरों का हस्पताल दिया गया था। जहां तक इन्दरी के हस्पताल की बात है वह विचराधीन है सरकार ज्यादा से ज्यादा इस बात कोशिश करती है कि देहात

के अन्दर जितने अधिक से अधिक हस्पताल डिस्पैसरीज ओर सब सैन्टर्ज आदि खोले जा सके खोले जाये। (डा० मंगल सैन की तरफ से विघ्न) स्पीकर साहब, डा० मंगल सेन जी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने हलके मे कोई हस्पताल नहीं खोला। है। (विघ्न) मास्टर राम सिंह जी ने रादौर के हस्पताल को अपग्रेड करने ओर बबैन में प्राइमरी हेल्थ सैन्टर बनाने की बात की। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डा० मंगल सैन जी जिस बात का जवाब आप इनसे चाहते हैं उसके लिए मैंने ही इन्हे रोका है क्योंकि आज टाईम नहीं है। पर्सनल ऐक्सप्लेनं इन के लिए मैं कल इन्हे टाईम दूंगा।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसके अलावा स्पीकर साहब, जिन जिन माननीय सदस्यों ने हास्पिटल ओर डिस्पैसरिज के बारे में कहा है। उनकी बातों पर पूरी तरह से विचार किया जायेगा। वैसे तो सरकार की पहले से ही कोशिश है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा दवाईयां हास्पिटलज ओर डिस्पैसरीज मे पहुंचा सके पहुंचाने की कोशिश करते हैं ओर अधिक से अधिक हास्पिटलज ओर डिस्पैसरिज खोलने का प्रयत्न करते है। करनाल के हस्पताल के बारे में कहा गया। आज तक वहां पर जगह कमी की थी अब जगह मिल गई है। हम जल्दी ही नया हस्पताल बनाने वाले है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है। हम जल्दी ही नया हस्पताल बनाने वाले हैं मुख्य मंत्री जी ने कोशिश कर दिया है। जैसे

जैसे पैसे का प्रबन्ध होता जायेगा हास्पिटल बना दिया जायेगा।
स्पीकर साहब, मैं एक ओर बात कहना चाहूंगी कि विपक्षी भाई
कभी पी डब्ल्यूडी कभी हैल्थ ओर कभी एक्साइज टेक्स ट्रेन विभाग
के बारे में कहते हैं कि उसमें यह हो गया वह हो रहा है। असल
बात यह है कि सावन क अन्धे को हरा ही हरा दिखाई देता है

श्री किताब सिंह: बहिन जी कह रही हैं कि अपोजीसन
के लोग जैसे जी कह देते हैं लेकिन बात कुछ नहीं है मैं अपने
हल्के गोहाना के बारे में बताना चाहता हूँ। वहां पर न कोई
हस्पताल ही खोला गया है। और न ही पीएचसी खोला है।

श्री अध्यक्ष: जो श्री निहाल सिंह के बारे में कहा गया है
वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री मंगल सैन:.....।

श्रीमती प्रसन्नी देवी:।

श्री अध्यक्ष: वह रिकार्ड में कुछ नहीं आयेगा।

श्री मंगल सैन:।

श्री अध्यक्ष: जो कुछ डा10 मंगल सैन जी ने कहा है यह
रिकार्ड न किया जायें।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, जब इनकी तरफ से बातें कही जाती हैं। तो हमें कहनी पड़ती है। इनकी तरफ से भी नहीं आने चाहिए।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री बृज मोहन): स्पीकर साहब, एक्साइज एंड टैक्स ऐंड डिपार्टमेंट की सन् 1984-85 के लिए 40756425 की डिमांड है स्पीकर साहब, मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि हमारा रैवेन्यू पिछले साल 300 करोड़ का था और सन् 1984-85 में 330 करोड़ होने की सम्भावना है मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा की एस्टेबलिशमेंट का सबसे कम खर्चा है किसी भी स्टेट में हमारे से कम खर्चा नहीं है। एस्टेबलिशमेंट का खर्चा सवा परसैंट से कम बनता है। इस डिमांड पर मास्टर रिजर्व प्रसाद श्री ओम प्रकाश महाजन और राव निहाल सिंह जी बोले हैं। इस डिमांड में कोई खास बात नहीं है। यह डिमांड सेलरी मैडिकल ओर आफिस के खर्चों के बारे में है। इसमें कोई और खर्चा शामिल नहीं है श्री ओम प्रकाश जी ने टीवी ओर इलेक्ट्रिकल गुड्स पर टैक्स घटाने की बात की है। कि दूसरी स्टेट्स में टैक्स कम है। ओर हरियाणा में ज्यादा है। मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां भी ऐसी गुड्स हैं जो कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में टैक्स कम है। जहां सरकार यह समझती है कि टैक्स घटाने की आवश्यकता है वहां घटा भी देती है। पिछली दफा हमने ऐसा किया था।

श्री मंगल सैन: गवर्नमैट यह भी कह रही थी कि सेल्ज टैक्स माफ करना है।

श्री बृज मोहन: यह बात अलग हैं आप इस बारे में अलग से पूछें।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, जो 21 करोड के एरियर है इन के बारे में भी तो बता दे। (विधन)

श्री बृज मोहन: स्पीकर साहब, इस बारे में श्री ओम प्रकाश जी ओर दूसरे साथी मेरे पास आये तो बात कर लेगे मास्टर शिव प्रसाद जी ने चूडियों के व्यापार की बात का जिक्र किया। ये मेरे पास आए थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस मामले को हम एग्जामीन कर रहे हैं। अगर मुनासिब होगा तो खत्म कर देगे। एक दिक्कत ओर भी हैं चूडियों भी सोने की ओर प्लास्टिक की भी जमती है। (विधन)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस की सैस हो तो 20 मिनट के लिए हाउस का टाईम बढ़ा देते हैं।

आवाजे: बढ़ा दें जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1984-85 के बजट की डिमांड्स फार गॉट्स पर चर्चा तथा
मतदान (पुनरारम्भ)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं केवला इतना स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि अब कि बार जो भाराब के ठेके नीलाम हुए हैं उस नीलामी में सरकार को काफी आमदनी हुई है लेकिन मेरे विचार के अनुसार ओर भी अधिक हो सकती थी। भिवानी हिसार ओर रोहतक आदि कई जगहों पर ठेको की नीलामी हो गई। उस में पहले तो बोली दे दी गई लेकिन बाद में बोली सस्पैन्ड कर दी गई। इस प्रकार अनेक जगह हुआ है फिर दोबारा लोग इक्ट्ठें हुए। ओर बड़े बड़े ठेकेदारों को बुलाया गया ओर उनके नाम से ठेका छोड़ दिया गया। दूसरे जो लोग इन्टस्टिड थे उनको ठेका नहीं मिला।

श्री बृज मोहन: सै ।न में महज कोई बात कहने से हल नहीं हो जाती । मेरे नोटिस में आप पहले लाते तो हम उस हिसाब से चलते । मास्टर ि।व प्रसाद जी को बताना चाहूंगा कि चूडियों पर टैक्स के मामले को हम एग्जीमिन कर रहे हैं । वे मेरे से अलग से मिल ले जो भी मुनासिब होगा करेगे । अगर हम खत्म कर सके तो खत्म करेगे ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, राव साहब ने कुछ बातें कही । उन्होंने जनरल सी बातें कही । मैं उस वक्त हाउस में नहीं था । मैंने उन से हाउस के बाहर पूछा कि आपने हमारे डिपार्टमेंट

के बारे में क्या कहा है तो कहने लगे कि अपोजीसन में बैठते हैं कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ता है सरकार के खिलाफ कुछ तो बोलना ही है। इन्होंने जो टासफर्ज के बारे में बात कही कि पैसे लिए जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है और निराधार बात है। अगर इनके नोटिस में कोई बात हो तो यह हमारे नोटिस में लाये जो भी दोषी होगा हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इन भावों के साथ में अपना भुक्ति अदा करता हूँ।

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, मैंने भाराब के बारे में एक सवाल लिखकर दिया था कि जो मिलिटी वालों को थ्री एक्स रम सप्लाय करने के बारे में था। सरकार ने इस का जवाब यह लिख कर भेजा दिया है कि वे उस का जवाब नहीं दे सकती। उस का जवाब सरकार को देना चाहिए। (व्यवधान) यह मिलिटी वालों के साथ अन्याय की बात है। (व्यवधान)

वाक आउट

श्री अध्यक्ष: मनफूल सिंह जी मेरी बात सुनिये। डिफेंस की हर बात यहां पर नहीं बताई जा सकती। डिफेंस का जो रम जाती है। कितनी जाती है और कितने कन्सै इनल रेट पर जाती हैं। यह सारी बातें वहां डिस्कलोज नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूँ

(इस समय श्री मनफूल सिंह सदन ` वाक आउट कर गये ।)

वर्ष 1984.85 के बजट की डिमांडज फार गूट्स पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीस नेहरा): स्पीकर साहब, डिमांड नं. 9 के द्वारा 118 करोड 11 लाख 42 हजार 365 रूपये मांगे गए हैं यह मांग शिक्षा मंत्री के बारे में है ओर कई सदस्यों ने शिक्षा पर कई बातें कहीं। मैं माननीय सदस्यों की बातों का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कई माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी कांस्टीच्यूएसी के बारे में बातें कही ओर कई सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिये। श्री ओमप्रकाश महाजन ओर श्रीमती भारदा रानी जी ने स्कूलों में अध्यापकों की कमी होने के बारे में कहा। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम स्कूलों में अध्यापकों की कमी नहीं रहने देंगे। इसी तरह से राव निहाल सिंह जी ने बैकवर्ड एरियाज के बारे में बात कही कि उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह बात इनकी ठीक है। हम प्राइमरी शिक्षा के बारे में नारनौल जींद ओर सिरसा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी तरह से राव साहब ने एक एम एम एस सी जुआलोजी क्लासिज नारनौल में ही रहने देंगे। क्वैशन आवर के दौरान सप्लीमेंटरी भी किया था। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई विचाराधीन बात नहीं है। हां यह बात जरूर है कि वाईस चांसलर की तरफ से यह बात आई थी लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं लिया

गया है। मैं इन का विवास दिलाता हूँ कि यदि वहाँ पर लडके पूरे हो तो यह क्लास कतई नहीं हटाई जायेगीं इसी तरह से राव साहब ने एक ओर सुझाव दिया कि मैट्रिक सर्टीफिकेट में ही लडको की जाति आदि लिखी जानी चाहिए। यह सुझाव अच्छा है ताकि लडकों को बैकवर्ड ओर रिजर्व्ड कास्टस वगैरह का सर्टीफिकेट अलग न लेना पड़े। इस पर शिक्षा विभाग विचार करेगा ओर स्कूल शिक्षा बोर्ड से बातचीत करके जो भी हो सकेगा हम इस सुझाव को इम्पलीमेंट करने की कोशिश करेंगे। (व्यवधान) बोनार्फाईड रैजीडेंट भी उसमें आ जाता है। बैकवर्ड ओर रिजर्व्ड कास्टस भी उसमें आ जाते हैं।

श्रीमती चन्दावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। वजीर साहब बोल रहे हैं। मेरी एक बात का जवाब दे दे। कुछ स्कूलों ने बहुत दिनों से दरख्सात दे रखी हैं कि उनको सरकार द्वारा टेक अप कर लिया जाये। लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग बना दी है। ताकि सरकार उनको ले लें। इस विषय पर अगर कोई रोकनी दे तो अच्छा होगा क्योंकि गांवों के लोगों ने बिल्डिंग बना रखी है। ओर अब वे उनकी मरम्मत नहीं करवा सकते। अगर सरकार मुनासिब समझे ता उनको ले ले।

श्री जगदीश नेहरा: जैसा कि लीडर आफ दी अपोजीसन ने कहा अगर इस तरह का कोई स्कूल होगा तो हम उसको लेने के लिए तैयार हैं मैंने पहले भी कहा था कि गांव के लोगों में कम्युनिटी एजुकेशन के बारे में हमारी नीति यह है कि

लोग पहले स्कूल बना दे। इसके बाद हम वहां पर अध्यापक भेज देते हैं मैं माननीय लीडर आफ दी अपोजीसन से यह कहना चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसी बात उनके नोटिस में है तो यह हमारे नोटिस में लाये। हम फौरन उनको ले लेंगे। इसी तरह से कुन्दन लाल जी ने स्कूलों में अध्यापकों की कमी की बात कही है।

चौधरी बलबीर सिंह गेवाल: स्पीकर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने अभी वह बात कह दी कि आप हमें बताये हम फौरन उनको ले लेंगे। कई गांवों में स्कूल बने हुए हैं। लेकिन स्कूलों की बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं। बेसिकली वह बिल्डिंग गांव वालों ने बनायी थी। टेक ओवर करने के लिए लोगों ने कई कई महीनों से दरख्साते दे रखी हैं लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी की बुक्स में नहीं लिये गये हैं।

श्री जगदीश नेहरा: सर, पीडब्ल्यूडी बुक्स में टेक ओवर करना और स्कूल को टेक ओवर करना दोनों ही अलग बातें हैं। अध्यक्ष महादेय, गेवाल साहब को भी पता होगा कि जब गांव वाले कोई नया स्कूल बना देते हैं उसमें जब सरकार अध्यापक भेजती हैं तो वह उसी टाइम से लिया जाता है लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा टेक ओवर करने की जो फार्मलिटि है उसमें कुछ टाइम लगता है जो स्कूल उनकी स्पेसिफिकेशनज पूरी करता है उसको वे लेते जाते हैं। इसी तरह से मास्टर शिव प्रसाद जी ने भी कई बातें कहीं। एक बात उन्होंने यह कही कि बीईओ के अधीन ब्लाक सिस्टम ठीक नहीं होना चाहिए। उनकी यह बात ठीक

है। कि किसी ब्लाक में 40 स्कूल है। तो किसी ब्लाक में 80 स्कूल हैं इस वजह से सारे स्कूलों की अच्छी तरह से चैकिंग नहीं हो पाती है। मैं इनहें बताना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग इस बारे में विचार करेगा। इसी तरह से एसडीईओ के आफिस में टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया है। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि हमने यह मामला कमीसन के सामने भी रखा था। इनके कहने से पहले हमने यह सुझाव दे रखा था ताकि अगली सिक्सथ फाईव ईयर प्लान में यह सुविधा प्रदान की जा सके। अगर प्लानिंग कमीसन हमें 66 लाख रूपया दे देगा तो हम यह सुविधा उनको प्रदान कर देंगे। यह बात आलरेडी हमारे ध्यान में है क्योंकि हमें पता है कि एसडीईओ के पास काम बहुत होता है। इसीलिए यह सुविधा होनी लाजमी है। कई बार इसकी कमी की वजह से बड़ी मुश्किल पड़ जाती है यह सुझाव हैल्दी है। हमें इस पर आलरेडी गौर कर रहे हैं। इसी तरह से मास्टर प्रिन्सिपल जी ने अध्यापकों की हाजिरी के बारे में कहा। मैं अपने माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि कभी कभी वे खुद ही अपनी कांस्टीच्यूएसी में चैकिंग किया करें। जहां कहीं हमारे नोटिस में कोई ऐसी बात आती है हम एक्सन लेंगे। हमारे माननीय सदस्य हमारे नोटिस में कोई ऐसी बात लायेंगे या लिखकर भेजेंगे तो हम एक्सन लेंगे हम चाहते हैं कि स्कूलों में हाजिरी पूरी हो। इस बनावट पर हमने सैकड़ों स्कूलों को चैक किया है। अब पहले की अपेक्षा हाजिरी स्कूलों में ठीक होगी। (व्यवधान) हां मैं माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि वे जो लिखकर भेजेंगे सरकार उनके उपर एक्सन

लेगी। एक बात इन्होंने प्राईमरी एजुकेशन के लिए अलग से डायरेक्टोरेट बनाने के बारे में कह दी ।

श्रीमती बसन्ती देवी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मुझे इन डिमांडज पर बोलने का मौका तो नहीं मिला है लेकिन मैं एजुकेशन मिनिस्टर महोदय से एक बात पुछना चाहती हू पहले पहली ओर दूसरी क्लासिज में टैस्ट स्टुडेंट्स को अगले क्लास में किया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिना टैस्ट लिये ही उनको अगली क्लास में चढा दिया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि इन क्लासिज मे भी टैस्ट होना चाहिए?

मास्टर िव प्र ाद: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैंने यह भी कहा था कि डीपीआई लेवल तक प्रोमी इन एजुके इन डिपार्टमेंट मे से ही होनी चाहिएं ।

श्री राम बिलास भार्मा: मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय ने यह कहा है कि एम एल एज लिखकर भेज दे। अगर कोई अध्यापक स्कूल में न मिले और हम आपकी सेवा मे इस फ़ैक्ट को लिखकर कर भेजते है। तो क्या आप कार्यवाही करेगे।

श्री जगदी ा नेहरा: हां, की जायेगी। यदि कोई विधायक जिम्मेदरारी के साथ लिखेगा तो जरूर कार्यवाही होगी। जो भी आप लिखकर भेजेंगे उस पर जरूर कार्यवाही होगी मास्टर िव प्रसाद जी ने एक बात कही है कि िक्षा विभाग से ही

डीपीआई बनना चाहिए। उनका यह सुझाव बहुत है। हम इसको एग्जामिन करवा लेगे। वैसे यह बात सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एग्जामिन करवायेगी। कि इस का ही आदमी डीपीआई होना चाहिए। इसी तरह बहिन बसन्ती देवी जी ने कहा है। कि पहली ओर दूसरी जमात के बच्चों को बिना टैस्ट लिये प्रमोट कर दिया गया था। स्कूलों में नो डिटेनान का सिस्टम दर असल कई साल पहले लागू किया गया था। उस समय बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ जाते थे। टैस्ट सिस्टम फिर से लागू करने की बात विचाराधीन तो नहीं है। लेकिन फिर भी इस प्वायंट को एग्जामिन करवा लेगे।

श्री भाकुन्तला ने मेवात के एरिया में बाहर के अध्यापक लगाने के बारे में कहा। यह बात दुरुस्त है। वहां अध्यापक नहीं मिलते। उर्दू के जेबीटी 58 हैं जो जेबीटी इस्टीच्यू इन वहां खुले हुए हैं। उन में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको वहीं लगाया जाएगा। उर्दू पढ़ाने का प्रावधान शिक्षा विभाग में है। जहां प्राइमरी स्कूल नहीं है। अगर वहां तीस चालीस बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होंगे तो शिक्षा विभाग वहां ब्रांच प्राइमरी स्कूल खोलेगा। मास्टर राम सिंह ने कहा कि रादौर में अलविदा स्कूल होना चाहिए। मैं इन्हें बताना चाहता हू कि इसके बारे में हम देखेंगे। फुल चन्द जी ने एक सुझाव दिया था कि स्कूल तक ऐप्रोच रोडज होने चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि हर स्कूल को ऐप्रोच रीड दी जायेगी। इसी तरह अम्बाला में गवर्नमेंट कालिज होना चाहिए। जब ठीक है कि अम्बाला में गवर्नमेंट कालिज नहीं है वहां पर

गवर्नमैट कालिज होना चाहिये। जब भी फण्डज का प्रोवीजन होगा, हम को ि ि करेगे कि वहां कालिज खोला जाये। फूल चन्द जी ने एक बात ओर कही कि अध्यापक ओर होने चाहिये। हमारी को ि ि है कि अधिक से अधिक अध्यापक लगाए जायं ताकि अध्यापकों की कमी न जाये। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ि िक्षा के मामले मे सब सदस्य ि िक्षा विभाग को अपना अपना सहयोग दे। मै विरोधी पक्षो क भाईयों से प्रार्थना करूंगा कि जब भी गांव मे जाये तो गांव के लोगों से उनके बच्चे की पढाई के बारे में पुछताछ जरूर करे। भाहरों मे जो बच्चे पढ रहे हैं उनके मां बाप बच्चे से भाम के बारे में पढाई मे पुछते हैं कि उनहें आज क्या पढाया है। आज वह स्कूल गया या नही। कुछ पढता है या नही पढता है। अगर गांव मे एकसा हो जाए तो उनके बच्चे पर काफी अच्छा प्रभाव पडेगा। इस साल पांच से ग्यारह साल की उम्र से बच्चे 89 प्रति ित आए है। ि िक्षा विभाग ने नैतिक ि िक्षा भी लागू की है। इस बार प्लान साइड मे ज्यादा रूपया रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मै आपकी मारफत सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि डिमान्ड नम्बर 9 जो 118 करोड 11 लाख 42 हजार 365 रूपए की है। इसको पास किया जाये।

श्री किताब सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मंत्री जी बार बार विपेक्ष को आ वासन देते है। कि किसी के साथ भेदभाव नही बरता जायेगा। स्पीकर साहब, गोहाना के साथ सौतेली मां का सलूक किया जा रहा है। वहा पर 1.7.79 से 25.12.

82 तक कालिज ओर स्कूल की बिल्डिंग पर सिर्फ ग्यारह हजार रूपया खर्च किया है। जबकि आदमपुर में 65 लाख 13 हजार खर्च हुआ है।

वित्त मंत्री (चोधरी कटार सिंह छोकर): स्पीकर साहब, डिमान्डज पर चर्चा हो रही है। ओर काफी बातों का जवाब मेरे साथियों ने दिया है। जो कुछ बाकी रह गया है। वह मैं बता सकता हूँ। भारदा जी ने आगमेंटे इन ट्यूबवैल्ज के बारे में कहा कि उनसे पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। इस बारे में आईपीएम साहब ने असैम्बली में बताया है कि यह पुरानी स्कीम है और आगे से कोई ऐसी स्कीम चालू नहीं की जायेगी। कि जिसके कारण पानी का लेवल नीचे चला जायेगा। जहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी उसको देखा जा सकता है। ओर प्रबन्ध किया जा सकता है उन्होंने दस बारह गांवों का जिक्र किया कि वे जमुना के घेरे में है। और बरसात में काफी नुकसान होता है। उनकी प्रोटेक इन के लिए बांध नहीं बनाए गए है। ओर उन गांवों में सडक नहीं गई हे। यह सारा मामला कल की डिमान्डज में डिस्कस हो चुका है। यह मामला नोट कर लिया है। अगर वाकई तकलीफ है तो इसको दूर किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बल्लभगढ में एक जगह पर टुरिस्ट काम्पलैक्स बनाने के लिए कहा है। इसके अलावा इन्होंने बल्लभगढ और फरीदाबाद में कोई फर्क नहीं है। फरीदाबाद में पहले ही टुरिस्ट काम्पलैक्स बने हुए है। जहाँ काफी लोग रहते है। कुन्दन लाल जी न कहा कि उनका क्षेत्र इंडस्ट्रली

बेकवर्ड है इस लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाए। स्पीकर साहब, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो हमारे पास साधन उपलब्ध है। उनके मुताबिक प्रबन्ध किया जाता है। फिर भी इस बात पर गौर कर लिया जाएगा। फलडज के बारे में जो मैयर्ज सरकार ने लिए है व हाउस में बार बार बता दिए गए हैं। रोडज के बारे में भी परसों कहा था कि इनका इन्तजाम किया जा रहा है। जहां तक करनाल में मिनि सैक्रेटेरिट बनाने का सवाल है। उसका फाउन्डे इन स्टोन मुख्य मंत्री जी ने रखा है। उसको बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए पैसा पिछले साल प्रोवाइड किया गया था। इसके नक्शे बनने थे। आरै आर्किटेक्चर ने नक्शे तैयार नहीं किए थे। इस लिए यह काम चालू नहीं हो सका। रोड इन लाल जी ने किसानों से फोर्सिबल रिकवरी की बात कही। अगर इनके पास कोई स्पेसिफिक बात हैं तो ये बताएं। इनहोंने कहा कि वे गिरफ्तार हुए थे। पता नहीं ये हुए भी थे या नहीं। लेकिन अगर कोई खास केस इनके नोटिस में हो तो वे बताएं। इन्होंने प्रेस रिपोर्टर की बात कही कि अम्बाला की पुलिस उसको हैरास कर रही है। स्पीकर साहब, प्रेस रिपोर्टर खुद हमारे पास आ सकता है। ओर अपनी बात कह सकता है। यह अजीब बात है कि वह एमएलए के थ्रू अपनी बात कहना चाहता है। अगर सरकार के नोटिस में कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर ऐक इन लिया जाएगा। उन्होंने एक बात यह कही की कि उनके हल्के की सडक ओर ब्रिज एसडीओ के कागजों में बने हुए हैं। लेकिन मौके पर कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं हो सकती कि सडके और ब्रिज

कागजों पर ही हो। सडको ओर ब्रिजों का नाम ये बतायेगें तो गौर किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल औफिस यमुना नगर में स्थापित किया जाए इस बात पर विचार किया जा सकता है। इनकी यह बात उचित भी मालूम देती है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: आप कितना टाईम ओर लेगे?

चौधरी कटार सिंह छोकर: बस थोडा ही टाईम लूंगा।

श्री अध्यक्ष: हाउस का टाईम पांच मिनट ओर बढ़ाया जा सकता है।

वर्ष 1984-85 के बजट की डिमान्डज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी कटार सिंह छोकर: फोरैस्ट की बंगालिक की बात कही गई। बात तो कोई भी आदमी कह सकता है। बंगालिक के बारे में कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही जाये। बस स्टैड की डिमान्ड की गई है। कि रूरल एरियाज में बसस्टैड बनाये जाये। स्पीकर साहब, बस स्टैण्ड की जहां जरूरत है वहां बनाए जाते हैं। भाकरूलला जी ने कहा कि मेवात का एरिया बैकवर्ड एरिया है। वहां पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलना चाहिए। सरकार रिसोर्सिज को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती है। फिरोजपुर झिरका में बस स्टैण्ड की मांग की गई है। यह उनकी मांग उचित है।

इन्होंने कहा कि पुलिस स्टे इन की बिल्डिंग बहुत पुरानी है। यह भी उनकी बात उचित है। इन दोनों मांगों पर गौर किया जाएगा। एक बात इन्होंने ओर कही कि वहां जो आई टी आई है उनमें वहां के लडको को दाखिला कम मिलता है। बाहर के लडको को ज्यादा दाखिला मिलता है। इस लिए वहां के लडको के लिए रिजर्व इन होनी चाहिए। स्पीकर साहब, जहां तक मुझे याद है कि मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड में पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि एडमी इन में वहां के लडकों को प्रैफरेंस दी जाये। यह निर्णय इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जब भी मैं गुडगांव जाता हूं मैंने वहां देखा है कि यह निर्णय इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओर वहां के लडकों को प्रैफरेंस दिया जाता है।

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रैफैस मेवात के एरिया में किस हिसाब से दिया जाता है। रिलीजन के आधार पर दिया जाता है या बैकवर्ड के आधार पर दिया जाता है।

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, एक पर्टीकुलर एरिया को या रीजन को बैकवर्डनेस के आधार पर प्रैफैस दी जाती है। इसी प्रकार से श्री राम सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं। कि उनका एरिया बैकवर्ड है। जहां पर इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जानी चाहिए। जितनी बिजली हमारे पास अवेलेबल होगी उस के हिसाब से हम को Γ Γ करेंगे ओर करते भी हैं। कि इंडस्ट्री ओर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा बिजली दी जाये। यह

सारी बात बिजली की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करती है दूसरी बात उन्होंने यह कही मेरे हलके रादौर में जमीन एक्वायर कर रखी है। कि वहां पर इंडस्टीज के लिए इंडस्टियल कम्प्लेक्स बनाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ पिपली मे बस स्टेण्ड की बात भी कही गयी है। इन दोनो बातो पर विचार कर लिया जाएगा। हैण्ड का एक परचेजिंग सैन्टर रादौर मे बनाने की मांग उन्होंने कही है मेरे विचार में यह प्रबन्ध हो गया है। जैसे कि कोआपरे टन मिनिस्टर बता रहे थे यह समस्या तो उनकी है दूर हो जायेगी। इसी तरह से चौधरी फूल चन्द जी ने एक बात कही कि सो टाल वेलफेयर विभाग ओल्ड ऐजपेन् टान्ज लोगों को देता है। लेकिन लोगों को काफी एरियर्ज रूका पडा है। मै इनको बताना चाहता हूं कि विभाग के पास बहुत ज्यादा पैसा है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। यह एरियर दे दिया जाएगा। इसके इलावा यह विभाग ओर भी कई प्रकार की ऐक्टिविटीज चलाता रहता हे। हरिजन बच्चों को स्कालरशि प वगैरह भी यही विभाग देता है। इसके लिये हमें सैण्ट्रल गवर्नमैट को भी पैसा मिलता है। ओर स्टेट भी काफी योगदान करती है। इसलिये पैसे की किसी भी प्रकार की कोई कमी नही है। काम अव य बढ गया है। लेकिन पैसे की इस विभाग के पास कोई कमी नही है। इसके साथ साथ हिल्ली ऐरियाज के बारे में एक खास बात कही गयी है कि नारायणगढ ओर ताजें वाला के बीच में एक बैलट बनायी जाये ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। यह इनकी मांग उचित है। इसको देख लिया जाएगा। जो एरियर्ज की बात यहां पर कही गयी हैं उसके बारे में

यह कहना चाहता हू कि आडिट होने के बाद एतराज हो है । उस प्रोसीजर का तो स्पीकर साहब, आपको भी पता है सारा मामला पीएसी के पास जाता है उस की सिकूटनी होती है। इसके बाद डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है। तब जाकर इररेगुलेरीटीज मीट की जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर बात प्रोसीजर के हिसाब से होती है। इन लफ्जों के साथ स्पीकर साहब, मैं यह रिकवैस्ट करूंगा कि इन डिमांडज को पास किया जाये।

चौधरी फुल चन्द: स्पीकर साहब, हरियाणा से चण्डीगड को जो छात्र पढने के लिए जाते है। उनकी बसिज के पासों का किराया दुगुना कर दिया गया है। सरकार इस तरफ भी ध्यान दे ओर इसको ठीक करे।

चौधरी भारदा रानी: स्पीकर साहब, बल्लभगढ मे सस्ता पर्यटन केन्द्र खोलने के लिये हालांकि मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे साथ वायदा किया था। लेकिन मंत्री महोदय यह कह रहे है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है।

चौधरी कटार सिंह छोकर: स्पीकर साहब, मैं इस बारे में पहले ही कह चुका हूं कि फरीदाबाद मे इस तरह का एक पर्यटन केन्द्र पहले से ही मौजूद है। जो बल्लभगढ के काफी नजदीक पडता है। इसलिये बल्लभगढ मे ऐसी कोई आव यकता महसूस नही की जा रही है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय पांच मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाये।

आवाजे: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय पांच मिनट के लिये ओर बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1984.85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा
मतदान (पुनरारम्भ)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी बहन जी ने फरमाया कि उन्हें मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात का आवासन दिया है कि बल्लभगढ में टुरिस्ट कम्पलैक्स बना देगे। लेकिन मंत्री महोदय फरमा रहे है कि फरीदाबाद मे हमने आलरेडी टुरिस्ट कम्पलैक्स बना रखा है जोकि बल्लभगढ के नजदीक ही पडता है इसीलिये इस तरह का ऐसा कोई विचार सरकार का अभी नही है। आप ही बताएं कि कौन सी बात को सही माना जायें?

चौधरी कटार सिंह: स्पीकर साहब, मैने इनकार नही किया। मै ने यह बात कहा कि बल्लभगढ के नजदीक फरीदाबाद मे हमने कम्पलैक्स बना दिया है। जोकि बल्लभगढ के नजदीक ही पडता है ओर इस से काफी सहूलियत है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, एक्सार्ज एण्ड टैक् इन डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ 21 करोड़ के एरियर्ज

बकाया है और बजट में इनहोंने 47 करोड़ रुपये के करीब घाटा दिखाया है। अगर यह एरियरज वसूल हो जायें तो सरकार को काफी फायदा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: कुलबीर सिंज जी, जो सरकार की पालिसी है वह उन्होंने बता दी है।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री बृजमोहन): स्पीकर साहब, ये मेरे दफतर में आ जाये मैं इनको बता दूंगा।

श्री किताब सिंह: स्पीकर साहब, मेरी भी एक सबमिशन हैं। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं मेरा प्वायंट आफ आर्डर है किताब सिंह जी अब पहले बोलने के लिये खड़े हुए थे। उस वक्त आपने कहा था कि भाई तुम बजट के वक्त जब डिमांडज पर डिस्कसन हो तब बोल लेना। उनका काल अटैन्शन में था उस पर ये अपने विचार रखना चाहते थे। ये आपका ध्यान केवल इस ओर दिलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगर आप ने अपनी लिस्ट में डिप्टी स्पीकर साहब को इनका नाम दिया होता तो वे उस वक्त इनको बुलवा देते। दूसरी बात यह है कि जब मैं बैठा तब भी आप मेरे पास इनका नाम भिजवा देते तो भी मैं इनको टाईम दे देता।

श्रीमती चन्दावती:

इनका नाम लिस्ट में था जी। स्पीकर साहब, कल सब से पहले आप इनको बोलने का समय दे दे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है जी।

साहेबान अब मैं बेरीअस डिमांडज को वोटिंग के लिये पुट करता हूँ। अगर हाउस सहमत हो सारी डिमांडज को एक साथ ही ले लिया जाये।

आवाजे: ठीक है जी।

Mr. Speaker: Question is:-

That a sum not exceeding Rs. 115146430 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.2 General Adminstration**

That a sum not exceeding Rs. 115146430 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.2 General Adminstration**

That a sum not exceeding Rs. 385060795 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No3 Home.**

That a sum not exceeding Rs. 1181142365 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.9 Education**

That a sum not exceeding Rs. 886982850 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.10 Medical and Public health.**

That a sum not exceeding Rs. 77393280 for revenue expenditure and Rs. 31605600 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.16 Industries.**

That a sum not exceeding Rs. 156957765 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.20 Forest.**

That a sum not exceeding Rs. 782743200 for revenue expenditure and Rs. 123200000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.23 Transport**

That a sum not exceeding Rs. 7200290 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.1 Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. 40856425 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.5 Excise and Taxation.**

That a sum not exceeding Rs. 179519080 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.6 Finance.**

That a sum not exceeding Rs. 201159425 for revenue expenditure Rs. 2900000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.7 Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. 27840620 for revenue expenditure and Rs. 2700000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.11 Urban Development.**

That a sum not exceeding Rs. 67303915 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.12 Labour and Employment.**

That a sum not exceeding Rs. 156418215 for revenue expenditure and Rs. 10843000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of

charges under **Demand No.13 Social Welfare and Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. 20552440 for revenue expenditure and Rs. 1352452440 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.14 Food and Supplies.**

That a sum not exceeding Rs. 22445380 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.19 Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. 9392175 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No. 24 Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 1225063500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under **Demand No.25 Loans and Advances by State Government.**

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिये एडजर्न किया जाता है।

13.58 बजे

(तत्प चात् सदन वीरवार दिनांक 29-9-1984 को
प्रातः 9.30 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।